सारांश

ई एफ ए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2007

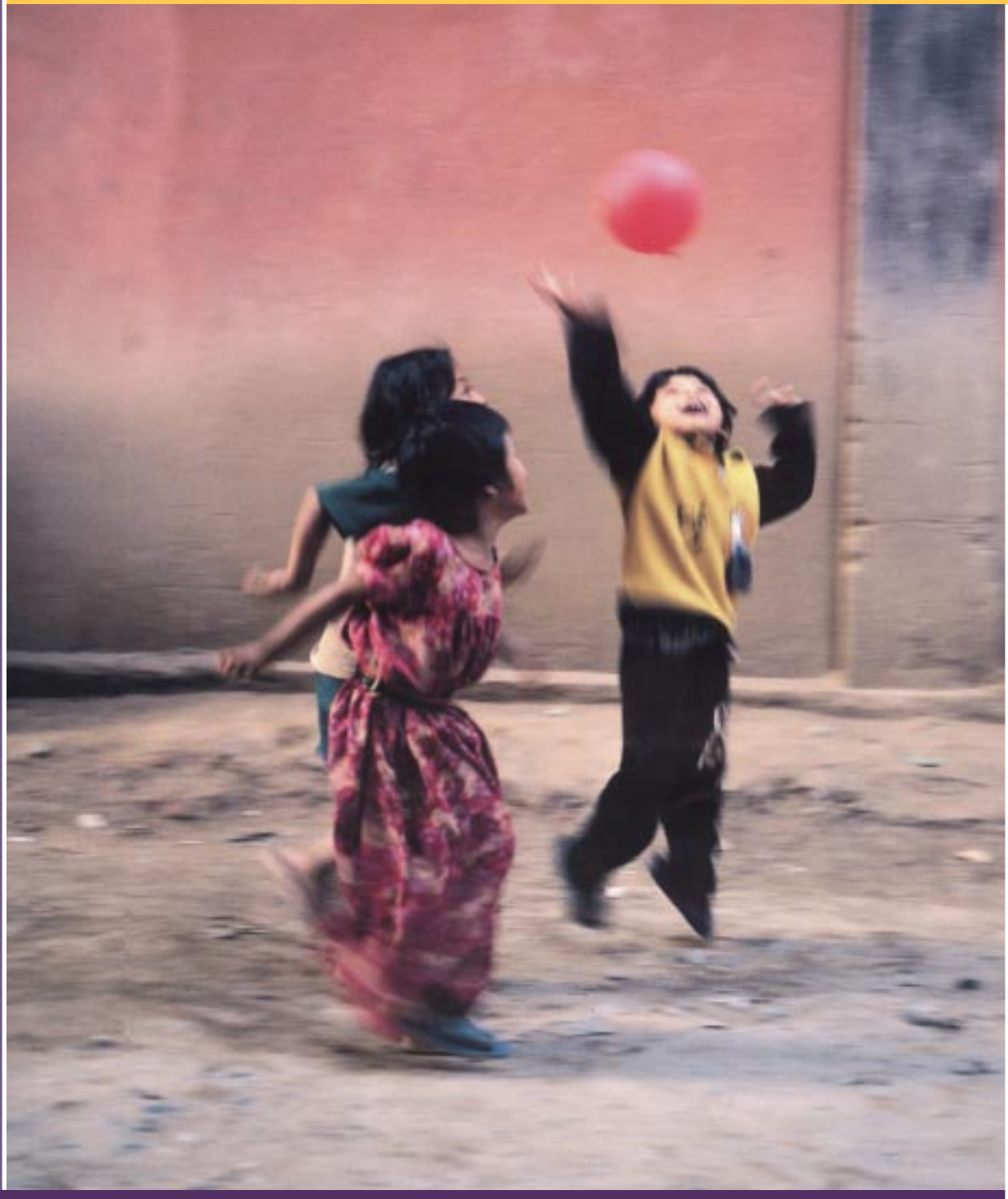

सुदृढ़ आधार

शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा

सुदृढ़ आधार

शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा

सारांश

यूनेस्को प्रकाशन

इस रिपोर्ट में दिए गए विश्लेषणों, नीति एवं संस्तुतियों के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि उनसे यूनेस्को (UNESCO) के दृष्टिकोण झलकते हों। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहल पर यूनेस्को द्वारा प्राधिकृत एक स्वतंत्र प्रकाशन है। यह रिपोर्ट सरकारों, संस्थाओं, एजेंसियों, रिपोर्ट टीम के सदस्यों तथा अन्य बहुत से लोगों के सामूहिक प्रयास का एक परिणाम है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों एवं रायों की जिम्मेदारी इसके निदेशक द्वारा वहन की गई है।

इस प्रकाशन में नियुक्त पदनाम तथा सामग्री के प्रस्तुतीकरण में व्यक्त किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति यूनेस्को पर उपलक्षित नहीं हैं फिर चाहे वह किसी देश, प्रदेश, शहर या क्षेत्र अथवा उसके अधिकारियों या सम्बद्ध क्षेत्र की सीमा या अग्रिम मोर्चे के परिसीमन का मामला हो अथवा कानूनी/वैधानिक सम्बद्धता का हो।

ई एफ ए विश्व निगरानी रिपोर्ट टीम

निदेशक
निकोलस बुरनेट

निकोल बेला, आरोन बेनावोट, फ़दीला कैलॉड, विटोरिया कैविक्चियोनी, अलीसन क्लेसन,
बेलरि डीजीओज, एना फोंट-गिनेर, कैथेराइन गिनिस्टी, सिथिंया गुटमैन, एलिजाबेथ हीन, कीथ हिंचलाइफ,
फ्रैंकोइस लैक्लेरक, डेलफिन एनसेन्गीमाना, बैनडे एनजोमिनी, उलरिका पेपलर बैरी, पौला राजकिन, इसाबेल रेवुलोन,
यूसूफ सईद, एलीसन कैनेडी (यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिसटिक्स),
माइकल जे न्यूमैन (अली चारल्ड हुड केयर एवं शिक्षा के विशेष सलाहकार)

रिपोर्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:-
निदेशक
ई एफ ए ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट टीम
c/o यूनेस्को
7, प्लेस डि फोनटेनोय, 75352, पेरिस 07 एस पी, फ्रांस
ई मेल efareport@unesco.org
फोन : +33 1 45 68 21 28
फेक्स : +33 1 45 68 56 27
बेवसाइट : www.efareport.unesco.org

ED-2006/WS/67

पूर्व प्रकाशित ई एफ ए ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट्स
2006-जीवन के लिए साक्षरता
2005-सबके लिए शिक्षा- गुणवत्ता अवश्यकरणीय
2003/4-जेंडर एवं सबके लिए शिक्षा-समानता की ओर कदम
2002-सबके लिए शिक्षा-क्या विश्व सही राह पर है?

2006 में, यूनाइटेड नेशन्स एजूकेशनल द्वारा प्रकाशित
साइंटिफिक एवं सांस्कृतिक संगठन
07, प्लेड डि फोनटेनोय, 75352, पेरिस 07 एस पी, फ्रांस
ग्राफिक डिजायन- सिलवाइन बाइयेन्स
आइकोनोग्राफ (चित्रकार) - डेलफाइन गैलार्ड
मुद्रण-ग्राफोप्रिंट, पेरिस
द्वितीय मुद्रण

© यूनेस्को-2006
फ्रांस में मुद्रित

ई एफ ए रिपोर्ट–2007 की विशिष्टताएं

2000 में तय, ई एफ ए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय हाथ से निकल रहा है। प्राथमिक स्तर पर कुल मिलाकर लड़कियों सहित वैश्विक प्रगति, जारी रहने के बावजूद, बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल में नहीं हैं या जल्दी ही पढ़ाई छोड़ देते हैं अथवा न्यूनतम अधिगम शिक्षा स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। शैशवकालीन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा और वयस्क या प्रौढ़ साक्षरता की कड़ी को उपेक्षित करने के द्वारा सभी देश प्राथमिक शिक्षा से लेकर बोर्ड के आर–पार तक और प्रक्रम में, बच्चों के भविष्य, तथा युवाओं व वयस्कों हेतु हर कहीं प्रगति के सुअवसर खो रहे हैं।

लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

प्राथमिक शिक्षा निरंतर विस्तार की ओर

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1999 तथा 2004 के बीच सार्वजनिक प्राथामिक शिक्षा के तीन में से दो क्षेत्रों में अत्यधिक तीव्र गति से नामांकन में वृद्धि हुई है–उप सहारान अफ्रीकी देशों में 27% और दक्षिण तथा पश्चिम एशिया में 19% की वृद्धि हुई है जबकि अरब राष्ट्रों में यह वृद्धि केवल 6% रही है। विश्व का कुल नामांकन अनुपात 86% पर ठहरता है। यद्यपि ग्रेड–1 में नामांकन में तेज वृद्धि हुई है, तथापि बहुत सारे जिन बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया था, वे प्राथमिक श्रेणी के अंतिम ग्रेड तक अभी भी नहीं पहुँच पाते हैं। आँकड़े बताते हैं कि आधे लातीन–अमेरिकी देशों में 83% से कुछ कम तथा कुछ कैरेबीआई देशों में एवं आधे उप सहारा अफीक्री देशों में दो–तिहाई से भी कम बच्चे स्कूल पहुँच पाते हैं।

स्कूल से बाहर बच्चेः वे कितने हैं और कौन हैं?

प्राथमिक स्कूली आयु वाले उन बच्चों की संख्या घटाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो स्कूल में नामांकित नहीं होते हैं। वर्ष 1999 एवं 2004 के बीच यह संख्या 77 मिलियन से घटकर 21 मिलियन रह गई। फिर भी न चाहते हुए भी यह संख्या बहुत अधिक है। ऐसे बच्चों में से तीन–चौथाई से अधिक बच्चे उपसहारा अफ्रीकी तथा दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में रहते हैं, हालांकि दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया क्षेत्र में 1999 से 2004 के बीच यह संख्या आधी रह गई है, इसका मुख्य कारण भारत में आई कमी है। वैश्विक अनुमान के अनुसार, यद्यपि यह संख्या अभी बहुत अधिक है, तथापि समस्या को समझना भी है। परिवार सर्वेक्षणों के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में नामांकित होने के बावजूद नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं।

ऐसे बच्चे बहुधा स्कूल से बाहर होते हैं और स्कूल न जा पाने वाले या अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों या गरीब परिवारों के होते हैं। एक औसत के अनुसार जिन बच्चों की माताएं अशिक्षित होती हैं; ऐसे बच्चे दो गुना स्कूल से बाहर होते हैं, अपेक्षाकृत उन बच्चों के, जिनकी माँएं थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं।

बहिष्करण से निपटने हेतु सरकारी नीतियाँ

सरकारों को तुरंत ही यह पहचानने की आवश्यकता है कि अधूरी पढ़ाई छोड़ने वालों के साथ–साथ जिन बच्चों का स्कूल में कभी नामांकन नहीं हुआ उन्हें पहचाना जाए। यह उन नीतियों को क्रियान्वित करने की दिशा में पहला कदम है जिससे कि बहिष्कृतों के पास पहुँच बने और शिक्षा की औचित्यता (उपयुक्तता) तथा गुणवत्ता एवं लचीलेपन में सुधार हो सके।

प्रोत्साहित समावेश के उपायों के साथ : स्कूली फीस की समाप्ति, ग्रामीण एवं गरीब परिवारों को आय का समर्थन उपलब्ध कराना; ताकि बाल श्रम पर उनकी निर्भरता घट सके, बच्चों को मातृ–भाषा में शिक्षित करना, विकलांगता तथा एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान करना तथा युवाओं एवं वयस्कों को दोबारा शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुनिश्चित करना आदि हैं।

शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा कार्य स्थितियों को बेहतर बनाना

ई एफ ए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त सुयोग्य एवं प्रेरित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। उप सहारा अफ्रीकी देशों को वर्ष 2015 तक 1.6 मिलियन नये शिक्षकों की आवश्यकता है। अफ्रीकी देशों में तथा दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया में स्कूलों में कन्या छात्रों को आकृष्ट करने के लिए तथा उन्हें शिक्षा में लगाए रखने के लिए बहुत कम महिला शिक्षिकाएं हैं। बहुत सारे विकासशील देशों में शिक्षकों की अनुपस्थिति भी एक गंभीर समस्या है।

अधिक कामकाजी – व्यवहार एवं व्यावसायिक विकास के साथ संक्षिप्त सेवा पूर्व प्रशिक्षण तथा दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लाभ एवं प्रोत्साहन आदि, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में काम करने वालों शिक्षकों को भर्ती करने तथा रोके रखने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ हैं।

माध्यमिक शिक्षाः बढ़ती माँग और पर्याप्त जगहों की कमी

माध्यमिक/द्वितीयक शिक्षा के विस्तार का दबाव नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। सभी विकासशील देशों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका (30%), दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया (51%) तथा अरब देशों में (66%) अभी भी निम्न है।

माध्यमिक शिक्षा में स्कूलों की निम्न संख्या, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि को धीमा करती है; क्योंकि ये परिपूर्ण प्राथमिक शिक्षा के प्रयास को कम करते हैं। ठीक उसी समय पर; माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती माँग के परिणामस्वरूप सरकारी खर्चों के लिए अन्य स्तरों पर प्रतिस्पर्धा होती है।

लैंगिक समानता : अभी भी वास्तविकता नहीं

अभी यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक 100 लड़कों की तुलना में 94 लड़कियाँ हैं जो 1999 की तुलना में 92 से थोड़ा अधिक हैं। वर्ष 2004 में उपलब्ध 181 देशों के आँकड़ों में से लगभग दो तिहाई देशों ने लैंगिक समानता की उपलब्धि प्राप्त की है। प्राथमिक शिक्षा लैंगिक अंतराल का समापन लड़कों के पक्ष में 26 में से केवल चार देशों में समाप्त हुआ है जोकि वर्ष 2000 में सकल नामांकन अनुपात 90% से नीचे था।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 177 देशों में से केवल एक तिहाई देशों ने माध्यमिक शिक्षा में समानता प्राप्त की है। इस स्तर पर अक्सर असमानता का पहलू लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पक्ष में होता है। तृतीयक स्तर पर लैंगिक असमानता, 2004 के आँकड़ों के अनुसार, 148 देशों में से केवल 5 देशों में विद्यमान है। लैंगिक समानता भी सदैव एक मुद्दा रहा है। जो अधिगम सामग्री में रुढ़िबद्ध तरीके से समाहित होता है और अक्सर ही शिक्षकों की अपेक्षाएं भी लड़कियों एवं लड़कों से भिन्न होती हैं।

साक्षरता : एक दुर्ग्राह्य लक्ष्य

लगभग 781 मिलियन वयस्क (दुनिया भर में हर पाँचवा व्यक्ति) न्यूनतम साक्षरता कौशल से रहित है। इनमें से दो तिहाई औरतें हैं। अभी भी दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (59%), उप सहारा अफ्रीकी (61%), अरब राष्ट्रों (66%) तथा कैरेबीयन देशों में (70%) साक्षरता दर निम्न है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार एवं सघन प्रयास के बिना, वर्ष 2015 तक वैश्विक निरक्षर लोगों की संख्या में केवल 100 मिलियन की कमी ही हो पाएगी। सभी सरकारों को निश्चितरूप से साक्षर वातावरण बनाने में ध्यान केंद्रित करना होगा।

संघर्षरत देश : प्राय : विश्लेषण से छूट जाते हैं

बहुत से देशों में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, इनमें अधिकतर वे देश हैं जो संघर्षरत हैं या फिर संघर्ष के बाद के दौर में हैं। अतैव ये देश रिपोर्ट विश्लेषण में पूर्णत: प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। उनकी ई एफ ए (सर्व शिक्षा प्राप्ति) की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और जब हम वैश्विक सर्व शिक्षा (ई एफ ए) की तस्वीर पर ध्यान देते हैं तो उन्हें याद करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए, उनके जीवन में कुछ स्थायित्व लाने के लिए उपभोक्ता अपेक्षित शिक्षा अवसरों (कस्टम टेलर्ड एजूकेशन अपारचुनटीज) की आवश्यकता होती है।

वित्त एवं अनुदान

घरेलू व्यय उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1999 से 2004 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा व्ययों पर 106 देशों में से 41 देशों में कमी आई है जबकि अन्य क्षेत्रों के व्ययों पर वृद्धि हुई है। सबके लिए शिक्षा या सर्वशिक्षा (ई एफ ए) का लक्ष्य को पाने के लिए सरकारी व्ययों का ध्यान इस दिशा में केन्द्रित करने की आवश्यकता है; जैसे कि शिक्षकों, प्रौढ़ साक्षरता, बालपन में बच्चों की देखभाल व शिक्षा (ई सी सी ई) तथा सभी स्तरों की नीतियों पर ध्यान देना।

स्कूल फीस स्कूल फीस बहुत सारे देशों में घटा दी गई है या बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। परन्तु अभी भी बहुत से देशों में प्राथमिक स्कूलों में गरीबों की शिक्षा में नामांकन (भर्ती) हेतु यह एक बहुत बड़ी बाधा है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु कुल सहायता कम आय प्राप्त वाले देशों में यह सहायता 2000 से 2004 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है (जो 1.8 बिलियन यू एस डालर से बढ़कर 2003 में 3.4 बिलियन है) जो कि पहले कम हो गई थी। संपूर्ण शिक्षा की सहायता हेतु, हालांकि कम आय समूह वाले देशों का हिस्सा लगातार 54% पर ही स्थिर है। सभी द्विपक्षी दानदाताओं में से आधे अपनी शिक्षा सहायता राशि को मध्य आय वाले विकासशील देशों को प्रदान करते हैं और लगभग आधे दान दाता अपने दान का केवल एक चौथाई हिस्सा ही प्राथमिक शिक्षा हेतु उपलब्ध कराते हैं।

त्वरित मार्गीय प्रयास दानदाता संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समन्वय-प्रक्रम उपलब्ध कराता है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए वैश्विक सुसम्बद्धता को नहीं बढ़ा सका है। वर्ष 2002 से अब तक केवल 11 देशों में पहुँच बना पाया है और केवल 96 मिलियन यू एस डालर संवितरित कर पाया है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा दानकर्ताओं ने महत्वपूर्ण रूप से अपनी राशि बढ़ाई है।

फांडिंग अंतराल सर्वशिक्षा (ई एफ ए) के लिए बाहरी फंडिंग की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा तथा शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा भी शामिल है, जिसके लिए एक वर्ष हेतु नयी अनुमानित राशि 11 बिलियन यू एस डालर है। जोकि वर्तमान राशि से तीन गुना और हाल ही में प्रतिज्ञात (वचनवृद्ध) आश्वासन राशि से दोगुना है और लगभग समस्त राशि की 2010 तक प्राप्ति की संभावना है।

आरंभिक बालपन सेवा तथा शिक्षा

यह क्या है?

- शैशवकालीन देखभाल तथा शिक्षा (ECCE) की औपचारिक परिभाषा भिन्न-भिन्न है। यह रिपोर्ट एक समग्र उपागम अपनाती है-ई. सी. सी. ई. (शैशवकालीन देखभाल तथा शिक्षा) बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि, विकास एवं शिक्षा को समर्थन देता है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता और जन्मजात/सहजात, सामाजिक, शारीरिक (भौतिक) तथा भावनात्मक विकास शामिल है-जिसमें जन्म से प्राथमिक स्कूल की औपचारिक, अनुपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाएं भी आती हैं।
- ई सी सी ई कार्यक्रमों के घेरे में विविध व्यवस्थाएं आती हैं जिसमें समुदाय आधारित बाल सेवा के लिए अभिभावकत्व से लेकर, केन्द्र-आधारित प्रावधान तथा विद्यालयों में प्राय: दी जाने वाली औपचारिक पूर्व प्रांरभिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।
- ये कार्यक्रम विशिष्ट रूप से दो आयु समूहों के लिए लक्षित हैं- एक में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे आते हैं, जबकि दूसरे में तीन वर्ष से प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश स्तर की आयु वाले बच्चे आते हैं। (जिसमें सामान्यत: 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के होते हैं)।

यह क्यों महत्त्व रखती है?

- ई सी सी ई एक अधिकार है जिसे "बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन" में मान्यता दी गई थी और जिसने लगभग सार्वजनिक वैश्विक अभिपुष्टि पाई थी।
- ई सी सी ई आपके बच्चों की बेहतरी को और अच्छा बना सकता है, विशेष रूप से विकासशील दुनिया में जहाँ एक बच्चे को दस में चार अवसर घोर गरीबी में रहने के पेश आते हैं और जहाँ पर एक वर्ष के दौरान 5 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले रोकथाम या निवारण योग्य बीमारियों से 10.5 मिलियन बच्चे मर जाते हैं।
- मस्तिष्क के विकास के लिए शैशवकाल विशिष्ट समय होता है जोकि भावी शिक्षण (आधिगम) की नींव डालता है।
- ई सी सी ई अन्य सबके लिए शिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्यों में भागीदारी करता है (जैसे कि यह प्राथमिक स्कूल के पहले वर्ष के निष्पादन को बेहतर बनाता है)। और साथ ही सहस्राब्दी (मिलेनियम) के विकास लक्ष्यों में, विशेष रूप से गरीबी घटाने के लक्ष्य में पहुँचने के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में हाथ बंटाता है।
- यह निवारक उपायों को क्रियान्वित करने तथा प्रारंभिक आयु के बच्चों को सहारा देने में बहुत ही लागत प्रभावी है, विशेषकर उन बड़े बच्चों की कमियों को क्षतिपूरित करने के लिए जिन्हें ये सेवाएं शैशवकाल में नहीं मिलती।
- वहन योग्य, भरोसेमंद बाल देखभाल कामकाजी लोगों (अभिभावकों) को अनिवार्य सहारा प्रदान करता है, विशेष रूप से कामकाजी माताओं के लिए।
- ई सी सी ई में निवेश करने से अति उच्च आर्थिक वापसी प्राप्त होती है जो कि उनकी कमियों तथा असमानताओं को दूर करता है, विशेष रूप से गरीब परिवार के बच्चों के लिए लाभदायक है।

स्थिति क्या है?

- लगभग 80% विकासशील देशों ने कुछ हद तक औपचारिक प्रसूति अवकाश प्रतिष्ठापित किए हैं, हालाँकि इनका लागू होना वैविध्यपूर्ण है।
- अत्यंत छोटे बच्चों की बहुत उपेक्षा होती है। पूरी दुनिया के लगभग आधे देशों के पास तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं हैं।
- आज पूर्ण प्राथमिक शिक्षा में, 1970 की अपेक्षा तीन गुनी संख्या में पंजीयन बढ़े हैं, फिर भी बच्चों का सम्मिलन अभी भी अधिकतर विकासशील दुनिया में बहुत निम्न है।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) के अधिकतर देश कम से कम दो वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराते हैं।
- विकासशील देशों के बीच, लातीनी अमेरिकी, कैरीबियन तथा प्रशांत सागरीय देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात काफी उच्च है जबकि उसके काफी पीछे पूर्वी एशिया, दक्षिण एवं पश्चिम एशिया, अरब राष्ट्र तथा उप सहारा फ्रीकी देश आते हैं।
- वर्ष 1990 में तीव्र गिरावट के पश्चात मध्य एवं पूर्वी यूरोप के संक्रमणशील देश धीरे-धीरे उबर सके परन्तु मध्य एशियाई देश अभी भी पीछे हैं।
- विकासशील एवं संक्रमणशील देशों के साथ और लीतीनी अमेरिकी देशों सहित सरकारी क्षेत्रों द्वारा सर्वाधिक ई सी सी ई कार्यक्रमों का प्रावधन रखा गया है।
- इस दिशा में निजी क्षेत्र की उपस्थिति उप सहारा अफ्रीकी, अरब राष्ट्रों तथा कैरीबियन एवं पूर्वी एशिया क्षेत्रों में प्रचुरता से है।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अधिकतर क्षेत्र लैंगिक समानता के करीब हैं।
- कुछेक महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर, सभी देशों के भीतर भी व्यापक असमानताएं हैं। गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के बच्चे और वे जो समाज से बहिष्कृत हैं (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र आदि नहीं है) वे महत्वपूर्ण रूप से ई सी सी ई कार्यक्रमों तक, शहरी परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कम पहुँच वाले हैं।
- ई सी सी ई कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले बच्चे बहुत संभव हद तक वे हैं जो कुपोषण के अधिक करीब या जोखिम में हैं और निवारक रोगों की परिधि में हैं। परन्तु वे संभवत: सबसे कम नामांकित होते हैं।
- विकासशील देशों के ई सी सी ई कर्मचारी विशिष्ट रूप से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण पूर्व सेवा वाले होते हैं और प्राय: उन्हें अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी समनुरूपता अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाली होती है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की व्यापक समिश्रित सेवा प्रदाताओं की कमी तथा आँकड़ों की कमी ई सी सी ई पर कुल राष्ट्रीय खर्चों की गणना को मुश्किल बना देती हैं। फलत: इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे देश विकासशील परिदृश्य को ध्यान में रखकर ऐसी अनुमानित लागत बना सकते हैं जो सम्मिलन, गुणवत्ता एवं प्रावधान की प्रकृति के रूप में बहुत भिन्न हो सकती हैं।
- अधिकतर दान कर्ता संस्थाओं के लिए ई सी सी ई एक प्राथमिकता नहीं है। वे लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा की तुलना में केवल 10% राशि सुनिश्चित करते हैं। इनमें से आधे से भी कम 2% राशि सुनिर्धारित करते हैं।

कार्यक्रमों के क्या काम हैं?

- एक ऐसा उपागम जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल एवं शिक्षा का सम्मिश्रण अधिक प्रभावी तरीके से छोटे बच्चों के वर्तमान कल्याण कार्यों तथा उनके विकास को बेहतर बनाता है जो कि एक पहलू से हस्तक्षेपों को सीमित बनाते हैं।

- परम्परागत बाल कल्याण व्यवहारों पर बने सम्मिलित कार्यक्रम बच्चों की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले तथा विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाते हैं।

- सरकारी या कार्यालयी भाषा की अपेक्षा मातृ भाषा में चलाए जाने वाले कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं जो कि पूरी दुनिया भर में एक मानदंड के रूप मे विद्यमान हैं।

- सुरचित कार्यक्रम लैंगिक रुढ़िबद्धता को चुनौती दे सकते हैं।

- ई सी सी ई समानता का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्प बच्चों एवं कर्मचारियों के बीच, बच्चों की आवश्यकताओं पर केंद्रित परस्पर क्रिया है। इसके लिए औचित्यपूर्ण कार्यदशाओं की अपेक्षा होती है। जैसे कि बच्चे/कर्मचारी निम्न अनुपात एवं पर्याप्त सहायक सामग्री।

- कर्मचारी निरंतरता, पाठ्यक्रम तथा अभिभावकों का सम्मिलन प्राथमिक स्कूलों हेतु आसान पारगमन होता है। आरंभिक वर्ष में स्कूली शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों एवं अनुभवों से आए छोटे बच्चों के लिए बेहतर समायोजन की आवश्यकता होती है।

ई सी सी ई लक्ष्य पर पहुँचने के लिए क्या आवश्यकता होगी?

- उच्च स्तरीय राजनैतिक समर्थन एक अनिवार्य घटक है।

- जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए एक परामर्शक प्रक्रम, जो उपयुक्त क्षेत्रों तथा सरकार के सभी स्तरों के आर-पार प्रशासकीय जिम्मेदारी एवं बजटीय बचनवद्धता को विशिष्टीकृत करें।

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर आँकड़ों का संकलन तथा निगरानी प्रयास ताकि सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की गोष्ठियों में आवश्यकताओं एवं परिणामों का मूल्यांकन होता रहे।

- छोटे बच्चों एवं ई सी सी ई की नीतियों के लिए एक अग्रणी मंत्रालय या संस्था को मनोनीत करना तथा निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण समन्वयन प्रक्रम के साथ एक अंतर संगठन/संस्था को विर्निदिष्ट करना।

- सभी आयु समूहों के लिए सरकारी एवं निजी प्रावधानों को आवृत करने हेतु बेहतर प्रवर्तित राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक।

- सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सुदृढ़ एवं अधिक भागीदारी, जोकि बहुत सारे क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण ई सी सी ई पणधारी (भागीदार) हैं।

- ई सी सी ई कर्मचारी की प्रोन्नति, विशेष रूप से लचीली भर्ती नीतियों के माध्यम से, उपयुक्त प्रशिक्षण, मानक गुणवत्ता एवं पारिश्रमिक जोकि प्रशिक्षित कर्मचारी को रोक सकें।

- ई सी सी ई की बढ़ी हुई तथा बेहतर लक्षित सरकारी फंडिंग, विशेष रूप से गरीब बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तथा विकलांगतायुक्त बच्चों का खास ध्यान रखने के साथ।

- प्रमुख सरकारी संसाधन अभिलेखनों में ई सी सी ई का विशिष्ट सम्मिलन जैसे कि राष्ट्रीय बजट, क्षेत्रीय योजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यनीतियों के विलेख आदि।

- दानदाता संस्थाओं की ओर से अधिक ध्यान एवं अधिकाधिक फंडिंग।

प्रस्तावना

एक बच्चे की शिक्षा उसके कक्षा में प्रवेश करने के बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चों के शुरूआती वर्षों की सर्वोच्च महत्ता को वर्ष 2000 में डाकार में 164 देशों द्वारा अधिगृहीत किए गए सबके लिए शिक्षा (EFA) के पहले छह लक्ष्यों में व्यक्त किया गया है। ये वर्ष अत्यंत सुकुमारता एवं अकूत क्षमता वाले होते हैं, जिस दौरान पर्याप्त संरक्षा, देखभाल एवं उत्प्रेरणा आवश्यक होते हैं ताकि बच्चे की सकुशलता एवं विकास के लिए एक आधार उपलब्ध हो सके।

सबके लिए शिक्षा या सर्वशिक्षा लक्ष्य की सरकारों से पहली माँग शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा के विस्तार तथा विस्तृत या विलक्षण सुधार पर है। विशेषरूप से सर्वाधिक सुकुमार या जोखिमजन्य एवं लाभ वंचित बच्चों के लिए, जिनके पास ऐसे अवसरों के लिए न्यूनतम अवसर होते हैं और जो लाभों से बहुत दूर खड़े होते हैं।

विस्तृत कार्यक्रमों के लिए आहवान एक समग्र उपागम को संदर्भित करता है जिसके दायरे में जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल दोनों ही आते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम आवश्यकताओं की एक परिधि पर केन्द्रित होते हैं जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण से लेकर जन्मजात, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तक होते हैं। समग्र शैशवकालीन कार्यक्रम सबके लिए प्राथमिक शिक्षा एवं गरीबी घटाने की लक्ष्यप्राप्ति की किसी भी रणनीति में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। जो कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुँचने का उद्देश्य भी है। अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर बनाते तथा एच आई वी/एड्स से लड़ते हैं और बच्चों को प्राथमिक स्कूल हेतु सहज पारगमन के लिए तैयार करते हैं।

हाल ही के वर्षों में शैशवकालीन के लिए प्रतिबद्धताएं बढ़ी हैं। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यू.एन.जी.ए) द्वारा "बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन" आयोजित किया गया और अब तक इसे 192 देशों द्वारा समर्थित किया जा चुका है। यह बच्चों की उत्तरजीविता, विकास तथा संरक्षण के लिए बच्चों के अधिकारों हेतु एक अनूठा प्रपत्र (उपकरण) है। तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन शैशव जीवन की नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं। विकासशील देशों में शैशव जीवन के कार्यक्रमों तक पहुँच बहुत व्यापकता से नहीं हो पाई है। इसके विपरीत, विकसित देशों के अधिकतर बच्चे कम से कम दो वर्ष तक की प्राथमिक स्कूल से पूर्व स्कूल की शिक्षा मुफ्त प्राप्त करते हैं।

शैशवकालीन के अतिरिक्त, यह रिपोर्ट पाँच अन्य सर्व शिक्षा लक्ष्यों के व्यापक विश्लेषण के साथ-साथ प्रगति की निगरानी कर रही है जिसमें पहले की अपेक्षा स्कूल से बाहर के बच्चे तथा उन तक एवं अन्य जोखिम समूह के बच्चों तक पहुँचने की रणनीति शामिल है। यह सरकारों द्वारा सबके लिए शिक्षा प्राप्ति हेतु नीतियों के क्रियान्वयन की गतिविधियों तथा उसके बाहर कौन सा दानदाता इन प्रयासों को समर्थन दे रहा है, का अभिलेखन करती है। इसके बाद यह रिपोर्ट अपने विशेष विषय की ओर बढ़ती है। शैशवकालीन की देखभाल एवं शिक्षा (ई सी सी ई) कार्यक्रमों की सुदृढ़ता के लिए विवेकपूर्ण विन्यास स्थापना के बाद, इन सेवाओं के लिए यह रपट देशों के प्रावधानों का मूल्यांकन करती है, विशेषरूप से लाभ रहित या जोखिम समूह के बच्चों के लिए भिन्न उद्देश्यों के साथ विविध विन्यास वाले, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सेवा देने हेतु, सभी कार्यक्रम प्रकृति में अत्यधिक भिन्नता पूर्ण होते हैं, और अभी भी अच्छी व्यवहारिकता की अनेक विशिष्टताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद विस्तारण प्रावधानों के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक समुदाय के लिए एक संक्षिप्त एजेंडे की कार्यवाही के साथ समाप्त होती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष क्षेत्र पार राष्ट्रीय शैक्षिक सांख्यिकियों, परिवार सर्वेक्षणों, निष्कर्षों, साहित्य समीक्षाओं तथा विशेष रूप से निगमित लेखों जो वेबसाइड पर (www. efa report.unesco.org) उपलब्ध है, जिसमें इस रिपोर्ट का सारांश भी सम्मिलित है। इसके साथ ही पूरी रिपोर्ट में सांख्यिकी सारणियां एवं क्षेत्रीय अवलोकन भी दिए गए हैं। ■

सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा

1. विस्तृत शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा का विस्तार एवं सुधार, विशेष रूप से अधिक जोखिम युक्त एवं लाभ रहित बच्चों के लिए।
2. यह सुनिश्चिय करते हुए कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, विशेषतौर पर लड़कियों, कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों और वे बच्चे जो मानवजातीय अल्पसंख्यक हैं, को पूर्णत: मुफ्त तथा अच्छी किस्म की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो।
3. यह सुनिश्चित करें कि सभी छोटे बच्चों एवं वयस्कों की शिक्षा आवश्यकता समान पहुँच के साथ उपयुक्त शिक्षण एवं जीवन कौशल कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त हो।
4. वर्ष 2015 तक प्रौढ़ शिक्षा के स्तर का 50 प्रतिशत सुधार प्राप्त हो, विशेषतौर पर स्त्रियों के लिए, और सभी वयस्कों के लिए आधारभूत तथा सतत शिक्षा समान पहुँच से प्राप्त हो।
5. वर्ष 2005 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विषमता समाप्त हो और वर्ष 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राप्त हो कि लड़कियों को पूर्ण एवं समान पहुँच के साथ तथा अच्छी किस्म की प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित बनाया जाए।
6. शिक्षा की बराबरी के सभी पहलुओं में सुधार हो तथा सबके लिए सर्वोत्कृष्टता सुनिश्चित हो ताकि सभी के द्वारा प्राप्त अधिगम के परिणाम मापनीय एवं मान्यतापूर्ण हों। विशेष रूप साक्षरता, संख्या – गणना तथा आवश्यक जीवन कौशल से पूर्ण हों।

भाग–I. सबके लिए शिक्षा की दिशा में प्रगति: सामना करते अपवर्जन

प्राथमिक शिक्षा विस्तारण
स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट
बच्चे स्कूल में क्यों नहीं हैं
माध्यमिक स्कूलों पर दबाव
लैंगिक भेदभाव घट रहा है
शिक्षकों की कमी एक चुनौती
दुर्ग्राह्य साक्षरता लक्ष्य
अपवर्जन से निपटने के उपाय
अपर्याप्त घरेलू व्यय

सबके लिए या सर्व शिक्षा लक्ष्य एक व्यापक अधिगम वर्णक्रम में फैले हैं जो छोटे बच्चों की देखभाल एवं सहजात विकास से लेकर युवाओं एवं वयस्कों के लिए साक्षरता एवं जीवन कौशलों के माध्यम तक जाते हैं। यह भाग व्यापक रूप से वर्ष 2004 की समाप्ति पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिक्स (यू आई एस) के लिए रिपोर्ट किए गए आँकड़ों पर आधारित है। इसके साथ में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता सुधार तथा बच्चों, युवा एवं वयस्कों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी प्रगति चार्ट आदि भी शामिल हैं। स्कूल से बाहर बच्चों की स्थिति ने विशेष ध्यान प्राप्त किया है। यदि कोई सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों को बाहर रखने वाली बाधाओं को समझती है, केवल तभी वे ऐसी नीतियों की रचना एवं क्रियान्वयन कर सकती हैं और यह गारंटी दे सकती हैं कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का बाल अधिकार सुनिश्चित हो। यह भाग बच्चों की शिक्षा तक पहुंच एवं पूर्णत्व के लिए लक्षित नीतियों व कार्यक्रमों को; विशेष रूप से कठिन पहुंच वाले समूहों को पहचान रहा है। शैशवकालीन कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने की प्रगति भाग–IV में अलग व्याप्ति (कवरेज) प्राप्त कर रही है।

सब के लिए शिक्षा विकास सूची: अति गरीब देशों ने अधिकाधिक प्रगति की है।

सब के लिए शिक्षा विकास सूची या सूचकांक (ई डी आई) को वर्ष 2003-04 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था जो एक देश की स्थिति के साथ-साथ सब के लिए शिक्षा लक्ष्यों की एक संक्षिप्त माप उपलब्ध कराती है: वे हैं- सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा (यू पी ई), वयस्क/प्रौढ़ साक्षरता, लिंग एवं शिक्षा में समानता। शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा (लक्ष्य-1) को, और युवाओं एवं वयस्कों की अधिगम आवश्यकता (लक्ष्य-3) को सम्मिलित करने हेतु आँकड़े अपर्याप्त रूप से मानकीकृत पाए गए।[1] चारों लक्ष्यों में से प्रत्येक एक छद्म संकेतक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ई डी आई चारों संकेतों का एक सरल औसत है जो 0 और 1 के बीच परिवर्ती है, जिसमें 1 के साथ ई एफ ए उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2004 में 125 देशों के लिए यह सूची संगणित की गई थी।

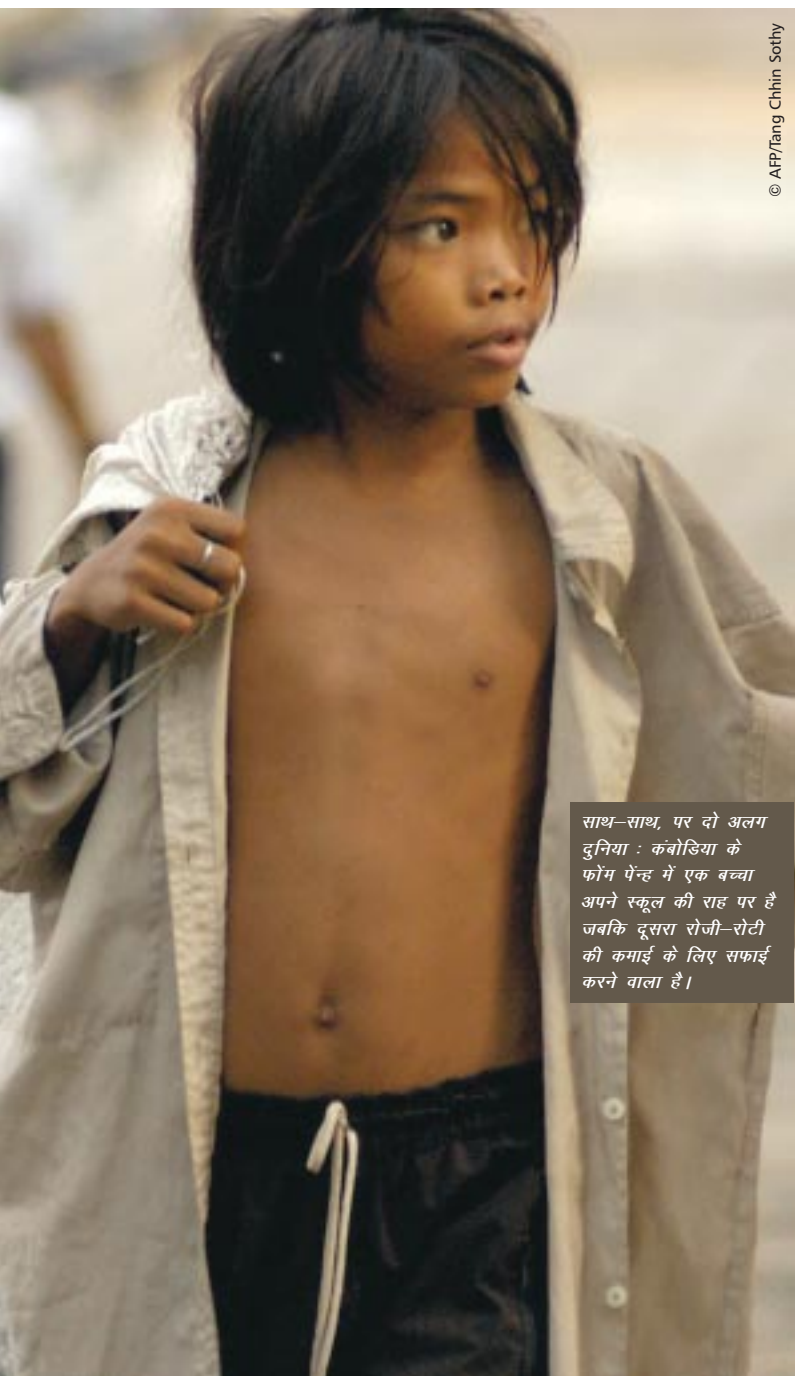

© AFP/Tang Chhin Sothy

साथ–साथ, पर दो अलग दुनिया : कंबोडिया के फ्नोंम पेन्ह में एक बच्चा अपने स्कूल की राह पर है जबकि दूसरा रोजी–रोटी की कमाई के लिए सफाई करने वाला है।

- 47 देशों के पास 0.95 या इससे अधिक की ईडीआई पहुँच चुकी है और इन्हें सबके लिए शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने वाले या प्राप्ति के करीब की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के लगभग सभी देश भी इसी श्रेणी में हैं और इसके साथ ही इस श्रेणी में लातीनी अमेरिकी तथा कैरीबियन क्षेत्र के 6 देश तथा मध्य एशिया के 4 देश आ चुके हैं।

- सभी क्षेत्रों में विस्तृत लगभग 50 देशों की ई डी आई का परिणाम 0.80 से 0.94 के बीच है। लातीनी अमेरिकी लगभग सभी 15 देश इस श्रेणी में आ रहे हैं; क्योंकि ग्रेड-5 में अपेक्षाकृत निम्न उत्तरजीविता है। अरब देशों के मामले में प्रौढ़ शिक्षा की निम्न दर कुल मिलाकर पूरी ई डी आई को नीचे ला देती है। इसमें अधिकतर 8 देश इस श्रेणी में उप सहारा अफ्रीकी, दक्षिणीय अफ्रीकी या छोटे द्वीप समूह वाले हैं।

- 28 देशों का ई डी आई योग 0.80 से नीचे है। इसमें दो तिहाई देश उप सहारा अफ्रीकी, लेकिन कुछ अरब राष्ट्र तथा दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के देश हैं। इस श्रेणी के 5 देश, जो सभी फ्रेंच भाषी हैं, व पश्चिमी अफ्रीका से आते हैं, 0.60 से नीचे का योग रखते हैं।

वर्ष 2003 से वर्ष 2004 में सूचकांक औसतन 1.6 प्रतिशत बढ़ा है। आशाप्रद बात यह है कि उच्चतम ई डी आई वृद्धि 4.5 प्रतिशत की है जो कि निम्न तक ई डी आई देशों से संबद्ध है (चित्र 1.1)। हालाँकि; कम से कम एक दर्जन देश महत्वपूर्ण रूप से निम्नतम ई डी आई वाले हैं, जिनमें संघर्षरत या संघर्ष के पश्चात स्थिति वाले देश भी हैं जिन्हें आँकड़ों के अभाव के कारण से भी विश्लेषणों में छोड़ दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा : सतत विस्तार, परन्तु अभी भी सभी के लिए नहीं

सर्व शिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्य तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य वर्ष 2015 है। यदि तब तक सभी बच्चे अच्छी किस्म की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं तथा इनमें से जो भी उपयुक्त आयु वाले हैं उन्हें निश्चित रूप से वर्ष 2009 तक कक्षा 1 में पंजीकृत हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा पर घरेलू तथा बाहरी व्यय, दोनों ही अवश्य बढ़ाए जाने चाहिए ताकि और अधिक जगहें व शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। सरकारों को निश्चित तौर पर ऐसी एक बेहतर समझ बनानी होगी कि कुछ खास बच्चे कभी भी स्कूल में नामांकित क्यों नहीं हो पाते हैं या जल्दी ही पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं। ताकि ऐसे कार्यक्रम विनिर्मित किए जाएं जो प्रभावी तरीके से इन बाधाओं से निपट सकें।

वर्ष 2004 में, लगभग 682 मिलियन बच्चों को प्राथमिक स्कूल में पंजीकृत किया गया जो 1999 से 6 प्रतिशत की वृद्धि है। उनकी यह संख्या उप सहारा अफ्रीकी (27 प्रतिशत), दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (19 प्रतिशत) काफी तेजी से तथा अरब राष्ट्रों की काफी धीमी (6 प्रतिशत) दर से बढ़ी है। दुनिया भर में कुल प्राथमिक पंजीयन अनुपात[2] वर्ष 1999 में 83 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 86 प्रतिशत हुआ है (चित्र 1.2)। सबसे कम व्याप्ति वाले क्षेत्रों ने आश्चर्यजनक छलांग लगाई है। उप सहारा अफ्रीकी देशों में एन ई आर 55 प्रतिशत से बढ़कर

1. यू पी ई: कुल प्राथमिक नेट पंजीयन अनुपात: प्रौढ़ साक्षरता: 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की साक्षरता दर; लैंगिक समानता एवं बराबरी : जेंडर-विशिष्ट ई एफ ए सूचकांक (संसूची), शिक्षा की गुणवत्ता: ग्रेड (कक्षा) 5 में उत्तरजीविता दर।

2. एक दिए गए शिक्षा स्तर हेतु सरकारी आयु समूह का पंजीयन या नामांकन, जो उस आयु समूह की जनसंख्या के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है।

विश्व भर में ऊपर को उठते पंजीयन की प्रवृत्ति से लड़कियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

65 प्रतिशत हुई और दक्षिण तथा पश्चिम एशियाई देशों में यह 77 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत जा पहुँची। लगभग सभी देश जो 1999 में 85 प्रतिशत से नीचे एन ई आर के साथ थे, उनकी स्थिति में सुधार आया, कुछ मामलों में यह महत्वपूर्ण रहा (जैसे कि इथोपिया, लेसोथो, मोरक्को, मोजांबिक, नेपाल, नाइगर तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया)। यहाँ पर कुछ चिंता का विषय भी है जहां कुछ अवधि में 45 विकासशील देशों में से 24 देशों की एन ई आर में गिरावट आई, जहां पर 1999 में यह 85 प्रतिशत से ऊपर थी।

विश्व भर में ऊपर को उठते पंजीयन की प्रवृत्ति से लड़कियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। जिन देशों में लड़कियों का पंजीयन अनुपात कम था तथा उनके साथ शिक्षा तक पहुँच हेतु लैंगिक भेदभाव था। आज, 2004 में दुनिया भर में हर 100 लड़कों के प्राथमिक स्कूल में पंजीयन की तुलना में लड़कियों की संख्या 94 है, जो 1999 के 92 की तुलना में अधिक है। उपलब्ध आँकड़ों वाले 181 देशों में से दो तिहाई देशों ने प्राथमिक स्कूलों में लैंगिक समानता प्राप्त कर ली है। कई देशों ने यह समानता 1999 में ही प्राप्त कर ली थी जिनमें मलावी, मारीटानिया, कतर तथा यूगांडा आदि हैं। अभी भी लिंग भेदभाव व्यापक तौर पर अफगानिस्तान (जहाँ 100 लड़कों की तुलना में 44 लड़कियाँ हैं), मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइगर, पाकिस्तान तथा यमन आदि में हैं। हालाँकि, एक बार स्कूल आने के बाद, लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ स्कूल में अधिक रुकती हैं उनकी कार्यदक्षता भी अपेक्षाकृत बढ़िया होती है।

प्राथमिक स्कूल सहभागिता में वैश्विक वृद्धि ग्रेड। की नए प्रवेशकों में व्यापक रूप से प्रदर्शित होती है। वर्ष 1999 एवं 2004 के बीच उप सहारा अफ्रीका में यह उछाल 30.9% दिखती है। पहली कक्षा के छात्रों में यह वृद्धि दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में 11.5% और अरब राष्ट्रों में 9.1% आई है जबकि यमन में अत्यंत तीव्र वृद्धि 57% सबसे आगे रही है।

कक्षा (ग्रेड-I) में देर से प्रवेश पाने वाले व्यापकतौर पर उप सहारा-अफ्रीकी देशों में विद्यमान हैं, जबकि यही प्रवृत्ति लातीन अमेरिका तथा कैरेबीयाई देशों में भी हैं। कुछ साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि जब बच्चे बड़ी उम्र में प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें बहुत संभव अधिगम की कठिनाइयों का अनुभव होता है और उनके शिक्षा के अगले चरण में जाने की कम संभावनाएं होती हैं। बड़ी उम्र में पंजीयन के लिए आने वाले बच्चे बहुत हद तक गरीब परिवारों या प्राय: दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों वाले होते हैं। इसमें माँ की शिक्षा भी प्राय: बहुत महत्वपूर्ण प्रभावक होती है। केन्या में, जिन बच्चों की माँ पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं उनमें 60% के बच्चे स्कूल में अपेक्षाकृत देरी से नामांकन के लिए आते हैं जबकि इसकी तुलना में एक तिहाई बच्चों की माँएं प्राथमिक स्कूल तक पढ़ी होने के कारण सही समय पर बच्चे का नामांकन कराती हैं।

कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं?

स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटाने की दिशा में प्रगति हुई हैं[3]। प्राथमिक स्कूली आयु के अनुमानित बच्चों के आँकड़ों को प्राथमिक स्कूल में नामांकित बच्चों के प्रशासकीय आँकड़ों की तुलना करने पर यह संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2004 में 77 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं थे जो कि 1999 की तुलना में 21 मिलियन कम हैं। यह एक ध्यान देने योग्य उपलब्धि है। वर्ष 2002

3. यह रिपोर्ट स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या के लिए और अधिक परिशुद्ध मापदंड प्रस्तुत करती है। पहले का परिकलन प्राथमिक स्कूल की आयु वाले बच्चों की संख्या पर आधारित था, जो कि प्राथमिक स्कूल में नामांकित नहीं थे। यहाँ कुछ बच्चों को स्कूल से बाहर का मानकर गिन लिया गया था, जबकि वे पहले ही माध्यमिक शिक्षा में नामांकित हो चुके थे। परिभाषा के अनुसार स्कूल से बाहर एक बच्चा वह है जो न तो प्राथमिक स्कूल में और न तो माध्यमिक स्कूल में नामांकित है।

चित्र 1.1 = वर्ष 2003 से वर्ष 2004 में परिवर्तित ई डी आई।

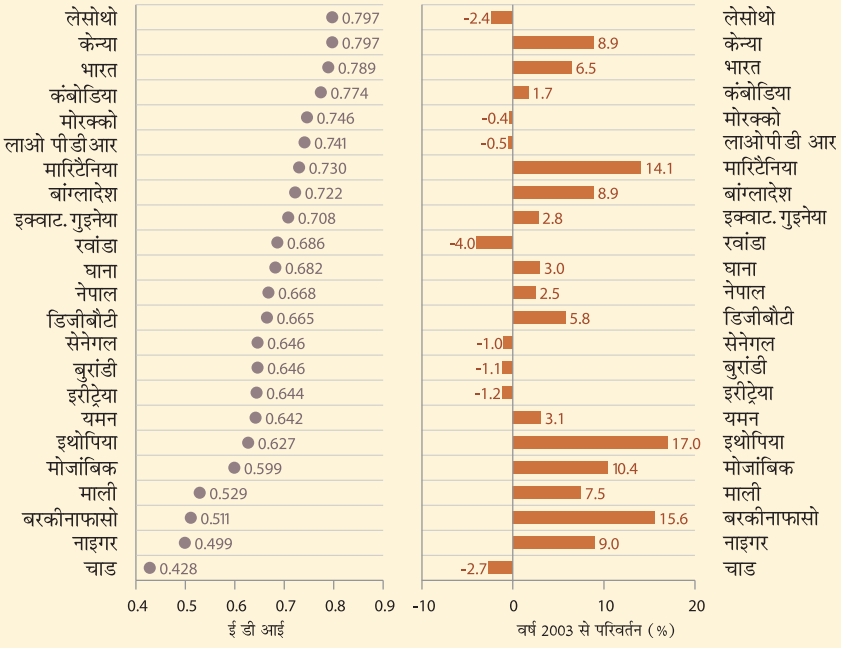

सूचना : केवल वे देश शामिल हैं जिनका ई डी आई योग 0.800 से कम है।
स्रोत :– देखें, अध्याय–2, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट

चित्र 1.2: वर्ष 1999 एवं 2004, प्राथमिक शिक्षा में नेट पंजीयन अनुपात

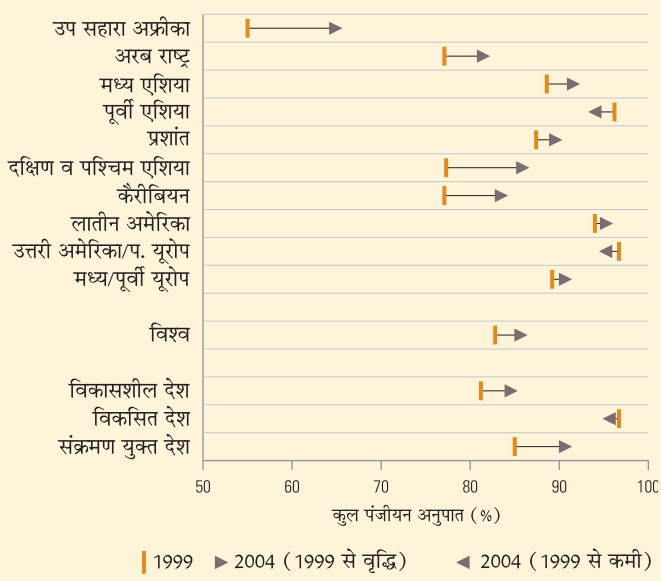

स्रोत : देखें अध्याय 2, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट

से 2004 के बीच तीन चौथाई गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 1999 से 2004 के बीच सभी विकासशील देशों के क्षेत्रों में इस संख्या में कमी आई, जिसमें दक्षिण तथा पश्चिम एशिया में तीव्र गिरावट आई (जो 31 मिलियन से 16 मिलियन पहुँच गई) इसमें अधिकांश व्यापक गिरावट भारत में आने के कारण हुई। आज भी उप सहारा अफ्रीकी देशों में दुनिया भर के स्कूलों में जाने वाले बच्चों की आधी संख्या रहती है, यद्यपि 1999-2004 के बीच यह 43 मिलियन से घटकर 38 मिलियन हुई है। स्कूल से बाहर बच्चों में लड़कियों की संख्या 57% है जो कि 1999 में 59% की तुलना में थोड़ी कम है। यह भागीदारी दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (69%) में काफी अधिक है। यहाँ 28 विकासशील देशों में (112 में से, जिनसे सूचनाएं उपलब्ध हैं) से प्रत्येक में आधा मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। नाइजीरिया, पाकिस्तान, भारत तथा यूथोपिया (क्रमश: घटते क्रम में) आदि भारी संख्या में -23 मिलियन बच्चे इन चार देशों के हैं (चित्र 1.3)।

प्रोत्साहन पूर्ण बात यह है कि स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है पर यह आत्मसंतुष्टि नहीं बननी चाहिए। कुछ देशों के लिए पंजीयन पर सरकारी आँकड़ों एव अन्य हेतु परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त उपस्थिति सूचनाओं का उपभोग करते हुए यू आई एस और यूनीसेफ के एक संयुक्त अध्ययन से वर्ष 2002 में स्कूल से बाहर के बच्चों की अनुमानित संख्या 115 मिलियन थी, जबकि इसी वर्ष प्रशासकीय आँकड़े इसे 94 मिलियन की संख्या सुझाते थे। इसके अतिरिक्त दोनों ही अनुमान संभवत: नियमित स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करके आँकते हैं। हाल ही में भारत भर में प्राथमिक स्कूलों एव बच्चों की संख्या पर हुआ सर्वेक्षण यह दिखाता है कि सर्वेक्षण के दौरान स्कूल विजिट करने पर 30% बच्चे अनुपस्थित थे।

वे कौन से बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं हैं?

उन सरकारों के लिए जो स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को घटाने के लिए नीतियाँ बनाती एवं क्रियान्वित करती हैं, उन्हें यह बेहतर समझना आवश्यक है कि वे कौन हैं? इस रिपोर्ट के लिए यू आई एस तथा यूनीसेफ अध्ययन एवं कार्य ने स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए प्रमुख विशिष्टताओं एवं शैक्षिक अनुभवों को हाथ में लिया है। यह साक्ष्य उन कार्यक्रमों की रचना के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो लाभहीनता की विभिन्न दिशाओं को प्रभावी तरीके से सुधारती है (बाक्स 1.2)।

लगभग 77 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं हैं

वर्ष 2004 में मोटेतौर पर 77 मिलियन स्कूल न जाने वाले बच्चों में 7 मिलियन बच्चे स्कूल से अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले हैं। इनमें संभवत: 23 मिलियन देर से पंजीयन पाने वाले हैं जबकि 47 मिलियन बच्चे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कभी भी नामांकित नहीं होने वाले हो सकते हैं। तीसरे समूह के बच्चों का समानुपात उन स्थानों पर बहुत ऊँचा है जिन क्षेत्रों में निम्नतम शिक्षा संकेतक हैं, जैसे कि उप सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया, लातीनी अमेरिका तथा कैरीबियन देशों में पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों में देर से प्रवेशकों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत उनसे अधिक है जो बच्चे संभवत: कभी भी नामांकित नहीं हो सकते।

परिवार सर्वेक्षण लगभग अस्सी देशों के स्कूल में नहीं होने वाले बच्चों की पृष्ठभूमि के आँकड़े उपलब्ध कराता है (चित्र-1.4)।

- *लिंग :* जाँच की गई विशिष्टताओं के साथ लिंग का अंतर छोटी मात्रा में महत्व दर्शाता है। फिर भी, अरब देशों में लड़कियों का बहिष्करण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है (प्रत्येक 100 लड़कों के लिए 134 लड़कियां स्कूल में नहीं हैं) दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (129) तथा स्वतंत्र तौर पर कुछ देशों जैसे कि यमन(184), भारत (136) तथा बेनिन (136) है।

चित्र 1.3- 500,000 से अधिक स्कूल से बाहर वाले बच्चों के साथ विकासशील देश, 2004

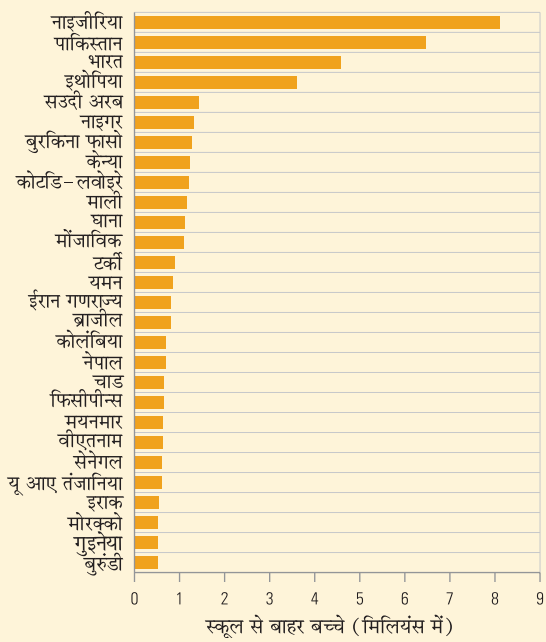

स्रोत : –देखें अध्याय–2, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट

चित्र 1.4: 80 देशों में स्कूल से बाहर के बच्चों की विशिष्टताएं

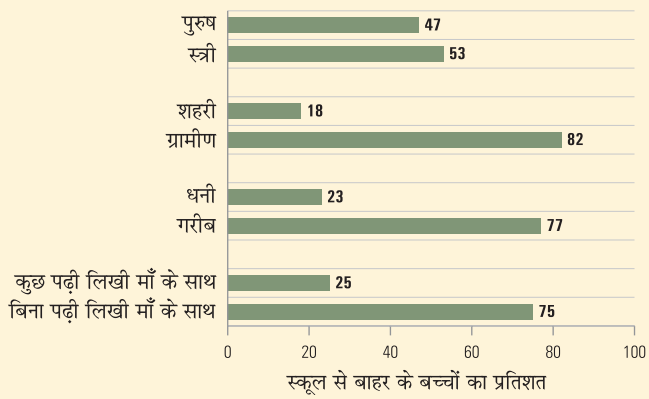

स्रोत : देखें पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट के अध्याय 2 में चर्चा

उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के अधिकतर देशों में दो तिहाई से कुछ कम ही बच्चे अंतिम ग्रेड तक पहुँच पाते हैं।

- ***आवास:*** 24 देशों में, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की भागीदारी में शहरी बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण बच्चों की संख्या कम से कम दोगुना है। बुरकीना फासो, इरिट्रेरा, इथोपिया तथा निकारागुवा में भारी पैमाने पर ग्रामीण–शहरी अंतर है। इसके साथ ही उप सहारा अफ्रीकी तथा दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में भी स्कूल से बाहर होने वाले 80% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

- ***पारिवारिक समृद्धि:*** वे बच्चे जो 20% गरीबतम परिवारों से होते हैं, वे 20% धनाड्य परिवारों के बच्चों की अपेक्षा संभवत: तीन गुना स्कूल से बाहर होते हैं। यह प्रभाव व्यापक रूप से एवं विशेषतौर पर अरब राष्ट्रों, तथा छोटे मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में है।

- ***माँ की शिक्षा:*** औसतन, एक बच्चे की माँ यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो वह पढ़ी लिखी माँ के बच्चे की तुलना में संभवत: दोगुना स्कूल से बाहर रहने की संभावना से युक्त होता है। दक्षिण एशिया एवं लातीनी अमेरिकी देशों में यह प्रवृत्ति 2.5 गुना के करीब है।

बहिष्करण के मिले–जुले प्रभाव लडखड़ा रहे हैं। गुइनियामें, एक शिक्षित माँ तथा समृद्ध परिवार से संबधित लडके के पास, एक गरीब ग्रामीण एवं अशिक्षित माँ वाली लड़की की अपेक्षा, स्कूल जाने के संभवत: 126 गुना अधिक अवसर होते हैं।

कितने बच्चे प्राथमिक शिक्षा के अंतिम कक्षा तक पहुँचते हैं?

बच्चे स्कूल में कितनी लंबी अवधि तक टिकते हैं, इस बात को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। जैसा कि स्कूल से बाहर बच्चों के विश्लेषण प्रकट करते हैं, उसके अनुसार एक परिवार की गरीबी बच्चे की शिक्षा की प्रमुख बाधा की भूमिका निभाती है। कुछ देशों में एक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई की लागत पर अपनी कुल आय का 40% से अधिक खर्च करते हैं जिनमें उनकी फीस, पुस्तकें, कपड़े तथा परिवहन आदि होता है। बच्चों की अक्सर परिवार के लिए पूरक आय जुटाने (बाक्स 1.1) या फिर अपने छोटे भाई–बहिनों की देख रेख के लिए आवश्यकता होती है। एक बार स्कूल में आने पर खराब किस्म की शिक्षा– जैसे कि भीड़–भाड़ युक्त कक्षा में पढ़ाई होना, खराब प्रशिक्षित शिक्षक तथा शिक्षा–सहायक सामग्री की कमी भी गंभीर रूप से छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करती है और इससे अधूरी पढ़ाई छोड़ने वालों का जोखिम बढ़ जाता है।

बाक्स 1.1: प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु बालश्रम को घटाना एक कुंजी है।

बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते। संभवत: घोरतम गरीबी के कारण किसी न किसी प्रकार के काम में लगे होते हैं। हालांकि हाल ही के वर्षों में बालश्रम की घटनाओं में कमी आई है फिर भी यहाँ पर लगभग 218 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं इनमें से तीन चौथाई बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम के हैं। कुल बच्चों में से लगभग 126 मिलियन बच्चे 5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और बाल शोषण के विकृत स्वरूपों में संलग्न हैं जैसे कि अवैध काम–धंधे, कर्ज से लेकर बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति तक तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियाँ। वर्ष 2006 में, विश्व के लगभग 162 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन पर बालश्रम के विकृत स्वरूप की अभिपुष्टि की है। अनेक देशों ने, बच्चों को अपने काम की जरूरतों को घटाने के लिए तथा स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए नकद छूट कार्यक्रम देने की शुरूआत की है। अन्य देश कामकाजी बच्चों के पास औचित्यपूर्ण लचीले शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सीधी पहुँच बना रहे हैं।

आँकड़े प्राप्त 132 देशों में लगभग आधों में, जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा में छात्र के रूप में प्रवेश पाते हैं उनमें से, 2003 में केवल 87% ही आखिरी ग्रेड तक पहुँच पाए। यह औसत क्षेत्रानुसार महत्वपूर्ण विविधता युक्त है। लातीनी अमेरिका तथा कैरेबीयन देशों में कुल मिलाकर प्राथमिक स्कूलों में उच्च स्तर की पहुँच व भागीदारी के बावजूद पूरी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाना महत्वपूर्ण यू पी ई चुनौती बना हुआ है और अधिकतर देशों में 83% से कुछ कम ही ग्रेड 1 से अंतिम ग्रेड तक पहुँचते हैं। उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के अधिकतर देशों में दो तिहाई से कुछ कम ही बच्चे अंतिम ग्रेड तक पहुँच पाते हैं। अनेक दक्षिणी एवं पश्चिमी एशिया के देशों में बच्चों का स्कूल में बने रहना भी काफी निम्न है जिनमें नेपाल व बांग्लादेश भी शामिल हैं।

ठीक वही घटक जो बच्चों को स्कूल से बाहर रखता है, वही बच्चों की अधूरी पढाई के लिए प्रभावक है। बिना किसी आश्चर्य के, बहुत संभव हद तक ग्रामीण क्षेत्रों एवं गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल से जल्दी ही पढ़ाई बंद कर देते हैं। फिर चाहे बच्चा किसी भी लिंग से क्यों न संबंधित हो। इथोपिया में, शहरी बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण बच्चे 60 गुना अधिक संभावना के साथ अधूरी पढ़ाई वाले होते हैं जब कि बुरकिना फासो, माली तथा मोजांबिक में 40% गरीब परिवारों के बच्चों में से केवल 10% ही प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में सफल हो पाते हैं।

यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से इस बात के बीच भी अंतर हो सकता है (जो 20 प्रतिशत से अधिक है) कि जो बच्चे प्राथमिक स्कूल के अंतिम ग्रेड में पहुँचते हैं तथा वे बच्चे जो सफलातपूर्वक अंतिम ग्रेड को पास करते हैं, उनके बीच समानुपातिक अंतर हो सकता है। इसके पीछे के कारण में निम्न अधिगम प्राप्ति शामिल हो सकता है; परन्तु निम्न माध्यमिक शिक्षा में सीमित जगहें उपलब्ध होने के कारण कठिन चयन नीतियाँ भी एक कारण हैं। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निम्न माध्यमिक स्कूलों का विस्तार, यू पी ई की उपलब्धि पूरा करने के लिए, ये दोनों ही शर्तें जरूरी हैं।

माध्यमिक स्कूलों पर दबाव

बहुत सारी सरकारों ने नौ वर्षीय सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने को स्वत: प्रतिबद्धता दिखाई है। 203 देशों एवं शासित क्षेत्रों में से 192 ने अनिवार्य शिक्षा के कानून बनाने की सूचना दी है। इनमें से अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत तीन चौथाई देशों ने निम्न माध्यमिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया हुआ है।

माध्यमिक शिक्षा की माँग जोर पकड़ रही है। वर्ष 2004 में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 502 मिलियन बच्चे पंजीकृत हुए जो 1999 की तुलना में तीव्र 14% वृद्धि थी। यह तीव्र वृद्धि अरब राष्ट्रों, उप सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (प्रत्येक में 20% वृद्धि) में देखने को मिली है। प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में अंतरण की दर लगभग सभी क्षेत्रों में 90% रही, केवल उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र को छोड़कर; यहाँ पर दो तिहाई से कम ही बच्चों ने माध्यमिक स्कूलों में अंतरण प्राप्त किया।

माध्यमिक शिक्षण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में लगभग सार्वजनिक है तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, लातीनी अमेरिका तथा कैरेबियन देशों में उच्च है। जबकि इसके विपरीत माध्यमिक सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर एस)[4] उप सहारा अफ्रीका में 30% से नीचे, दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में 51% तथा अरब राष्ट्रों में 66% से नीचे रहा। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी का स्तर बढ़ा है, फिर भी यह प्राथमिक स्तर की अपेक्षा बहुत कम है। दुनियाभर में वर्ष 2004 में माध्यमिक शिक्षा में जी ई आर का औसत 65% था।

दुनियाभर में, उच्च माध्यमिक की अपेक्षा निम्न माध्यमिक में भागीदारी काफी ऊँची रही जोकि 2004 में, क्रमश 51% और 78% जी ई आर रही (चित्र 1.5)। इन दो स्तरों के बीच भागीदारी का यह अंतर (प्रतिशत में) विशेष रूप से पूर्वी एशिया और प्रशांत (42), लातीनी अमेरिका तथा कैरेबियन (31), रही जोकि वैश्विक औसत (27) से दोनों ही क्षेत्रों में अधिक है।

माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश की बढ़ती माँग के बीच अति उच्च असामान्यता रही। सीमांत बच्चे मुख्यत: (गरीब, विशेष मानवजीतीय समूह, विकलांग तथा प्राय: लड़कियाँ) बहिष्कृत हुए। उप सहारा अफ्रीका में, गरीब ग्रामीण एवं औरतों के बीच यह वंचना असमानुपातिक रही। उच्च आय समूह वर्ग के 50% लड़कों ने ग्रेड 7 तक की शिक्षा पूरी की, जबकि (इसी क्षेत्र में) गरीब परिवारों की केवल 4% लड़कियाँ इस ग्रेड तक पहुँच सकीं।

माध्यमिक शिक्षा में केवल एक तिहाई देशों ने ही लैंगिक समानता प्राप्त की है, जबकि दो तिहाई प्राथमिक शिक्षा में प्राप्त कर पाए हैं। परिस्थितियाँ बाध्य कर रही हैं कि सभी स्तरों पर तुरंत ही लिंग संवेदी कार्यक्रमों की रचना की जाए। स्कूलों में होने वाले यौन शोषणों तथा उत्पीड़न के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण प्रशिक्षणों के भेदभाव को मिटाकर लैंगिक जागरूकता के प्रति पुन: संशोधन तथा प्रचलित भ्रांतियों व निषेधों को तोड़ने की दिशा में काम करते हुए आवश्यक अवयवों की एक रणनीति, जो समानता को बढ़ावा देती हो, बनाई जानी चाहिए।

प्राथमिक स्तर की अपेक्षा माध्यमिक स्तर पर लैंगिक असमानता के मापदंड अधिक जटिलतापूर्ण हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे देश हैं जहाँ लड़कियों के लिए किए जाने वाले भेदभाव की कीमत पर माध्यमिक स्तर पर लड़कों को हानि उठानी पड़ती है। दूसरे वे हैं जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अनुपात बहुत कम है (जैसे कि अफगानिस्तान, चाड, गुइनिया, टोगो तथा यमन, जहाँ प्रत्येक 100 लड़कों की तुलना में 50 से भी कम लड़कियाँ माध्यमिक स्तर पर नामांकित होती हैं)। लड़कों की कीमत पर लड़कियों के बीच भेदभाव विकासशील देशों में दिखने के साथ-साथ लातीनी अमेरिकी तथा कैरेबियन देशों में भी दिखता है।

तृतीयक शिक्षा : बढ़ रही है, लेकिन लिंग समानता से दूर

तृतीयक शिक्षा कम से कम दो प्रकार से सर्व शिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्य से जुड़ी है। प्रत्यक्ष तौर पर लिंग समानता लक्ष्य के एक घटक के रूप में

चित्र 1.5 माध्यमिक सकल पंजीयन अनुपात-स्तर एवं क्षेत्र के अनुसार, 2004

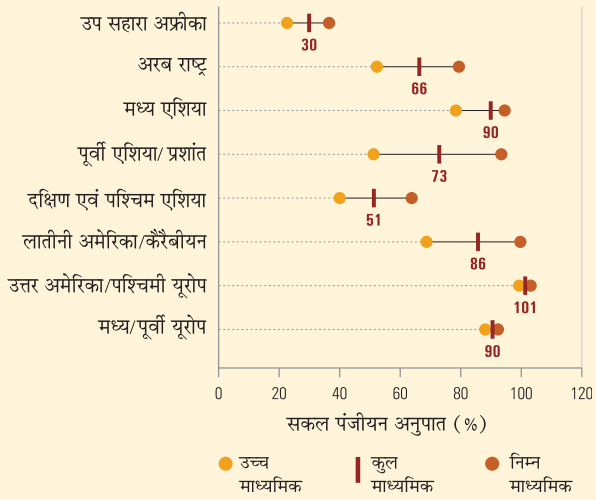

स्रोत : देखें अध्याय 2, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में।

और प्राय: स्कूली शिक्षकों तथा प्रशासकों को उपलब्ध कराने वाले मुख्य प्रदाता के रूप में। दुनियाभर में वर्ष 2004 में लगभग 132 मिलियन छात्र तृतीयक शिक्षा में पंजीकृत हुए थे जोकि 1999 की तुलना में 43% बढ़े हुए थे। इस वृद्धि का तीन चौथाई भाग विकासशील देशों से था। इसमें अकेले चीन 60% वृद्धि के लिए हिस्सेदारी रखता है। इस स्तर पर जी ई आर 24% है लेकिन दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (10%) तथा उप सहारा अफ्रीका में (5%) यह बहुत निम्न रहा।

माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश की बढ़ती माँग के बीच अति उच्च असामान्यता रही।

तृतीयक स्तर पर लैंगिक समानता केवल एंडोरा, साइप्रस, जार्जिया, मैक्सिको तथा पेरु में विद्यमान है। विकसित एवं संक्रमणशील देशों में इस स्तर पर औरतों की संख्या पुरूषों से अधिक रही। विकासशील देशों में कुछ सुधार के बावजूद 1999 से 2004 के बीच पुरुषों की अपेक्षा औरतों की भागीदारी कम ही रही। वर्ष 2004 में प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में औसतन 87 औरतें पंजीकृत हुई जो कि 1999 की 78 की तुलना में थोड़ा ऊपर थी। तृतीयक शिक्षा के विषयों में भी जैसे कि शिक्षा एवं समाज विज्ञान की तुलना में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में उनकी भागीदारी असमानुपातिक ही रही जिसके परिणामस्वरूप समाज में लैंगिक असमानता प्रबल रहती है। फिर चाहे वह नौकरी के सुअवसर हों, समान वेतन की हो या फिर/और प्रबंधकीय पदों तक पहुँच की हो।

शिक्षकों में निवेश तथा छात्र कैसे बेहतर अधिगम कर सीख सकते हैं, का मूल्यांकन करना

इस रिपोर्ट का प्रत्येक संस्करण यह विश्लेषित करने का प्रयास करता है कि शिक्षा प्रणाली कितने बेहतर ढंग से बच्चों की सेवा कर रही है। सच्चाई यह है कि बच्चों की शुरूआती स्कूल में पढ़ाई छूटना या आधारभूत साक्षरता और साधारण गणना कौशल प्राप्त न कर पाना अंशत: खराब शिक्षा श्रेणी को बिंबित करती है। शिक्षकों के बारे में सूचना तथा छात्र शिक्षण उपलब्धि मूल्यांकन के इन दो पहलुओं को देखते हैं कि दुनिया भर में कक्षाओं के भीतर क्या हो रहा है।

4 आयु को ध्यान में न रखते हुए विशिष्ट स्तर की शिक्षा में कुल पंजीयन (नामांकन), इस स्तर की शिक्षा से अधिकृत आयु समूह के तदनुरूप जनसंख्या के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

शिक्षक संख्या, प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरण को संबोधित करना

शिक्षा की गुणवत्ता के एक संकेत के रूप में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या का प्राय: उपयोग किया जाता है। छात्र-शिक्षक अनुपात (पी टी आर एस) वर्ष 1999 से 2004 के बीच घटा है, केवल दक्षिण वं पश्चिम एशिया को छोड़कर। 2004 में, उपलब्ध आँकड़ों वाले 174 देशों में 84% में प्राथमिक स्तर पर प्रति शिक्षक 40 से कुछ कम छात्र का औसत था जबकि तीस देशों में शिक्षक छात्र औसत 40:1 से अधिक था जोकि अधिकतर उप सहारा अफ्रीकी देश थे, लेकिन पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र एवं दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में अनेक देश थे। उन देशों में शिक्षक छात्र औसत अधिक हो रहा है जहाँ प्राथमिक स्तर पर पंजीयन में वृद्धि हो रही है। कांगो, इथोपिया तथा मलावी में प्रति शिक्षक 70 छात्र का औसत पाया गया है।

अधिकतर देशों में; प्राथमिक स्कूल शिक्षक बहुतायत में स्त्रियाँ हैं

अधिकतर देशों में; प्राथमिक स्कूल शिक्षक बहुतायत में स्त्रियाँ हैं, यद्यपि इसमें भी अपवाद हैं। अफगानिस्तान, बेनिन, चाड और टोगो आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर लड़कों के पक्ष में भारी मात्रा में लिंग भेद विद्यमान है। प्राथमिक शिक्षक कार्यबल में औरतों की भागीदारी पाँच में से एक या इससे भी कम है। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों के रूप में औरतों की भागीदारी काफी कम है। विशेष रूप से तृतीयक स्तर पर, जहाँ शिक्षण सर्वाधिकता से एक पुरूष व्यवसाय है।

उपलब्ध आँकड़ों वाले इकतालीस देशों में से लगभग आधों में 1999 से 2004 के बीचें प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के प्रतिशत में थोड़ी सी वृद्धि हुई। बहामास, नामीबिया तथा रवांडा में यह सुधार (60% से अधिक बढ़ोत्तरी) ध्यान देने योग्य था। अभी भी 2004 में 76 देशों के आँकड़ों में प्राइमरी स्तर पर तथा 59 में माध्यमिक स्तर पर यह दर्शाते हैं कि आधे देशों में 20% (पाँचवा हिस्सा) शिक्षक शिक्षणात्मक प्रशिक्षण से रहित हैं। उदाहरण के रूप में लेबनान, नेपाल तथा टोगो जैसे देशों में, उनके राष्ट्रीय मानक के अनुसार आधे से कम ही शिक्षक प्रशिक्षित हैं।

शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण एक चिंता का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहाँ प्राथमिक स्कूल छात्रों की जनसंख्या अभी बढ़ रही है। बांग्लादेश, इथोपिया, पाकिस्तान तथा सउदी अरब में संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 65000 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। उप सहारा अफ्रीकी देश वर्ष 2015 तक यू पी ई के लक्ष्य को पाने हेतु लगभग 1.6 मिलियन और शिक्षक भरती करेगा जबकि अन्य देश भी छात्र शिक्षक औसत 40:1 को घटाने हेतु ऐसा करेंगे।

शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की प्रतिष्ठा एवं सेवा शर्तों से निकट संबद्ध है। हाल ही में अनेक उप सहारा अफ्रीकी तथा दक्षिण एशियाई देशों[5] में शिक्षण-उत्प्रेरण अनुसंधान परियोजना इस नतीजे पर पहुँची है कि अधिकतर कम आय वाले देशों द्वारा शिक्षक उत्प्रेरण संकट झेला जा रहा है। शहरी स्कूलों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करना अत्यंत कठिन है। इस अध्ययन ने शिक्षण की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए मुख्य रणनीतियाँ अभिज्ञान की हैं, जो कि निम्नवत हैं-

- बिजली एवं पानी की सुविधा सहित अच्छा आवास बहुत हद तक अत्यंत लागत प्रभावी उपाय है जो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों को आकर्षित एवं रोके रख सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए विशेष भत्ता उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए औचित्यपूर्ण क्षतिपूरक साबित होना चाहिए।
- ग्रामीण स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक कर्मियों को जल्दी-जल्दी पदोन्नति दी जानी चाहिए और अथवा उन्हें अपनी योग्यता को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक पूर्ण पहुँच के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- शिक्षकों को स्कूल के प्रबंधकों, अभिभावकों तथा व्यापक समुदाय के साथ निर्णय-प्रक्रिया एवं संवाद में व्यापक बोध के साथ सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

अनेक लातीनी अमेरिकी देशों में प्रोत्साहन रणनीतियां विद्यमान हैं। बोलिविया ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों का वेतन बढ़ा देता है। चिली तथा मैक्सिकों ने कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था प्रस्तुत की है; चिली में शुरूआती साक्ष्य दर्शाते हैं कि भागीदारी स्कूलों में उच्च छात्र उपलब्धि पाते हैं। एल-सल्वाडोर एवं होंडूरास में शिक्षकों को अपने स्कूलों के बारे में निर्णय लेने के कारण व्यापक सफलता मिली है जोकि विकेन्द्रीकरण एवं स्कूल आधारित प्रवर्धन नीतियों का परिणाम है। ब्राजील में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों को अतिरिक्त शिक्षकों की सेवाएं लेने एवं प्रशिक्षण करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है।

शिक्षकों की संख्या बढ़ाने तथा शिक्षण की वास्तविक दुनिया से प्रशिक्षण को जोड़ने के लिए अनेक देशों ने संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा कार्य व्यवहारिकता पर जोर दिया है। क्यूबा में, सभी पूर्व प्रशिक्षण स्कूल आधारित हैं। इस प्रकार की प्रणाली के लिए पर्याप्त स्कूलों की आवश्यकता होती है जो प्रशिक्षण पर्यावरण के उद्देश्य को पूरा कर सकें तथा परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए। अनेक उप सहारा अफ्रीकी देशों में लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम एक प्रवृत्ति है। गुइनिया ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को 1998 में तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष का कर दिया था और तब से प्रतिवर्ष 1500 से अधिक शिक्षक प्रतिवर्ष आकृष्ट किए हैं। जबकि सुधार से पहले यह संख्या 200 शिक्षक थी। सेवा पूर्व प्रशिक्षण की लंबाई घटाना शिक्षकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। अधिक से अधिक देश छोटे एवं अधिकाधिक स्कूल आधारित प्रशिक्षण की दिशा में बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में अब प्रशिक्षु शिक्षक अपने प्रशिक्षण का दो तिहाई समय स्कूल में बिता सकते हैं।

अधिगम (शिक्षण) के परिणामों के राष्ट्रीय मूल्यांकन की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति

वर्ष 1990 के बाद से अधिक से अधिक सरकारों ने छात्रों के सीखने को आँकलन तथा एक समय के बीच अधिगम परिणामों की प्रगति को मापने की दिशा में उपाय अपनाए हैं। राष्ट्रीय अधिगम मूल्यांकन सरकारों को उनकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता एवं सक्षमता के बारे में संभावित उपयोगितापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते

5 घाना, भारत, लेसोथो, मलावी, सियेरा-लियोन, संयुक्त गणराज्य तंजानिया तथा जांबिया।

हैं। वे प्राय: चुने हुए स्कूल विषयों पर राष्ट्रीय परिभाषित मानकता पर छात्र की अधिगम का मूल्यांकन उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि इन मूल्यांकनों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण रूप से वैविध्यपूर्ण हो सकती है।

अधिगम का अंतर्राष्ट्रीय आँकलन, जो 1960 की शुरूआती स्थिति की ओर ले जाता है, वैश्विक प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जिसमें अधिकाधिक देश एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। वर्ष 1989 के बाद से अधिकाधिक मध्यम एवं निम्न आय वाले देशों ने विभिन्न मूल्यांकनों में हिस्सा लिया है। यह प्रक्रिया लातीनी अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका तथा प्रशांत क्षेत्रीय द्वीपों में छात्रों की उपलब्धि के क्षेत्रीय मूल्यांकन के विकास के रूप में फैल रहा है।

हाल ही में पार-राष्ट्रीय अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि छात्रों की उपलब्धि लगातार उन परिवारों के छात्रों में कम निष्पादन वाली है जो गरीब हैं एवं सांस्कृतिक घेरे से बाहर हैं। अपेक्षाकृत उन परिवारों के बच्चों के जो अच्छे परिवार है और सांस्कृतिक मुख्य धारा में हैं। एक उच्च किस्म के शैक्षिक वातावरण (पुस्तकों, अखबारों, लिखित सामग्री तक आसान पहुँच) वाले घर के छात्रों ने महत्वपूर्ण रूप से उपलब्धि पाई है। गरीब परिवारों एवं लाभ रहित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता अधिक महत्व रखती है।

अधिगम एवं जीवन कौशल : बेहतर निगरानी हेतु मार्ग

अधिगम एवं जीवन कौशल कार्यक्रम के वितान के अंतर्गत व्यापक एवं विविध दायरे के प्रदाता एवं क्रियाकलाप आते हैं जो निगरानी को प्रस्तुत करना कठिन बनाते हैं। अनिवार्यत: सर्व शिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्य 3 उन छोटे बच्चों एवं वयस्कों को अधिगम अवसर उपलब्ध कराने के बारे में है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से अपवर्जित रह गए हैं। कुछ देश औपचारिक प्रणाली से बाहर अधिगम क्रियाकलापों को पाने के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं। एक अनौपचारिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रतिरूप यूनेस्को तथा उसके सदस्य संस्थानों द्वारा बनाया गया था, जिसे अनेक देशों में प्रायोगिक तौर पर चलाया गया था। जिनमें कंबोडिया भारत, जोर्डन तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया आदि शामिल थे।

साक्षरता : लक्ष्य अभी भी दुर्गाह्य है

वर्ष 2006 की रिपोर्ट में साक्षरता ने विस्तृत व्याप्ति पाई है। चूँकि परंपरागत मापदंड एक व्यक्ति की साक्षरता कौशल एवं सक्षमता को सीधे नहीं जाँच पाते हैं। अत: वे एक ऐसी तस्वीर उपलब्ध कराते हैं जो चुनौतियों के वास्तविक पैमाने को नहीं प्रतिबिंबित कर पाते हैं। इन परम्परागत मापदंडों के अनुसार लगभग 781मिलियन वयस्क, जिनमें से दो तिहाई औरतें हैं जो न्यूनतम साक्षरता कौशल से वंचित हैं। इनमें से भारी संख्या में दक्षिण एवं पश्चिम एशिया, उप सहारा अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों में रहते हैं। असीम संख्या में निरक्षर लोग लगातार पहले दो क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के बिना सघन उपाय के साथ प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के फैलाव वर्ष 2015 तक वैश्विक निरक्षरों की संख्या में केवल 100 मिलियन की कमी ही आ पाएगी (सारणी 1.1)।

सारणी 1.1 वर्ष 2002–2004 अनुमानित साक्षरता दर (15 वर्ष+) तथा लिंग समानता सूचकांक (जी पी आई), तथा 2015 के लिए पूर्वानुमान

	2000-2004		2015	
	साक्षरता दर %	जी पी आई	साक्षरता दर %	जी पी आई
	योग	एफ/एम	योग	एफ/एम
विश्व	82	0.89	87	0.92
उप सहारा अफ्रीका	61	0.77	67	0.84
अरब राष्ट्र	66	0.72	79	0.82
मध्य एशिया	99	0.99	100	1.00
पूर्वी एशिया/प्रशांत	92	0.93	96	0.96
पूर्वी एशिया	92	0.93	96	0.96
प्रशांत	93	0.98	93	0.99
दक्षिण एवं पश्चिम एशिया	59	0.66	68	0.74
लातीनी अमेरिका/ कैरीबियन	90	0.98	94	0.99
कैरीबियन	70	1.00	97	1.01
लातीनी अमेरिका	90	0.98	94	0.99
उत्तरी अमेरिका/प. यूरोप	99	1.00	100	1.00
मध्य/ पूर्वी यूरोप	97	0.97	98	0.98

स्रोत : देखें अध्याय 2; पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में

सभी क्षेत्रों में साक्षरता दर में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी अपेक्षाकृत धीमी गति है जो दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (59%), उप सहारा अफ्रीका (61%), अरब राष्ट्र (66%), तथा कैरीबियन (70%),में है। वर्ष 2015 तक साक्षरता लक्ष्य पाना, विशेष रूप से 22 देशों में कठिन ही रहेगा क्योंकि वहाँ की साक्षरता दर 60% से नीचे है। 10 देशों में प्रत्येक में 10 मिलियन निरक्षर हैं और 1990 से केवल आधे देशों ने अपनी असीम संख्या को थोड़ा घटाया है। साक्षरता में लैंगिक आयाम अभी भी अपरिवर्तित हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में प्रत्येक 100 साक्षरों के लिए केवल 66 औरतें साक्षर हैं जबकि अरब राष्ट्रों में यह 72% तथा उप सहारा अफ्रीकी देशों में यह 77% है। सभी क्षेत्रों में, 1999 के बाद युवा साक्षरता दर (15 से 24 आयु वर्ग) में बढ़ोत्तरी हुई हैं। जिसके परिणामस्वरूप उप सहारा अफ्रीकी देशों को छोड़कर साक्षर युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

शिक्षा योजनाएं : सीमांत समूहों का सम्मिलन

सर्व शिक्षा (ई एफ ए), जैसा कि विश्व शिक्षा मंच पर कल्पित की गई थी, वह एक सम्मिलित उपागम थी; जिसमें जोखिम युक्त या नाजुक एवं लाभ रहित समूह को विशेष ध्यान देने के लिए अनेक लक्ष्यों में बाँटा गया है। कम माँग, गैर लचीले प्रावधान तथा खराब गुणवत्ता अनेक लोगों के लिए अपवर्जन का चक्र पैदा करती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए उन प्रयासों की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा की गुणवत्ता, लचीलेपन तथा औचित्यता को सुधारें और दूसरी ओर परिवारों से स्कूली खर्चों के बोझ को घटाएं। पैंतालीस देशों की राष्ट्रीय सर्व शिक्षा योजना का एक विश्लेषण, जिसमें 20 वह देश हैं जिनके सबसे अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यह दर्शाता है कि सभी कुछ न कुछ नाजुक समूहों पर ध्यान देते हैं। अधिकतर देशों ने

गरीब एवं सांस्कृतिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चे समृद्ध परिवार के बच्चों की अपेक्षा कम बेहतर प्रदर्शन करते हैं

दुनियाभर में शिक्षा पर सर्वजनिक व्यय में 1999 के बाद से बढ़ोतरी हुई हैं

लड़कियों तथा उस जनसंख्या को प्राथमिकता देने हेतु पहचाना है जो दूरदराज के ग्रामीण घरों में रहते हैं। लातीनी अमेरिकी देशों ने विशेष रूप से मानव जातियों एवं भाषाई अल्प संख्यकों को चिंहित किया है। दूसरी ओर अनाथों, एच आई वी पाजिटिव तथा यौन शोषित बच्चे विशेष ध्यान हेतु नाममात्र के लिए स्पष्टीकृत किए गए हैं। बाईस देशों ने स्कूल की पढ़ाई की लागत को समाप्त करने या घटाने के उपायों की योजना बनाई है जिसमें स्कूली फीस समाप्त करना करना तथा शिक्षण सामग्री व यूनीफार्म उपलब्ध कराना शामिल है। अट्ठारह देशों ने स्त्री शिक्षकों को बढ़ाने के लिए उपाय सूचीबद्ध किए है और यह सुनिश्चित किया है कि स्कूल कन्या मैत्री हों। पन्द्रह देशों ने स्कूल की संख्या में विस्तार किया है जिनमें चाहे वे सचल स्कूल, ग्रामीण स्कूल हो या फिर अन्य प्रकार के स्कूल हो, प्राथमिकता दी हैं। अपवर्जित बच्चों के लिए (25 देशों में) शिक्षा कार्यक्रम सामान्य रूप से बढ़े हैं; उदाहरण के लिए, सेनेगल और ग्वाटेमाला, जहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साक्षरता कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो जल्दी छोड़ने वालों को ग्रहण करने का एक अवसर देता है। अधिकतर लातीनी अमेरिकी, 8 देशों ने स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषा को प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। सूचना अभियान ने अभिभावकों को लक्षित किया है तथा आठ देशों की योजना में व्यापक समुदाय को विशिष्टीकृत किया गया है।

जो सरकार व्यापकता से अपवर्जित होने के बहुसंख्य कारणों एवं अधिगम बाधाओं को निपटाती है, वे व्यापक रूप से सुनिश्चित करेंगी, किस प्रकार से सर्व शिक्षण की प्राप्ति के लिए ये देश करीब आते हैं। बाक्स 1.2 कुछ सामान्य नीतियों एवं उन बाधाओं को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों को संक्षेपीकृत करता है

शिक्षा पर घरेलू व्ययः व्यापक चुनौतियों वाले देशों के लिए अपर्याप्त

वर्ष 1999 से दुनिया भर में शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है। उपलब्ध आँकड़ों वाले 106 देशों में से, लगभग दो तिहाई देशों ने 1999 और 2004 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद से सरकारी शिक्षा व्ययों

बाक्स 1.2 अंतर्वेशन प्रोत्साहन हेतु नीतियाँ

नीति लक्ष्य	कार्यक्रम – उदाहरण
स्कूल की पढ़ाई की लागत घटाना: नब्बे से अधिक देशों में प्राथमिक स्कूल प्रवेश में प्रत्यक्ष शिक्षा लागत एक बाधा है,	बुरुंडी ने 2005 में प्राथमिक स्कूल शुल्क समाप्त कर दिए। स्कूल के पहले दिन ही 500,000 अतिरिक्त बच्चे पंजीयन के लिए स्कूल आए।
अनाथ एवं एच आई वी/ एड्स के प्रभाव से प्रभावित नाजुक बच्चों को समर्थन	स्वाजीलैडं में, जहाँ विश्व में सबसे अधिक एच आई वी/एड्स अभिभावी रहते हैं, सरकार ने 2004 में अनाथ एवं अन्य सुकुमार बच्चों के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में भाग लेने हेतु 7.5 मिलियन यू एस डालर प्रदान किए। पंजीयन अभी भी स्थिर है और अधूरी शिक्षा छोड़ने वालों में कमी आई।
नकद प्रोत्साहन द्वारा बाल श्रम की माँग को घटाना	ब्राजील के **बोलसा फैमिलिया** (पूर्वनाम बोलसा इस्कोला) में एक कार्यक्रम उन परिवारों को आय समर्थन देता है जिन्हें बच्चों को स्कूल भेजने की शर्त मंजूर है। यह कार्यक्रम 5 मिलियन अधिक बच्चों से तक पहुँच रहा है।
लचीले शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा बालश्रम की आवश्यकता को घटाना	भारत के आंध्र प्रदेश में **बालज्योति** कार्यक्रम के द्वारा, राज्य 250 स्कूल स्लम क्षेत्रों में चलाता है। इस राज्य में सर्वाधिक कामकाजी बच्चे हैं। इन स्कूलों में 31000 बच्चे पढ़ते हैं। यह कार्यक्रम सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग का सफल उदाहरण है।
माध्यमिक स्कूलों में कन्याओं की उपस्थिति बढ़ाकर लिंग समानता सुनिश्चित करना।	**गांबिया गर्ल्स' स्कालरशिप ट्रस्ट फंड** पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत ट्यूशन फीस, किताबें तथा परीक्षा शुल्क लगभग स्कूल की एक तिहाई लड़कियों को, जो निम्न पंजीयन से आई हैं, प्रदान करता है। इनमें 10% लड़कियाँ विज्ञान, गणित तथा टेक्नालोजी में सर्वोत्तम हैं। 16000 से अधिक लड़कियाँ हिस्सा ले रही हैं।
जिन युवाओं व प्रौढ़ों से औपचारिक स्कूलिंग छूट गई है उन्हें अनौपचारिक शिक्षा अवसर प्रदान करना	होंडूरास के **एजूकेटोडोस** कार्यक्रम उन छात्रों एवं वयस्कों को लक्ष्य करता है जिन्होंने नौ वर्षीय प्राथमिक शिक्षा कोर्स पूरा नहीं किया है। आधा मिलियन छात्रों को प्राथमिक स्कूल कार्यक्रम में नामांकित किया गया है। अधिगम केन्द्रों में आसान पहुँच उपयुक्त विषयवस्तु, लचीला कार्यक्रम तथा सुदढ़ सामुदायिक समर्थन पर प्रकाश डाला जाता है।
विकलांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशन शिक्षा उपलब्ध कराना	उरुग्वे में एक विशिष्ट समावेशन शिक्षा फंड सामान्य स्कूलों को विकलांग बच्चों के साथ समिश्रण में मदद प्रदान करते हैं। इससे लगभग 39000 बच्चों ने लाभ प्राप्त किया है।

को बढ़ाया है। लगभग 20 देशों में यह वृद्धि 30% या उससे अधिक दर्ज की गई है। यह वैश्विक प्रवृत्ति क्षेत्रीय भिन्नताओं से आवृत है। लगभग 41 देशों में सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत घटा है। विशेष रूप से, लातीनी अमेरिकी और दक्षिण तथा पश्चिम एशिया में (जहाँ तीन क्षेत्रों में आखिरी क्षेत्र में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है)। आज भी सर्व शिक्षा की विशाल चुनौती वाले कई देशों में शिक्षा पर व्यय अभी भी अपर्याप्त है। नाइगर, पाकिस्तान इसके उदाहरण है, जहाँ शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% से भी कम खर्च होता है। (चित्र-1.6)।

सर्व शिक्षा के लिए एक सरकार की प्रतिबद्धता उसके द्वारा शिक्षा से संबंधित अन्य बजटीय खर्चों के लिए अर्जित भाग के द्वारा भी मापी जा सकती है। 36 देशों के लिए 1999 एवं 2004 के उपलब्ध आँकड़ों से, उत्साहवर्धक रूप से इनमें तीन चौथाई का कुल सरकारी शिक्षा खर्च में बढोत्तरी देखी गई । इसका एक रोचक उदाहरण संयुक्त गणराज्य तंजानिया का है। वर्ष 2001 में सरकार ने स्कूलों की फीस खत्म कर दी जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के पंजीयन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। वहां शिक्षा पर वर्ष 2000 में सरकारी खर्च 2.1% सकल घरेलू उत्पाद से बढ़कर वर्ष 2004 में 4.3% पहुँच गया।

2004 में, अधिकतर जिन देशों के आँकड़े उपलब्ध हैं, वे अपने कुल शिक्षा खर्च का 50% से भी अधिक प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जी एन पी) के रूप में; जिन 90 देशों के आँकड़े उपलब्ध हैं; वे अपनी राष्ट्रीय आय का 2% से भी कम हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। यह परिदृश्य दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के तीन देशों तथा उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के 16 देशों का है जो क्षेत्र अभी भी यू पी ई प्राप्त करने में कुछ दूर हैं।

जैसे-जैसे माध्यमिक शिक्षा विस्तृत होती है तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बीच फंड की प्रतियोगिता बहुत हद तक बढ़ जाती है। अनेक विकासशील देश इनके बीच सही संतुलन बना पाने में स्वयं को संघर्षरत पाते हैं। बिना पर्याप्त माध्यमिक शिक्षा अवसर के सर्वशिक्षा तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अच्छी किस्म की प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौम प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे माता-पिता अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में इस उम्मीद से भेजते हैं कि वे माध्यमिक स्कूल में भी उसकी शिक्षा को बढ़ाएंगे। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर उच्च खर्चों के प्रति उन देशों में अवबोध है जो यू पी ई को प्राप्त कर चुके हैं या वे प्राप्ति के करीब हैं। हालांकि जिन देशों में प्राथमिक शिक्षा भी अभी सार्वभौम नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश व नेपाल, वहां प्राथमिक शिक्षा खर्च का हिस्सा 1999 की अपेक्षा कम हो गया है।

कोरिया गणतंत्र ने अपनी माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, किसी अन्य क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली पर निवेश को दाँव पर लगाए बिना किया है। सरकारी खर्चों को टिकाऊ बनाते हुए गरीब बच्चों को पश्च-प्राथमिक शिक्षा में समर्थित करने हेतु लाटरी जैसे प्रोत्साहक प्रयास किए हैं तथा देश की शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के सम्मिलन के साथ, एक संतुलित नियामक ढांचा देश की शैक्षिक उपलब्धि की विशिष्टताएं हैं। बांग्लादेश व दक्षिण अफ्रीका ने माध्यमिक शिक्षा में एक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी विकसित की है। बांग्लादेश में; प्रोत्साहक नीतियाँ लाभरहित परिवारों के बच्चों को भोजन एवं वजीफा तथा गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

चित्र 1.6. 2004 में, वे देश जो अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जी एफ पी) का 3% से कम शिक्षा पर खर्च करते हैं।

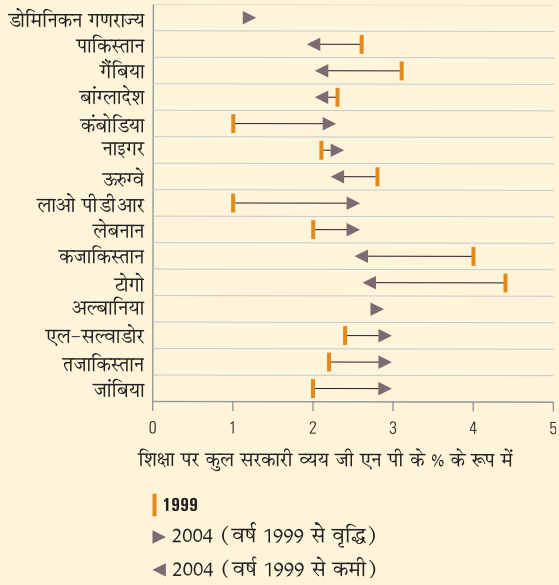

स्रोत : देखें अध्याय 3, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में

प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियाँ बहुकोणीय हैं: उदाहरण के लिए, वित्तीय प्रोत्साहनों को निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास से जुड़ा होना चाहिए। यह बात मायने रखती है कि सरकार ने विशिष्ट समूह को लक्षित करने के लिए क्या सत्प्रयास किये हैं। स्थानीय समुदायों तथा नागरिक समितियों के साथ समन्वय रचनात्मक क्षमता से पूर्ण होते हैं। वित्तीय प्रयासों में वह ताकत होती है कि विशिष्ट बाधाओं से पार पाया जा सके। पर्याप्त बजट संबंधी समर्थन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भारत में कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा की कीमत पर मिड डे मील (दोपहर का भोजन) तथा विभिन्न स्वरूपों में लड़कियों की शिक्षा को बजट में डाला है। यहाँ पर लाभरहित बच्चों, युवाओं, तथा वयस्कों की आवश्यकताओं को निश्चित तौर पर सावधानी पूर्वक आँकलित किया जाना चाहिए। बहुत सारे देशों में जहाँ प्राथमिक स्कूलों में पंजीयन बढ़ रहा है। वहाँ अब पहले से भी यह अधिक महत्वपूर्ण है कि अच्छी गुणवत्ता वाले उन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाए जो समानता प्रभावशीलता तथा असर के लिए निगरानी रखे। सफलतापूर्ण कार्यक्रम वे हैं जो शिक्षा प्रणाली में क्रमबद्ध पुनर्गठन के साथ समिश्रित हस्तक्षेप करें ताकि सभी बच्चों के लिए आसान पहुँच रहे और बेहतर अधिगम के अच्छे परिणाम मिलें। ■

प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियाँ बहुकोणीय हैं

भाग–II. सर्व शिक्षा (ई एफ ए) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: वचनबद्धताओं पर अच्छा काम करना

- प्राथमिक शिक्षा विस्तार हेतु मदद, परन्तु आवश्यकताओं से काफी कम
- पाँच दानदाता द्विपक्षीय शिक्षा सहायता की विशाल भागीदारी के लिए जिम्मेदार
- सभी देशों में दानदाताओं की उपस्थिति असमान
- क्षेत्रीय वितरण में वैषम्यता है
- सहायता अंतराल वृद्धि आँकलित करता है
- तीव्र मार्गीय प्रयास जोर पकड़ते हैं। परन्तु अभी तक वैश्विक संघात असर नहीं डाल पाए हैं।

कार्यवाही के लिए डाकार संरचना (ढांचे) ने एक संघात (इंपैक्ट) द्वारा यह सुनिश्चित किया कि सबके लिए अर्थात् सर्व शिक्षा (ई एफ ए) के लिए कोई भी देश पूरी तरह गंभीरता से प्रतिबद्ध नहीं है। अत: वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति से संसाधनों की कमी के कारण विफल हो जाएंगे। यद्यपि 2000 से प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता बढ़ी हैं तथा अतिरिक्त समर्थन भी प्रतिभूतित है, यह राशि वार्षिक 11 बिलियन यू एस डालर से बहुत कम है जो कि सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा तथा शैशवकालीन एवं प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के विस्तार की लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित है।

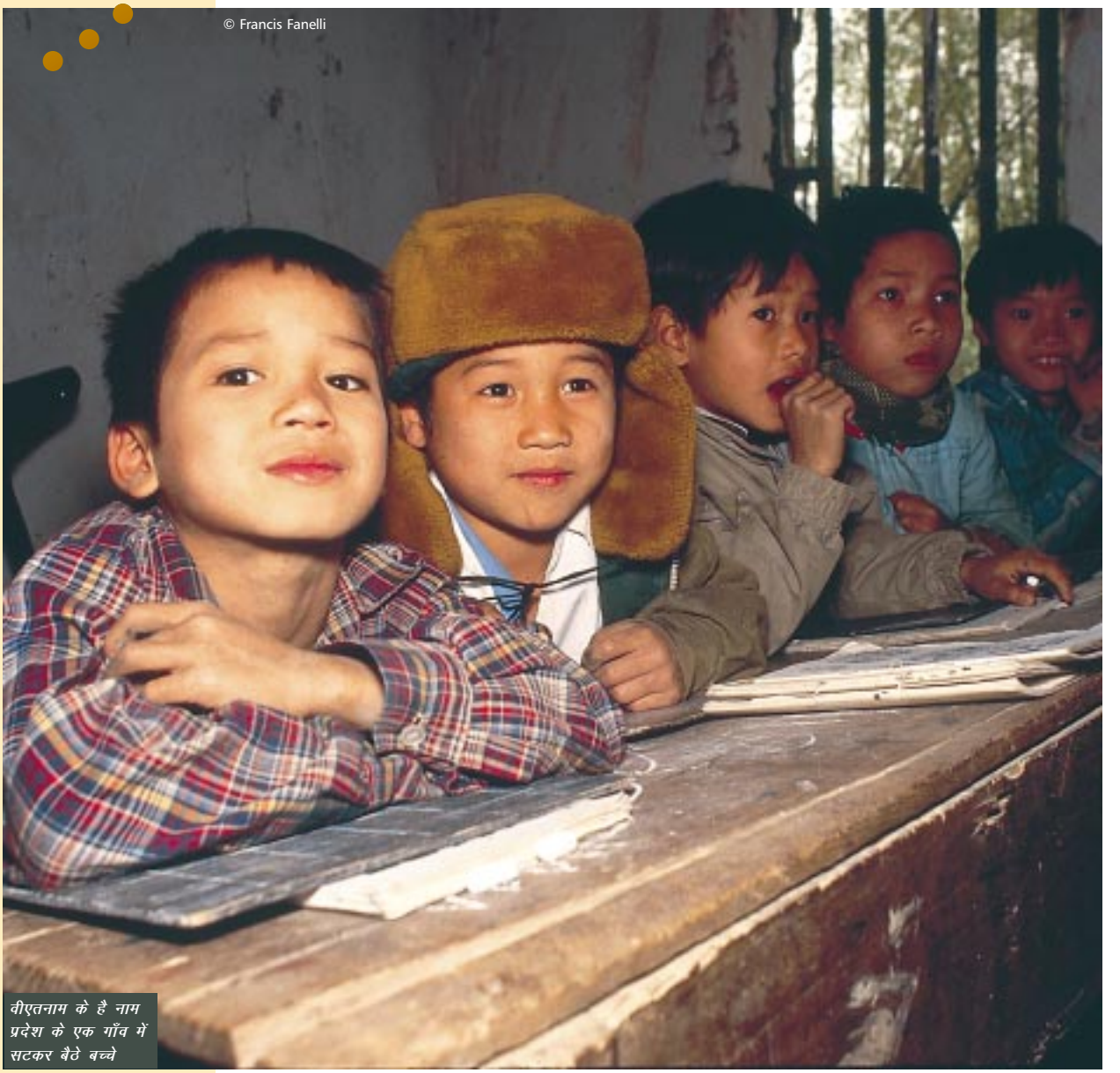
© Francis Fanelli

वीएतनाम के है नाम प्रदेश के एक गाँव में सटकर बैठे बच्चे

शिक्षा हेतु सहायताः सही शिक्षा दिशा में बढ़ रही है

कुल सहायता: 1990 के दशक के, बीच में असफल होने के बाद आफिसियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओ डी ए) का वास्तविक स्तर 1995 और 2000 के बीच स्थिर हो पाया और इसके बाद विस्तारित हुआ। वर्ष 2000 से 2004 के बीच कुल सहायता प्रवाह 57 बिलियन यू एस डालर से बढ़कर 72 बिलियन यू एस डालर जा पहुँची[6]। जिसके साथ द्विपक्षीय दानदाता इस राशि के लगभग तीन चौथाई हिस्से के लिए सीधे जिम्मेदार थे। कम आय वाले देशों के रूप में अभिचिह्नित 72 देशों में जाने वाली सहायता राशि का हिस्सा लगभग 46% पर स्थिर रहा, यद्यपि इनका अलग-अलग हिस्सा अति गरीब देशों के लिए भिन्न था। न्यूनतम विकसित (एल डी सीज) 51 देशों की सहायता को 26% से बढ़कर 32% कर दिया गया। दोनों ही वर्षों में उप सहारा अफ्रीकी देशों को कुल सहायता राशि का एक तिहाई हिस्सा दिया गया और दक्षिण तथा पश्चिम एशिया भारी वृद्धि के साथ लाभान्वित हुए, जैसा कि इराक के लिए किया गया। कुल सहायता में कर्ज सहायता राशि 10% तक बढ़ गई; यह कई न्यूनतम विकसित देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और इनमें से बहुतायत देश उप सहारा अफ्रीका से थे।

शिक्षा हेतु सहायता: सभी विकासशील देशों में कुल प्रत्यक्ष शिक्षा सहायता राशि में 85% तक विस्तार हुआ जो वर्ष 2000 में 4.6 बिलियन यू.एस. डालर से बढ़कर 2004 में 8.5 बिलियन यू एस डालर हो गई। यहाँ तक कि कम आय वाले देशों में उच्च वृद्धि प्राप्ति अन्तप्रवाह देखा गया जो 2.5 बिलियन यू एस डालर से लगभग दो गुना 5.5 यू एस डालर हो गयी और यह सारी शिक्षा सहायता का दो तिहाई हिस्सा बनती थी (सारणी 2.1)। सहायता की कुल राशि में शिक्षा के लिए दिया गया हिस्सा विशिष्ट क्षेत्रों में वर्ष 2000 में 10.6% से बढ़कर वर्ष 2004 में 13.6% तक जा पहुँचा।

प्राथमिक शिक्षा हेतु सहायता: प्राथमिक शिक्षा को कुल मिलाकर शिक्षा में बढ़ाई गई पूरी सहायता से लाभ पहुँचता है। सर्वोतम अनुमान या आँकलन यह दर्शाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सहायता (इसमें सहायता का वह भाग भी शामिल है जिसे स्तर के अनुसार विशिष्टीकृत नहीं किया गया है) वर्ष 2000 में 2.1 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2004 में 3.9 बिलियन यू एस डालर हुई जो सभी विकासशील देशों को मिलाकर दी गई और इसके साथ ही 1.4 बिलियन यू एस बढ़ाकर 3.0 बिलियन डालर निम्न आय समूह के देशों को अकेले दिया गया। दोनों ही प्रकार के देशों में कुल शिक्षा सहायता में से प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा लगातार स्थिर ही रहा। जो सभी विकासशील देशों में ठीक आधा तथा निम्न आय देशों मैं आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा रहा।

इस तस्वीर को परिपूर्ण करने के लिए, सहायता समानता में बजट समर्थन भी एक घटक है। किसी विशिष्ट परियोजना, कार्यक्रम या क्षेत्र के लाभान्वित करने की अपेक्षा इस प्रकार की मदद सीधे हिस्सेदार सरकारों के राष्ट्रीय कोष में पहुँचा दी जानी चाहिए। वर्ष 2004 में, सभी विकासशील देशों को बजट समर्थन की राशि 4.7 बिलियन यू एस डालर थी। यह अनुमानित किया गया कि यह 20% समर्थन शिक्षा के लिए जाता है और इसका आधा प्राथमिक शिक्षा द्वारा ग्रहण किया जाता है।

6. सभी सहायता राशि आँकड़े 2003 के स्थिर मूल्य पर आधरित हैं।

इन सभी स्रोतों से आने वाली, शिक्षा के लिए सहायता, अनुमानत: सभी देशों में बढ़ी है जो वर्ष 2000 में 5.6 विलियन यू एस डालर से बढ़कर वर्ष 2004 में 9.5 बिलियन यू एस डालर हो गई। इसमें कुल वृद्धि 3.4 विलियन यू एस डालर से 6.4 विलियन यू एस डालर हुई। वर्ष 2004 में सभी विकासशील देशों में कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा के 4.4 बिलियन डालर खर्च किए गए और इसे 3.4 बिलियन यू एस डालर निम्न आय समूह में खर्च किया गया।

यह ऊपर की ओर बढ़ती प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सर्व शिक्षा (ई एफ ए) एजेंडा के लिए दानदाता तथा ग्रहण करने वाले देश दोनों ही का पूरा ध्यान केन्द्रित है। 1990 के दशक के अंतिम चरण में प्रमुख बहुस्तरीय दानदाताओं ने सरकारों को गरीबी उन्मूलन रणनीति दस्तावेजों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया ताकि दानदाताओं से कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रति परिचर्चा कर सकें। इस प्रक्रम के माध्यम से, प्राथमिक शिक्षा ने व्यापक ध्यान आकृष्ट किया, इसके साथ ही इस दौरान बहुत सारे बहुपक्षीय दानदाताओं एवं एजेंसियों का ध्यान सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर केंद्रित रहा और साथ ही इसने प्राथमिक शिक्षा पर अतिरिक्त व्यय के आहवान पर जोर डाला गया।

यद्यपि, यह प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहनपूर्ण हैं; लेकिन अभी भी सभी विकासशील देशों की कुल सहायता का प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा केवल 4.8% है। इससे भी ऊपर, मध्य आय वाले विकासशील देश अपने हिस्से का केवल पाँचवा हिस्सा प्राप्त करते हैं और लगभग शिक्षा के लिए 50% द्विपक्षीय सहायता तृतीयक स्तर को प्रदान की गई, जिसमें से एक भारी राशि दानदाता देशों के संस्थानों में छात्रवृत्ति के लिए दी जाती है।

शिक्षा हेतु द्विपक्षीय सहायता में पाँच दानदाताओं का विशाल हिस्सा है।

ये दानादाता अपनी शिक्षा के समर्थन में एक ही समजातीय समूह से नहीं है। वर्ष 2004 में, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ मिलाकर शिक्षा के लिए द्विपक्षीय सहायता में 72% हिस्सेदारी थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग दो तिहाई भागीदारी नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट्स से आती है। यदि प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया जाता है तो और अधिक दानदाताओं को और अधिक भारी मात्रा में, सम्मिलित होने की जरूरत है या प्रमुख दानदाताओं या दोनों को अपनी भागीदारी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

गरीब देशों हेतु शिक्षा सहायता के लिए व्यापक ध्यान केन्द्रित करने के बार-बार आह्वान के बावजूद ओ ई सी डीज की डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी (डी ए सी) की आधे से अधिक देशों ने अपनी शिक्षा सहायता का आधे से अधिक भाग को मध्य आय देशों के लिए प्रदान किया।

वर्ष 2003-04 में बहुपक्षीय दानदाताओं ने अपनी कुल शिक्षा सहायता का 11.8% भाग प्रदान किया। इसमें से 52% हिस्सा प्राथमिक शिक्षा के लिए गया। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई डी ए) के बाद, यूरोपियन कमीशन सबसे बड़ा बहुपक्षीय दानदाता है। वर्ष 2005 के लिए अंतरिम आँकड़े यह सुझाते हैं कि शिक्षा हेतु इसका आधा परिव्यय प्राथमिक शिक्षा के लिए जाता है। इसमें उप सहारा अफ्रीका (30%) तथा दक्षिण एवं मध्य एशिया (19%) के लिए उच्च प्रतिबद्धता थी।

यद्यपि, यह प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहनपूर्ण हैं; लेकिन अभी भी सभी विकासशील देशों की कुल सहायता का प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा केवल 4.8% है।

सारणी 2:1:2000 एवं 2004 (एक समान 2003 में यू एस डालर बिलियन में) आय समूह द्वारा, शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल ओ डी ए का आँकलन

	शैक्षिक क्षेत्र		प्राथमिक शिक्षा		
	विकासशील देश	कम आय वाले देश		विकासशील देश	कम आय वाले देश
2000			**2000**		
प्रत्यक्ष	4.60	2.48	सीधे (प्रत्यक्ष)	1.40	0.98
			'अविशिष्टीकृत स्तर' से	0.68	0.38
अविशिष्टीकृत स्तर से	1.00	0.93	बजट समर्थन से	0.50	0.47
योग	5.60	3.41	**योग (कुल)**	2.59	1.83
2004			**2004**		
प्रत्यक्ष	8.55	5.53	सीधे (प्रत्यक्ष)	3.32	2.70
			'अविशिष्टीकृत स्तर' से	0.56	0.29
अविशिष्टीकृत स्तर से	0.94	0.85	बजट समर्थन से	0.47	0.43
योग	9.49	6.83	**योग (कुल)**	4.35	3.42
2000 से बदलाव	69.3%	87.2%	**2000 से बदलाव**	68.1%	86.6%

स्रोत : देखें अध्याय 4, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में

सहायता: कौन लाभ पाता है

सहायता प्राप्त करने वाले देश पर ध्यान केन्द्रित करने से सहायता परिदृश्य की एक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध होती है। दानदाता अपने संसाधनों को बहुत ही असमान रूप से वितरित करते हैं। शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता सहायता की उच्च राशि केवल 20 देश प्राप्त करते हैं। इनमें केवल सात निम्न आय समूह (एल डी सीज) हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ जो गरीबतम देशों की शिक्षा सहायता की सघनता पर अभिभावी हो रही हो।

दुनिया भर के गरीबतम 72 देशों में दानदाताओं की असमान उपस्थिति है। इथोपिया, माली, मोजांबिक, एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया में हर एक के बीच शिक्षा क्षेत्र में दस से बारह दानदाता हैं; जबकि दूसरी ओर बत्तीस देशों में प्रति देश के साथ केवल दो दानदाता हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न सहायता के लक्ष्य के बारे में उठता है कि दानदाता उस देश को लक्षित करें जहाँ सहायता अधिक महत्व रखती हो।

शिक्षा की कुल सहायता में सभी क्षेत्रों को अपेक्षाकृत समान महत्व नहीं दिया गया है। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया तथा अरब राष्ट्र शिक्षा क्षेत्र का काफी ऊँचा हिस्सा (कुल सहायता का 20% से अधिक) प्राप्त करते हैं जो अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों से अधिक है। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सभी तेइस देशों द्वारा कुल मदद राशि का सिर्फ 11% प्राप्त करते हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के देशों ने अपनी सहायता राशि का 50% भाग प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में प्रवाहित किया हुआ है जबकि इसकी तुलना में उप सहारा अफ्रीकी तथा लातीनी अमेरिकी देश में यह कुल सहायता राशि का 20% हिस्सा होती है। यहाँ तक कि अरब राष्ट्रों तथा पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में यह हिस्सा इससे भी कम है।

सभी देश लगातार सहायता की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं जोकि वर्ष 2005 में 100 से अधिक दानदाता तथा विकासशील देशों द्वारा 2005 में डिक्लेरेशन आन एड एफिक्टिवनेस (सहायता प्रभावशीलता घोषणा) में हस्ताक्षरित भावना की उत्साहशीलता से सम्बद्ध है। तीव्रमार्गी प्रोत्साहन (एफ टी आई) अधिकाधिक रूप से प्रमुख शिक्षा क्षेत्रों में प्रेरक के रूप में देखे गए हैं जो निरंतर घोषणा के साथ गतिशील है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्र में संयुक्त निगरानी समीक्षा, अब लगभग 20 देशों द्वारा बढ़ाई जा रही है और सामान्यत: धरातल पर सभी एजेंसियाँ तथा सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित है। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में (या उपक्षेत्र अथवा विशाल परियोजना) कार्य निष्पादन कों, एक सहमत विकल्पी सेट के प्रति मूल्यांकित करना है – उदाहरण के लिए प्राथमिक शिक्षा में पहुँच, परिमाण एवं गुणवत्ता आदि।

शिक्षा के लिए सहायता–परिमापन

कई विकसित देशों की सरकारों ने वादा किया कि अगले कुछ वर्षों तक भरपूर मात्रा में अपनी सहायता का प्रवाह बढ़ाते रहेंगे। 2005 अनेक उच्च रूपरेखा वाली गोष्ठियों ने अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। दानदाताओं ने वचनबद्धता दिखाई है कि वे अपनी जी एन पी (सकल घरेलू उत्पाद) के एक हिस्से के रूप में सहायता बढ़ाएंगे और वचनबद्धता पूरा होने के परिणामस्वरूप यह राशि 50 बिलियन यू एस डालर हो सकती है। या वर्ष 2010 तक सहायता राशि में 60% वृद्धि हो जाएगी जिसमें अफ्रीकी देशों के लिए कुल राशि का दोगुना होना भी शामिल है। उन लोगों ने यह भी कहा कि सभी गरीबतम देशों द्वारा ढोए जाने वाले-इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, आई डी ए, अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड आदि के कर्जों को चुका देंगे। संभाव्यता, छियालीस गरीबतम देशों को कर्ज से मुक्ति के रूप में संसाधन बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

हाल ही में, मार्च 2006 में, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने यह वादा किया कि अगले 10 वर्षों तक शिक्षा के लिए 15 बिलियन यू एस डालर प्रदान करेगी और साथ ही अन्य सरकारों से भी यह अपील की है कि वे भी आदेश का अनुपालन करें ताकि सर्व शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वित्तीय अंतराल को कम से कम किया जा सके। जुलाई 2006 में, सेंट पीट्सवर्ग में जी-8 देशों की गोष्ठी के दौरान, प्राथमिक शिक्षा हेतु अपनी प्रतिबद्धता का पुनर्निश्चय दोहराया तथा जैसा कि उन्होंने 2005 में एफ टी आई में (बाक्स 2.1) तब किया था, उसे पुन: समर्थित किया।

वर्ष 2000 एवं 2003 के बीच दाताओं ने वास्तविक वितरण से कहीं 50% अधिक प्रतिबद्धता दिखाई। दानदाताओं को चाहिए कि दीर्घकालिक अवधि की गारंटी देने हेतु पूर्वानुमानित वित्तीय सहायता के लिए व्यापकत प्रयास करें। उन देशों के लिए इस आश्वासन की आवश्यकता रहती है जो इस लक्ष्य को पाने के क्रम में कठिनाई पाते हैं तथा अक्सर खर्चीले नीति निर्णय सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए लक्षित होते हैं।

दानदाता बहुत हद तक तब अपनी प्रतिबद्धता को सम्मान देते हैं जब वे यह देखते हैं कि वे देश उनकी सहायता को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषकर, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में विकासशील देशों की परिव्यय दर कम होती है। सरकारों की नीतियां बनाने तथा क्रियान्वित करने की क्षमता को निश्चित ही सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक इसी समय, प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता का जो भाग तकनीकी समन्वय के लिए निश्चित है, वह घट रहा है। जो संभवत: कुछ अंश तक प्रत्यक्ष बजट समर्थन प्रवृत्ति में बिम्बित हो सकता है। जो तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण पर प्राथमिकता को घटाने की अनुमति देता है। सर्व शिक्षा (ई एफ ए) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सहायता के अतिरिक्त राशि के अनेक अनुमानों को पिछले कुछ वर्षों में कई बार परिकलित किया जा चुका है-

- विश्व बैंक ने अनुमानित किया है कि वर्ष 2001 से सभी निम्न आय वाले देशों द्वारा 2015 तक यू पी ई की प्राप्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि राशि 9.7 बिलियन यूएस डालर प्रतिवर्ष जरूरत है जिसमें से 3.7 बिलियन डालर को बाहर से उपलब्ध कराने की जरूरत है।

- वर्ष 2002 सर्व शिक्षा (ई एफ ए) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट संस्तुत करती है कि बाहर की राशि का अंतराल 3.1 विलियन यू एस डालर से कहीं अधिक है। यह तर्क देती है कि घरेलू खर्च के बारे में वार्षिक वृद्धि दर की विश्व बैंक परिकल्पना अधिकाधिक आशापूर्ण है और यह कि शिक्षा पर परिवारों की लागत को घटाने की जरूरत है तथा एच आई वी/एड्स के पूर्ण संघात के साथ तालमेल तथा संघर्षों, अस्थिरता तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों की पुनर्वास प्रणाली की लागत घटाने की जरूरत है।

- फिलहाल कम आय वाले देशों में प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता की राशि उनकी आवश्यकता से कहीं कम है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005 से 2015 तक प्रतिवर्ष औसतन 9 बिलियन यू एस डालर प्रतिवर्ष की आवश्यकता है। यह अनुमान केवल यू पी ई की प्राप्ति के लिए हैं। इसके साथ साक्षरता तथा शैशवकालीन देखभाल लक्ष्य के लिए प्रत्येक को प्रतिवर्ष एक बिलियन यू एस डालर की आवश्यकता है, जो बाहरी फंडिंग की आवश्यकता को प्रतिवर्ष 11 बिलियन डालर तक बढ़ा देता है (2003 की स्थिर कीमत पर)।

यदि दानदाता अपनी प्रतिबद्धता निभाते हैं और वर्ष 2010 तक कुल राशि में 2004 से 60% की वृद्धि तक जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा निरंतर स्थिर रहता है। और प्रतिवर्ष की यह प्रस्तावित राशि 5.4 बिलियन यू एस डालर तक पहुँचेगी जो अपेक्षित राशि 11 बिलियन यू एस डालर से ठीक आधे से भी कम है। सर्व शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तीव्र प्रगति लाने के लिए कुल ओ डी ए में प्राथमिक शिक्षा के हिस्से को ठीक दो गुना करने की जरूरत है।

उच्च स्तर की सहायता के लिए प्रतियोगिता संभवत: बढ़ेगी, जिसमें माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर की शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों की शिक्षा जैसे स्वास्थ्य एवं ढांचागत संरचना शामिल हैं। यहाँ पर दानदाताओं के बीच भी एकता दिखती है कि वे उन देशों की संख्या घटा रहे हैं जहाँ उनके सहायता कार्यक्रम हैं। इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दृष्टि के साथ प्रक्रम विकसित किया जाए–जैसे कि एफ टी आई कैटालिक फंड में एक सुधार–उन देशों में सहायता प्रवाहित करना जहाँ इसकी व्यापकता से आवश्यकता है।

शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता की अब आवश्यकता है, चूँकि वर्ष 2015 तक यू पी ई पर पहुँचने के लिए सभी बच्चे वर्ष 2009 तक निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु स्कूल में होने चाहिए। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की प्रतिबद्धता प्रोत्साहन पूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा हेतु सहायता वृद्धि के लिए दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक दुस्साहसी तथा अधिक विश्वासोत्पादक प्रयासों को करने की जरूरत है। निम्न आय वाले देशों की सरकारों को निश्चित रूप से चाहिए कि दानदाताओं के साथ परिचर्चा में शिक्षा की प्राथमिकता को ऊँचे स्थान पर रखते हुए राजी करना चाहिए तथा उन्हें कर्ज मुक्ति, बचत में भारी हिस्सा प्रदान किए जाने की माँग करनी चाहिए। ■

बाक्स 2:1 तीव्र मार्गीय प्रयास: एक वैश्विक संघात को प्रोत्साहन

वर्ष 2002 में इस उद्देश्य के साथ एफ टी आई की स्थापना की गई थी कि 'विश्वसनीय' शिक्षा क्षेत्र योजना विकास हेतु एक वैश्विक संघात को प्रोत्साहित किया जाए तथा सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बाहरी वित्तीय समर्थन को बढ़ाया जाए। इसमें 30 से अधिक दानदाताओं के सम्मिलन के साथ दानदाता एजेंसीज के लिए एफ टी आई एक महत्वपूर्ण समन्वय प्रक्रम बन गया। इसके अतिरिक्त इसके दो फंडों के माध्यम से कुछ अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को प्रणालित किया गया। कैटालिक फंड तीन वर्षीय शिक्षा योजना के लिए उन देशों को समर्थन प्रदान करता है जहाँ केवल कुछ दानदाताओं की उपस्थिति है और इससे अपवादस्वरूप अच्छी कार्य निष्पत्ति वाले भी अतिरिक्त को आकर्षित करते हैं। इस तरह से, हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका और फंडिग अवधि को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। एजूकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट फंड कई देशों को उनकी अपनी योजनाओं को विभिन्न तरीकों से विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2006 में जब से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है एफ टी आई ने 74 देशों को शिक्षा क्षेत्र योजनाओं के विकास के लिए तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया है। दानदाताओं ने 20 देशों की योजनाओं को समर्थित किया है तथा 12 अन्य देशों को भी 2006 के अंत तक समर्थित किए जाने की उम्मीद की गई है।

फिलहाल, कैटालिक फंड में राशि अभी भी अपेक्षाकृत छोटी है और सीमित संख्या में देश लाभान्वित हुए हैं। अगस्त 2006 के अनुसार इस फंड में कुल दानदाता भुगतान लगभग 230 मिलियन यू एस डालर है, यद्यपि 450 मिलियन यू एस डालर की आगे भी वर्ष 2007 के अंत तक प्रतिबद्धता दिखाई गई है। नीदरलैंड, दि यूरोपियन कमीशन तथा यूनाइटेड किंगडम 85% प्रतिबद्धता के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल केवल ग्यारह देशों में ही 96 मिलियन यू एस डालर की राशि परिव्यय की गई है। एजूकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट फंड के लिए दानदाताओं की संख्या पिछले वर्ष से दो से बढ़कर आठ हुई है और 2005–2007 के लिए 46 मिलियन यू एस डालर की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें से लगभग आधी राशि नार्वे से प्राप्त होनी है।

यदि वैश्विक संघात को वास्तविक रूप देना है तो अंतत: दानदाताओं से विस्तृत उच्च स्तरीय नेतृत्व अपेक्षित है। इसके अंतर्गत संभवत: एफ टी आई को और अधिक सुदृढ़ीकरण जैसे मापदंड अपनाने के साथ, एक ऐसे प्रयास के साथ जोड़ा गया जो अधिक पूर्वानुमानक हो, विशेष रूप से बहुत अधिक आवश्यकता वाले देशों के लिए औचित्यपूर्ण हो।

प्रतिवर्ष 11 बिलियन यू एस डालर की बाहरी फंडिंग की आवश्यकता है

भाग III. शैशवकालीन देखभाल तथा शिक्षा के लिए मामला

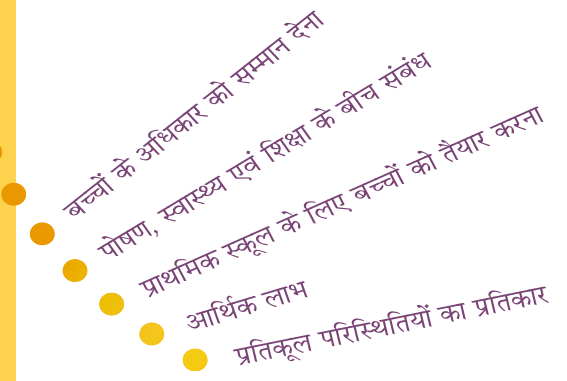

शैशवकालीन वह अवधि होती है जब मानव अपनी उत्तरजीविता, भावनात्मक सुरक्षा तथा सहजात विकास के लिए रिश्तों पर निर्भर होता है। पर्याप्त पोषण का अभाव तथा सही देखभाल की कमी उल्टे परिणाम प्रदर्शित कर सकती है। बच्चों के अधिकार पर हुआ सम्मेलन बच्चों के बेहतर हितों तथा विकास को केन्द्रीय संबद्धता बनाता है। शैशवकालीन कार्यक्रम का तात्पर्य छोटे बच्चों के अधिकारों को उनकी बेहतरी (कल्याण) को सुधारकर तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार कर, गारंटीकृत किया जा सकता है। तत्काल और दीर्घकालिक लाभ ऐसे कार्यक्रमों की एक लागत प्रभावी रणनीति बनाते हैं जो गरीबी को घटाती तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिकार करती है।

बहुत छोटे बच्चों के भी अधिकार हैं

अनेकों मानव अधिकार प्रपत्र बच्चों हेतु विशिष्टीकृत हैं। हालांकि ये कानून से बाध्य नहीं हैं। बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1959 में अधिग्रहीत किया गया था जो बच्चों के अधिकार संबंधी कुछ आधारभूत सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा उपेक्षा, निर्दयता एवं शोषण से संरक्षा के प्रावधान सम्मिलित हैं। लेकिन 1989 का बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन (सी आर सी) बच्चों के अधिकार हेतु एक नए युग की शुरूआत करता है। सी आर सी बच्चे के सर्वोत्तम हितों को अगली सीमा पर खड़ा करते हैं और बच्चों के दृष्टिकोण हेतु एकाग्र हैं। यह विश्व में सर्वाधिक मान्य मानव अधिकार समझौता है, सी आर सी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को घरेलू कानून एवं राष्ट्रीय व्यवहार में रूपांतरित कराने की प्रतिबद्धता है।

सी आर सी के पास सर्वाधिक छोटे बच्चों के समूह के लिए बहुत थोड़े प्रावधान हैं, परन्तु इसकी निगरानी समिति-द कमेटी आन चाइल्ड राइटस 2005 (बच्चों के अधिकार पर गोष्ठी) शैशवकाल के एजेंडे को एक सामान्य टिप्पणी के साथ आगे बढ़ाता है जिसके अनुसार छोटे बच्चों को पालन-पोषण, देखभाल, मार्गदर्शन की विशिष्ट आवश्यकता होती है। यह कार्यशील अभिलेख जो शैशवकाल या बचपन को जन्म से आठ वर्ष की अवधि के रूप में परिभाषित करता है और सी आर सी का एक हिस्सा रहता है। जिसमें उनकी जिम्मेदारियाँ के अंतर्गत सुयोग्य नीतियों का विकास जिसमें छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल तथा शिक्षा आदि के लिए अभिभावकों द्वारा सहायता एवं देखभाल शामिल है। शैशवकालीन शिक्षा कहती है कि यह सीधे तौर पर बच्चों के अधिकार के साथ जुड़ी होनी चाहिए जिसमें उसके व्यक्तित्व, कौशल का विकास तथा जन्म से दिमागी एवं शारीरिक सक्षमता को विकसित करना शामिल है।

यह मानना कि बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर स्थापित करने के लिए स्वत: अधिकार है जिसे कि सदैव वैयक्तिक सत्ता या राष्ट्रों द्वारा नहीं माना जाता है। इसके प्रावधान राष्ट्रों को सशक्त बनाते हैं कि एक बच्चे की ओर से उनके हित में दखलंदाजी करें, पर यह मुददा अभी भी विवादास्पद है। अभी भी, सी आर सी अपनी सार्वभौम अधिग्रहण के बावजूद, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त है जिससे केवल कुछेक ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते बराबरी कर सकते हैं और बचपन के लिए सशक्त नीति एजेंडे को आकार देने में व्यापक हाथ बँटाते है।

© EPA/KIM LUDBROOK/SIPA PRESS

पोषण अधिगम को बेहतर बनाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में पूर्व प्राथमिक स्कूल में भोजन का अवकाश

प्रारंभिक वर्षों के (शैशवकालीन) अनुभवों का प्रभाव

शैशवकाल एक उच्च संवेदनशील अवधि होती है जो शारीरिक, जन्मजात, सामाजिक तथा भावानात्मक विकास के तीव्र रूपांतरण या कायांतरण से विशिष्टीकृत होती है। कुपोषण, देखभाल से वंचना तथा खराब उपचार विशेष रूप से छोटे बच्चों में क्षति पहुँचाते हैं और इनके दुष्परिणाम वयस्कावस्था में प्राय: महसूस किए जाते हैं। जीवन के पहले वर्षों में विषाक्त पदार्थों के प्रति अरक्षितता तथा अपर्याप्त उत्प्रेरणा उन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। एक बच्चा जो बहुत ही खराब देखभाल पाता है या भाषा को यदा-कदा सुनता है (अनाथालयों में प्राय: ऐसा हो जाता है) बहुत हद तक विकास की कमी को झेल सकता है जिसे बाद में सुधार पाना कठिन होता है।

अच्छे कार्यक्रम इन शुरूआती रचनात्मक वर्षों में छोटे बच्चों की तंदुरुस्ती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं तथा घर पर की गई देखभाल संपूरक हो सकती है।

शिक्षण के लिए उचित स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यक है

प्रति वर्ष 10 मिलियन से अधिक बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं और इनमें आधे उन संक्रामक रोगों से मरते हैं जिन्हें निवारित या उपचारित किया जा सकता है। दुनिया भर में, निकट वर्षों में पैदा हुए प्रत्येक 1000 बच्चों में लगभग 86 बच्चे 5 वर्ष की आयु पर पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। यह शिशु मृत्यु दर उप सहारा अफ्रीकी तथा दक्षिण व पश्चिम एशियाई देशों (प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में 100 से अधिक बच्चे) में अत्यंत उच्च है।

खराब पोषण बच्चे की स्कूल में भागीदारी तथा उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। छात्र बच्चे (जो अपनी आयु की अपेक्षा छोटे होते हैं) संभवत: स्कूल में कम नामांकित होते हैं और बहुत संभव हद तक बाद में नामांकित होते हैं या पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। बचपन में एक गंभीर या दीर्घकालिक अनिवार्य पोषण की कमी बच्चे की भाषा, संचालन, तथा समाज-भावनात्मक विकास को क्षतिग्रस्त करता है।

बाल विकास का एक अति समग्र दृष्टिकोण ठोस धरातल पा रहा है, स्वास्थ्य तथा पोषण के बीच एक ओर जहाँ कड़ी का गठन हो रहा है वहीं दूसरी ओर शिक्षा भी आगे बढ़ रही है।

सुरक्षित पेयजल तथा उचित सफाई व्यवस्था के विस्तारण का प्रावधान शिशुओं एवं छोटे बच्चों की मृत्यु दर में नाटकीय रूप से कमी ला देता है। छोटे बच्चों के लिए उत्तरजीविता एवं विकास हेतु एच आइ वी / एड्स के लिए उपचार तक पहुँच बहुत महत्वपूर्ण या निर्णायक होती है (बाक्स 3.1)। उपसहारा अफ्रीकी देशों में सुनियोजित शैशवकालीन कार्यक्रमों की सीमित व्याप्ति होने के कारण खराब पोषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को ढूँढ पाना व इलाज कर पाना अत्यधिक कठिन होता है। लातीनी अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्रों में, शैशवकालीन कार्यक्रमों के कारण कुपोषण एवं अवरूद्ध विकास की प्रचुरता में कमी आई है तथा उसने बच्चों की तंदुरूस्ती एवं स्कूल प्रवेश की तैयारी में भागीदार निभाई है।

छोटे बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रमों एवं समेकित देखभाल स्थापित करने की दिशा में मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को घटाने के लिए उपाय निर्मित किए गए। कुपोषित बच्चों में सहजात परिणामों पर चार प्रकार के हस्तक्षेपों ने व्यापक प्रभाव डाला; ये थे- आयरन संपूरक, अतिरिक्त आहार, कृमिहरण तथा मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण। बाल विकास का एक अति समग्र दृष्टिकोण ठोस धरातल पा रहा है, स्वास्थ्य तथा पोषण के बीच एक ओर जहाँ कड़ी का गठन हो रहा है वहीं दूसरी ओर शिक्षा भी आगे बढ़ रही है। भारत में, दिल्ली राज्य में एक कार्यक्रम बच्चों को कृमिहरण एवं आयरन संपूरक उपलब्ध करा रहा है। फलस्वरूप उच्च पूर्व स्कूली उपस्थिति दर्ज की गई । पोषण और शिक्षा के साथ समिश्रित किए जानेवाले हस्तक्षेप बहुत संभव हद तक सफलता पा रहे हैं अपेक्षाकृत उनके, जो पोषण को चलाते हैं। ग्वाटेमाला तथा वीएतनाम के अध्ययनों में यह पाया है कि पोषण पैकेज तब दीर्घकालिक प्रभाव डालता है जब बच्चों को सहजात उत्प्रेरणा प्राप्त होती है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण समस्या से निपटने हेतु, विनिर्मित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शिक्षा को एक अभिन्न आयाम माना जाना चाहिए।

बाक्स 3.1 एच आईवी/एड्स : छोटे बच्चों के लिए उपचार

प्रतिदिन लगभग 1800 बच्चे एच आई वी संक्रमण के साथ जन्म लेते हैं। एच आई वी प्रभावित बच्चे, दूसरे बच्चों की तुलना में जल्दी-जल्दी सामान्य बालपन की बीमारियां से जूझते हैं; वह भी वृहद प्रबलता से तथा प्राय: दवाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशीलता से। जो बीमारियाँ स्वस्थ बच्चों के लिए घातक होती हैं, वे एच आई वी प्रभावित बच्चों के लिए उच्च मृत्यु दर का कारण बनती हैं। एंटीरेट्रो वायरल उपचार तक बिना पहुँच के बीमारियों की प्रगति बहुत तीव्र होती है - लगभग 45 प्रतिशत बच्चे दो वर्ष की अवधि पर पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। बच्चों पर एच आई वी संक्रमण के संघात को कम करने हेतु, प्रारंभिक निदान की जरूरत होती है। अच्छा पोषण, औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षीकरण तथा दवा उपचार सामान्य शैशवकालीन संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उच्च आय वाले देशों के अनुसंधानों ने यह दर्शाया है कि एच आई वी का संक्रमण निम्न शैक्षिक उपलब्धि, कमजोर भाषा कौशल, पूर्व प्राथमिक स्कूलों में कम पहुँच, तथा खराब दृश्य संचालन क्रियाशीलता से संबंद्ध होता है। संक्रमित बच्चों में एंटीरेट्रोवायरल उपचार सहजात एवं समाज-भावनात्मक विकास को बेहतर बनाता है। शैशवकालीन कार्यक्रम ऐसे उपचारों हेतु एक मार्ग उपलब्ध करा सकते हैं और इस बीमारी के भावनात्मक एवं अन्य दुष्परिणामों की क्षतिपूर्ति में मदद कर सकते हैं।

एड्स प्रभावित परिवारों के बच्चे बीमारी से जुड़े दोष को झेलते हैं। शैशवकालीन कार्यक्रम, प्रतियोगिता, अनाथपन के संघात पर उपलब्ध जानकारी बिरल बना देते हैं। इसके बावजूद ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क; प्राथमिक स्कूलिंग की तुलना में अधिक होती है तथा छोटे बच्चों के अभिभावकों की मौत का संघात उनकी उपस्थिति में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाल सकता है।

प्राथमिक स्कूल में पहुँच एवं प्रगति में सुधार

ई सी सी ई कार्यक्रम बच्चों की शारीरिक स्वस्थता, सहजात एवं भाषाई कौशल तथा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का संघात (प्रभाव) प्राथमिक स्कूल शिक्षा में भागीदारी तथा उसके आगे भी अच्छाइयाँ अभिलिखित प्रमाण हैं। उदाहण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में पूर्व स्कूली अनुभवों के परिणाम बेहतर बौद्धिक विकास, आत्मनिर्भरता, ध्यान केन्द्रित करने तथा पहले तीन वर्षों तक प्राथमिक स्कूल में मिलनसारिता में प्रदर्शित हुए।

इस कार्यक्रम के बारे में अनेक विकासशील देशों के अध्ययन शैशवकालीन कार्यक्रमों तथा प्राथमिक स्कूलों में बेहतर पंजीयन एवं कम से कम तीन-चार साल तक बेहतर परिणामों की ओर परस्पर संबंध का इशारा करते हैं। विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों वाले बच्चों में अधिक दिखता है। नेपाल के एक गरीब जिले के जिन बच्चों ने शैशवकालीन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उनमें से 95 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में गए जबकि इसके विपरीत कार्यक्रम में भाग न लेने वालों में से केवल 75 प्रतिशत स्कूल गए। कक्षा 1 की पढ़ाई के अंत में इन बच्चों ने उच्चतम अंक प्राप्त किए। टर्की के इंस्तबूल में गरीब क्षेत्रों में संचालित टर्किश अर्ली इनरिचमेंट प्रोजेक्ट (टर्किश प्रारंभिक सुदृढ़ता योजना) पूर्व-स्कूल तथा माताओं को समर्थन देना समाहित किए हुए हैं, परिणामत: 7 वर्षों के बाद भी 86 प्रतिशत बच्चे अभी भी स्कूल में है जबकि तुलनात्मक रूप से भाग न लेने वालों में से 67 प्रतिशत बच्चे हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए नियंत्रण हेतु एक अफ्रीकी देश ने पूर्व-प्राइमरी उच्च नामांकन अनुपात, उच्च प्राथमिक स्कूल समापन दर तथा प्राइमरी में पुननामांकन दर निम्न पाई गई ।

आर्थिक मामला

शैशवकालीन कार्यक्रमों के प्रदत्त स्वास्थ्य,पोषण तथा शिक्षा के संघात (असर) सकारात्मक नतीजों के साथ यह मानव पूँजी के लिए एक अच्छा निवेश है। यद्यपि, इस दिशा में शोध सीमित है; विशेष रूप से विकासशील देशों में, फिर भी ई सी सी ई कार्यक्रमों में निवेश करना सकारात्मक है और वास्तव में; प्राय: शिक्षा क्षेत्र में दूसरे निवेशों की अपेक्षा वापसी बेहतर है। ई सी सी ई के निवेश की वापसी लंबी अवधि के बाद परिपक्व होती है, अपेक्षाकृत उनसे जो बड़े बच्चों, युवाओं या वयस्कों को लक्ष्य बनाते हैं। कुल मिलाकर ई सी सी ई कार्यक्रम में अपेक्षित कौशल अन्य आगे के सभी शिक्षणों के लिए आधार होते हैं।

शैशवकालीन कार्यक्रम के सर्वाधिक व्यापकता से दृश्य साक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स के लांगीट्यूडनल हाई/स्कोप पेरी प्री स्कूल प्रोग्राम से आते हैं। वर्ष 1962 से 1967 के बीच कार्यक्रम ने उच्च जोखिम के स्कूल की असफलता हेतु कम आय वाले अफ्रीकी-अमेरिकी बच्चों को मूल्यांकित करने के लिए लक्षित किया। प्रतिभागियों तथा एक नियंत्रण समूह ने प्रति वर्ष 3 से 11 आयु वर्ग के बच्चों से संपर्क बनाए रखा तथा आगे भी

अनेक बार संपर्क रखा, जब तक कि वे 40 वर्ष की आयु के नहीं हुए। प्रतिभागिता के कारण आई क्यू में 5 वर्ष की आयु में बढ़ोत्तरी पाई गई, हाई स्कूल से ग्रेजुऐशन में पहुंचने की उच्चतम दर रही और 40 वर्ष की आयु में उनकी कमाई काफी उच्च थी। विस्तृत विश्लेषण यह सुझाता है कि कार्यक्रम से लाभ/लागत अनुपात 17:1 की प्राप्त हुई।

विकासशील देशों के साक्ष्य धीरे-धीरे संचित हो रहे हैं। दिल्ली में एक प्री-स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से औसतन स्कूल की सहभागिता को 7.7 प्रतिशत वृद्धि लड़कियों हेतु तथा 3.2 प्रतिशत लड़कों के लिए इंगित करता है। ठीक यही कार्यक्रम जीवन भर के पारिश्रमिक में कुल मूल्य में 29 यू एस डालर प्रति बच्चा बढ़ाता है जबकि इसकी लागत प्रति बच्चा केवल 1.70 यू एस डालर आती है। बोल्विया में, एक घर-आधारित कार्यक्रम की मूल्य/लागत अनुपात 2.4:1 से 3.1:1 आती है जो जोखिमग्रस्त बच्चों के लिए उच्च अनुपात है। कोलंबिया तथा मिश्र के विश्लेषण ने ठीक यही अनुपात पाया है। सभी मामलों में, ई.सी.सी.ई का प्रभाव गरीब परिवारों के बच्चों में, अधिक अनुकूल परिस्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा प्रतिभागिता को देखा गया; प्राथमिक स्कूलों में निम्न अधूरी पढ़ाई तथा पुनर्नामांकन की कम दर पाई गई।

सामाजिक असमानता को घटाना

छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के हिमायती लंबे समय से लगातार तर्क दे रहे थे कि ये सामाजिक असमानता को घटा सकते हैं। हाल ही के अनुसंधान यह सुनिश्चित करते हैं कि ई.सी.सी.ई कार्यक्रम विपरीत परिस्थिति वालों को क्षतिपूरित कर सकते हैं फिर चाहे वे गरीबी, लैंगिक, मानव जातीय, जाति या धर्म आदि किसी भी घटक के अन्तर्गत क्यों न आते हों। हेड स्टार्ट, 1964 में 'गरीबी पर हमला' के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी जो इस संकल्पना के साथ संचालित थी कि लक्षित हस्तक्षेप कम अनुकूल परिवारों एवं सामुदायिक पृष्ठभूमि वालों को क्षतिपूरित कर सकते हैं। द हाई/स्कोप पेरी प्रोग्राम ने प्रतिकूल परिस्थित वाले बच्चों को समान स्तर में लाने के क्षेत्र में काम किया। इस प्रकार के विविध स्थानों के कार्यक्रम; जैसे कि कैप वर्ड, मिश्र, गुइनिया, जमैका तथा नेपाल ने लगातार यह पाया है कि सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थिति वाले बच्चे उनमें से एक हैं जिन्होंने ई सी सी ई कार्यक्रम से सर्वाधिक लाभ उठाया है।

शैशवकालीन कार्यक्रम लैंगिक असमानता को भी घटा सकते हैं। जिन लड़कियों ने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया, वे संभवत: सही आयु पर स्कूल की शुरूआत करती हैं तथा प्राथमिक शिक्षा को पूरा करती हैं। ई.सी.सी.ई सहभागिता कार्यक्रम में एक प्रवृत्ति यह भी है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।

अच्छे किस्म के स्वास्थ्य एवं शैशवकालीन की देखभाल एवं समर्थन प्रावधान सभी बच्चों के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन यह कार्यक्रम विशेष रूप से गरीब एवं सुकुमार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है ताकि विपरीत परिस्थिति वाले क्षतिपूरित हो सकें। जैसा कि नोबुल पुरस्कार विजेता जेम्स हैकमैन के अनुसार, 'यह एक दुर्लभ सरकारी नीतिगत प्रयास है जो निष्पक्षता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है और ठीक इसी समय पर इकोनॉमी एवं व्यापक समाज की उत्पादकता को उन्नत बनाता है। प्रतिकूल परिस्थिति वाले छोटे बच्चों में निवेश करना एक नीति जैसा है'। ■

बगदाद में, अपने पुत्र के साथ एक स्वाभिमानी पिता

भाग IV. शैशवकालीन देखभाल तथा शिक्षा का प्रसार (ई.सी.सी.ई)

सभी समाजों में छोटे बच्चों की देखभाल एवं शिक्षित करने की व्यवस्था है। हालांकि, वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक प्रवृत्ति; प्रवास, शहरीकरण तथा स्त्री श्रम बाजार की भागीदारी को भी सम्मिलित किए हुए है जो कि आज परिवार संरचना को रूपांतरित कर रही है, साथ ही और अधिक नियोजित शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा की तीव्र माँग पैदा कर दी है। आज केवल कुछेक देश ही लगभग सार्वभौम व्याप्ति प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे विकासशील देशों में, शैशवकालीन कार्यक्रम केवल जनसंख्या के कुछ अंशों तक, विशिष्ट तौर से धनाड्य शहरियों तक पहुंच रहे हैं। यह भाग शैशवकालीन प्रावधान के उभार या उदय को देख रहा है तथा इस व्यापकता को मूल्यांकित कर रहा है कि दुनिया भर में कौन से बच्चे ई.सी.सी.ई कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं।

श्रम बाजार में स्त्रियों का आगमन
3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सीमित सरकारी प्रावधान
पूरे विकासशील विश्व में पूर्व-प्राइमरी नामांकन में वृद्धि
लैंगिक समानता की उपलब्धि के करीब
परिवार सर्वेक्षण जो असमानता को इंगित करता है
शैशवकालीन सेवाओं में एक नारी सुलभ गुण वाला कार्यबल

मुड़कर या पीछे देखना : कामकाजी माताओं हेतु समर्थन तथा नियोजित बाल–देखभाल का उदय

छोटे बच्चों की औपचारिक देखभाल अनिवार्यत: सदियों पूर्व अट्ठारहवी शती में शुरू हुई थी। यूरोप में तमाम प्रकार की शैशवकालीन देखभाल संस्थाओं ने धीरे-धीरे जड़ें जमाई, जिनमें से कुछ आज के जाने-माने शिक्षा शास्त्रियों ने स्थापित किए थे, जैसे कि फ्रोबेल तथा मोंटेसरी। कुछ ने कामकाजी माताओं या उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का काम लिया, वहीं कुछ ने मिडिल क्लास बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रमबल में औरतों की बढ़ रही संख्या के कारण उनके छोटे बच्चों के लिए उत्तम किस्म की तथा वहन योग्य देखभाल सेवा की मांग बढ़नी शुरू हुई। बीसवीं शती के अंत तक पूरे यूरोप में सरकारी नर्सरी स्कूलों ने प्रभुत्व जमा लिया।

विकासशील देशों में शैशवकालीन प्रावधान का औपचारिकीकरण काफी नया है और इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्षेत्रीय विविधताएं हैं। कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में औरतों की परम्परागत भूमिका के मद्देनजर उनके बच्चों की देखभाल तथा बड़ा करने के लिए रिश्तेदारों तथा अनौपचारिक सामुदायिक व्यवस्था पर उनकी भारी निर्भरता बनी। हालांकि 1950 के बाद विकासशील देशों की स्त्रियों की श्रम बाजार में भारी प्रवेश ने स्थिति को ही बदल दिया। वर्ष 2005 में स्त्री श्रम बल की भागीदारी दर पूर्व एशिया दक्षिण-पूर्व एशिया तथा उप सहारा अफ्रीकी देशों में 55 प्रतिशत से अधिक तथा लातीनी अमेरिका एवं कैरेबियन देशों में लगभग 50 प्रतिशत थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण एशिया (35 प्रतिशत) तथा अरब राष्ट्रों (28 प्रतिशत) में कम भागीदारी रही। लेकिन फिर भी पिछले दशकों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से ऊँची थी। सामान्यत:, घरेलू कमाई एवं खर्च पर औरतों का अपेक्षाकृत जितना अधिक नियंत्रण होता है, बहुत हद तक पारिवारिक निर्णयों में बच्चों की देखभाल महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता पूर्व होती है और यह कि लड़के एवं लड़कियाँ शैशवकालीन प्रावधान से एक समान लाभ प्राप्त करेंगे।

अधिकतर विकसित देशों में, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में औरतों का काम करना सुदृढ़ता के साथ बच्चों की पूर्व-प्राइमरी स्कूल कार्यक्रमों में उच्च नामांकन से संबद्ध है। विकासशील देशों में रोजगार के प्रतिमान तथा प्री-प्राइमरी शिक्षा के

बीच संबद्धता की कड़ी कमजोर है। लेकिन प्रवास एवं शहरीकरण तथा एचआईवी/एड्स की सार्वभौमता आदि विस्तृत एवं एकल परिवारों के बीच बंधन को कमजोर बना रहे हैं तथा एक शैशवकालीन देखभाल की आवश्यकता पैदा कर रहे हैं जिसे वर्तमान व्यवस्था पूरा नहीं कर सकती है। एकल अभिभावक परिवार की संख्या, विशेष रूप से जो स्त्रियों के नेतृत्व में है और विशेष रूप से यूरोपियन संघ के देशों तथा लातीनी अमेरिकी देशों के परिवारों ने भी बाल देखभाल के लिए निहितार्थ दिए हैं।

शिशु देखभाल को समर्थन देने वाली सरकारी नीतियों की शुरूआत काफी पहले उन्नीसवीं शती में हुई थी। 1970 के दशक तक लगभग सभी ओ ई सी डी देशों ने सवेतन प्रसूति अवकाश और कुछेक ने (विशेष रूप से नो आर्थिक देशों सहित) अभिभावक अवकाश का प्रावधान किया जिसमें माता या पिता या फिर दुर्लभ मामलों में माता-पिता, दोनों ही काम से अवकाश ले सकते हैं। लगभग 100 विकासशील देशों से भी रिपोर्ट हैं कि उनके यहाँ भी किसी न किसी प्रकार की प्रसूति अवकाश की व्यवस्था है, हालांकि कुछ खास क्षेत्रों में और जहाँ अमूमन प्रवर्तन का अभाव है, वहाँ कामगारों के लिए अवकाशों की बहुधा कमी रहती है।

सर्वशिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्य की दिशा में प्रगति की निगरानी

लगभग 738 मिलियन बच्चे-अर्थात् विश्व की लगभग 11 प्रतिशत कुल जनसंख्या 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग में आती है। उनकी यह संख्या वर्ष 2020 तक 776 मिलियन पहुँच जाने की उम्मीद है। जो उप सहारा अफ्रीकी देशों तथा अरब राष्ट्रों की वृद्धि दर से अभिप्रेरित होगी।

ई सी सी ई कार्यक्रमों में प्रावधान, संगठन तथा फंडिंग की व्यापक विविधता निगरानी के लिए दुर्जेय चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा, शैशवकालीन लक्ष्य में कोई परिमाणात्मक लक्ष्य समाहित नहीं है जिसके द्वारा प्रगति को मापते हैं। निगरानी समस्या के अंतर्गत 3 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए कार्यक्रमों पर क्रमबद्ध आंकड़ों की कमी, कौन सा कार्यक्रम किस व्याप्ति तक स्वास्थ्य, भौतिक विकास, अधिगम एवं अभिभावकों का समर्थन कर रहा है, के बारे में सीमित सूचनाएं; शिक्षा मंत्रालयों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले प्री-प्राइमरी के पंजीयन आंकड़े; जो अन्य मंत्रालयों द्वारा प्राइवेट समूहों या स्थानीय समुदाय द्वारा फंड किए गए कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को समेट सकते हैं, आदि बातें सम्मिलित हैं। आयु वर्ग 3 से 5 वर्ष अथवा 3 से 6 वर्ष समूह के अंतर्गत पंजीयन प्रतिमान या मापदंड भी महत्वपूर्ण रूप से भिन्नतापूर्ण हो सकते हैं जो कि अधिकतर देश शैशवकालीन कार्यक्रमों में भागीदारी को परिकलित करने में प्रयोग करते हैं। इस रिपोर्ट ने कार्यक्रमों को मूल्यांकित करने हेतु बहुसंख्यक स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त की हैं।

विकासशील देशों में तीन वर्ष से कम आयु की देखभाल एवं शिक्षा व्यापक तौर पर माता-पिता, निजी क्षेत्र के संगठनों/संघों या गैर सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। इन बहुत छोटे बच्चों के लिए एक या अनेक कार्यक्रम दुनिया के आधे-से अधिक देशों में पहचाने जा सकते हैं। ये अनूठी तरह से छोटे बच्चों को अर्ध सामयिक अभिरक्षी देखभाल प्रदान करते हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य सेवाएं तथा शैक्षिक गतिविधियाँ भी प्रदान करते हैं। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु कार्यक्रमों के बारे में, यदि ई.सी.सी.ई की व्यापक निगरानी जगह लेना चाहती है तो बहुत अधिक सूचना की जरूरत है।

© David Seymour / Magnum Photos

1948, हंगरी के बुडापेस्ट में सरकार द्वारा संचालित किंडरगार्टेन के प्रारंभिक दिन

पूर्व–प्राथमिक शिक्षा : तीव्र पंजीयन वृद्धि

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (आई एस सी ई) पूर्व प्राथमिक शिक्षा को (आई एस सी ई डी लेवल 0), जैसा कि अन्य सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित है, निम्नवत् परिभाषित करता है-बच्चों को देखभाल प्रदान करने के अतिरिक्त, एक संरचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण अधिगम क्रियाकलापों का रुख पेश करता है, जिसे या तो एक औपचारिक संस्थान प्रदान करता है या फिर अनौपचारिक व्यवस्था प्रदान करती है। तीन वर्ष या अधिक आयु के बच्चों हेतु कार्यक्रम के प्रावधान में सरकार अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अपेक्षाकृत बहुत सीमित भूमिका होती है। लगभग 70 प्रतिशत देशों में 3 वर्ष की अधिकारिक आयु पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए मानी जाती है।

पिछले तीन दशकों से दुनिया भर में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की पंजीयन संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। जो 1970 के दशक में मध्य में 44 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004 में लगभग 124 मिलियन पहुँच गई। पूर्व प्राथमिक सकल पंजीयन अनुपात (जी ई आर) कुल पंजीयन को व्यक्त करता है, जिसमें आयु अनापेक्षित होती है, परंतु प्रत्येक देश की अधिकारिक आयु समूह की जनसंख्या (विशिष्ट रूप से 3 से 5) का एक प्रतिशत शामिल होता है। वर्ष 1975 और 2004 के बीच वैश्विक जी ई आर दोगुना से भी अधिक था अर्थात् लगभग 17 प्रतिशत से 37 प्रतिशत पर था। विकसित एवं संक्रमणशील देशों के बीच का अनुपात 1970 में 40 प्रतिशत था जो 2004 में बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया। विकासशील देशों के बीच में पूर्व प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से निम्नतम रही: वर्ष 1975 में पूर्व प्राथमिक संस्थानों में यह पंजीयन का सम्मिलन 10 में एक बच्चे से भी कम था जो वर्ष 2004 तक यह पंजीयन 3 में से एक (32 प्रतिशत) बच्चे तक पहुँचा। वर्ष 1991-2004 के दौरान, दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध आँकड़ों वाले 81 देशों में 5 में से 4 देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि हुई।

पिछले तीन दशकों से दुनिया भर में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की पंजीयन संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।

चित्र 4.1 1970–71 से 2003–04 तक, पूर्व-प्राथमिक सकल पंजीयन अनुपात में क्षेत्रीय प्रवृत्ति

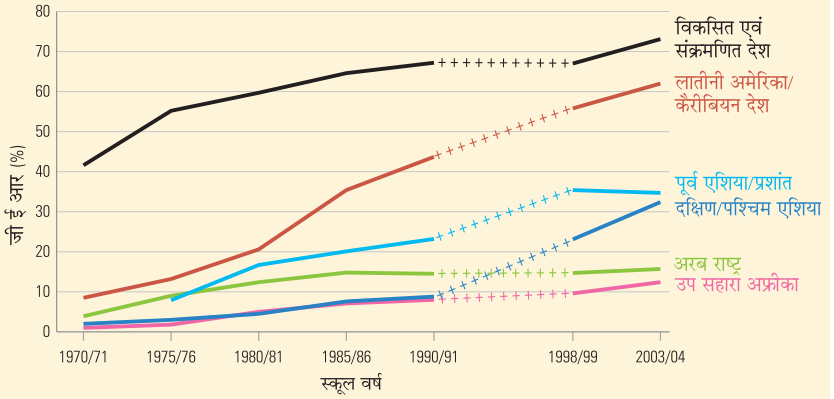

सूचना : टूटी हुई रेखाएं, नए वर्गीकरण के कारण, आँकड़ा शृंखला में एक अवरोध को इंगित करती हैं।
स्रोत : देखें अध्याय 6, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में

अधिकतर क्षेत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में बढ़ रहे हैं

यहाँ पर 1970 के दशक के दौरान बहुत ही स्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताओं वाली प्रवृत्ति देखने में आती है। लातीनी अमेरिका तथा कैरीबियन, जिन्होंने सुदृढ़ वृद्धि देखी है, में तीन चौथाई देशों में पूर्व प्राथमिक जी. ई.आर.एस 75 प्रतिशत से ऊपर है जबकि उप सहारा अफ्रीका में 1970 के दशक में एक स्थिर वृद्धि के बावजूद आधे देशों का अनुपात 10 प्रतिशत से भी कम है। अरब राष्ट्रों में 1980 के दशक के बाद से व्याप्ति पर्याप्त स्थिर है। जी ई आर पूरे एशिया में ध्यान देने योग्य विस्तारित हुई है। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में अधिकतर देशों में अब उनके एक तिहाई से लेकर आधे बच्चे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में पंजीकृत हो रहे हैं (चित्र 4.1)।

वर्ष 1999 से, पूर्व प्राथमिक पंजीयन बढ़ोत्तरी विशिष्ट रूप से उप सहारा अफ्रीका (जहाँ पंजीयन की संख्या 43.5 प्रतिशत बढ़ी है), कैरीबियन (43.4 प्रतिशत) और दक्षिण एवं पश्चिम एशिया (40.5 प्रतिशत) सुदृढ़ हुई है। यद्यपि उप सहारा अफ्रीका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पंजीयन की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है; लेकिन इस क्षेत्र की औसत जी.ई.आर में उछाल नहीं आया, क्योंकि जनसंख्या की सतत् उच्च वृद्धि दर है।

विकसित देशों के लिए 1999 से 2004 में औसत जी ई आर में साधारण (4 प्रतिशत) वृद्धि हुई है और यही संख्या विकसित एवं विकासशील देशों में बढ़ी है जबकि संक्रमणशील देशों के लिए वृद्धि (18 प्रतिशत) अधिक सुदृढ़ हुई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पंजीयन की संख्या पूर्वी एशिया में 10 प्रतिशत घटी; मुख्यत: चीन ने प्रभावी विस्तारण की एक अवधि का अनुपालन किया (यहाँ पंजीयन 1976 में 6.2 मिलियन से बढ़कर 1999 में 24 मिलियन पहुँची, जहाँ बाद में 2004 में यह 20 मिलियन घटकर आ गई चूंकि जनसख्या में 0–5 की कमी आई)। विश्व के पूर्व प्राथमिक पंजीयन में 48 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। यह समानुपात 1999 तक अपरिवर्तित था।

महत्वपूर्ण रूप से यह विषमता ठीक उन्हीं क्षेत्र के देशों में विद्यमान है जो सामान्यत: राष्ट्रीय विकास स्तर से संबद्ध हैं। (उदाहरण के लिए उप सहारा अफ्रीका में क्षेत्रीय औसत केवल 10 प्रतिशत मारीशस तथा सिशेल्स में जी ई आर 100 प्रतिशत के करीब; पूर्वी एशिया में कंबोडिया में जी ई आर 10 प्रतिशत से भी कम, जबकि कोरिया गणराज्य, मलेशिया तथा थाइलैंड में लगभग सार्वभौम पंजीयन दर्ज किया गया। मध्य एशिया में, 1990 की गिरावट से कुछ भरपाई के बावजूद कोई भी देश अपने यहाँ के आधे से अधिक बच्चों को नामांकित नहीं कर पाए। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में वस्तुत: सभी देशों में जी ई आर 60 प्रतिशत से ऊपर और इनमें से आधों का अनुपात 100 प्रतिशत है।

30 प्रतिशत से कम जी ई आर वाले 52 देशों में से अधिकतर उप सहारा अफ्रीका तथा अरब राष्ट्रों से हैं। कुल मिलाकर सामान्यतौर पर हाल ही की प्रगति धीमी (विशिष्ट रूप से 5 प्रतिशत अंकों से कम) है। वर्ष 2004 में 30 प्रतिशत ऊपर के जी ई आर वाले 86 देशों में से 66 देशों का अनुपात वर्ष 1999 से बढ़ा है। तीव्र प्रगति (10 प्रतिशत अंक से अधिक) ब्राजील, क्यूबा, इक्वाडोर, मैक्सिको तथा जमैका में रिपोर्ट की गई थी और अधिकतर संक्रमणशील देशों ने खोई हुई स्थिति पुन: प्राप्त करनी शुरू कर दी है।

यद्यपि लक्ष्य 1 परिमाणात्मक लक्ष्य नहीं है, लेकिन अनेक देशों ने स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 2010 से या 2015 के लिए अपनी राष्ट्रीय योजना में कम से कम 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों का प्रावधान है। अपेक्षाकृत उच्च पूर्व प्राथमिक जी ई आर वाले देशों ने उद्देश्य के रूप में 2015 तक सार्वभौम पूर्व स्कूल की ओर पंजीयन का लक्ष्य स्थापित किया है। चिली एवं मैक्सिको में ऐसा वर्तमान जी ई आर एस 50 प्रतिशत से ऊपर का है, उदाहरण के तौर पर ऐसा ही भारत, कजाकिस्तान तथा पैरागुवे ने किया है जिन सब का जी ई आर 40 प्रतिशत से नीचे का है। पिछली वृद्धि दर को देखते हुए, इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना, बिना महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रयासों के शायद संभव नहीं हो सकता है।

अधिकतर क्षेत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में बढ़ रहे हैं कुल मिलाकर स्त्री एवं पुरुष जी ई आर का अनुपात 0.97 है। उच्च विषमता वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति उभर कर आई है, विशेष रूप से; अरब राष्ट्रों में, जहां लिंग समानता सूचकांक 1999 में 0.76 की तुलना में 2004 में 0.87 था। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया भी 1999 से 2004 में 0.87 था। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया भी 1999 से 2004 में लिंग समानता की दिशा में बढ़ा है। कैरीबियन तथा अनेक प्राशांत-क्षेत्रीय भू भागों में लड़कियों के पक्ष में हल्की असमानता दर्शाई है। इनमें से अनेक देशों में लड़कियों के पक्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर में भी असमानता प्रदर्शित की है। कमतर जी पी आई वाले देशों में अफगानिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान तथा यमन हैं।

परिवार सर्वेक्षण ई सी सी ई हेतु सीमित पहुंच वाले समूहों पर प्रकाश डालते हैं

परिवार सर्वेक्षण सीधे लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित हैं और शैशवकालीन प्रावधान की एक अधिक विस्तृत तस्वीर उपलब्ध कराते हैं, अपेक्षाकृत सरकारी प्रशासन द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गए पूर्व प्राथमिक स्कूल आँकड़ों से। जिन तिरेपन देशों के सर्वेक्षण आँकड़े उपलब्ध हैं उनमें अधिकतर में लिंग अंतराल अपेक्षाकृत (10 प्रतिशत से कम) छोटा है। लेकिन तुलनात्मक रूप से शहर – ग्रामीण विभेद कहीं अधिक व्यापक है और (केवल जमैका को छोड़कर) सदैव ही ग्रामीण

चित्र 4.2–3 एवं 4 वर्ष की आयु में देखभाल तथा अधिगम कार्यक्रमों के लिए उपस्थिति दर में परिवारिक समृद्धि विषमता

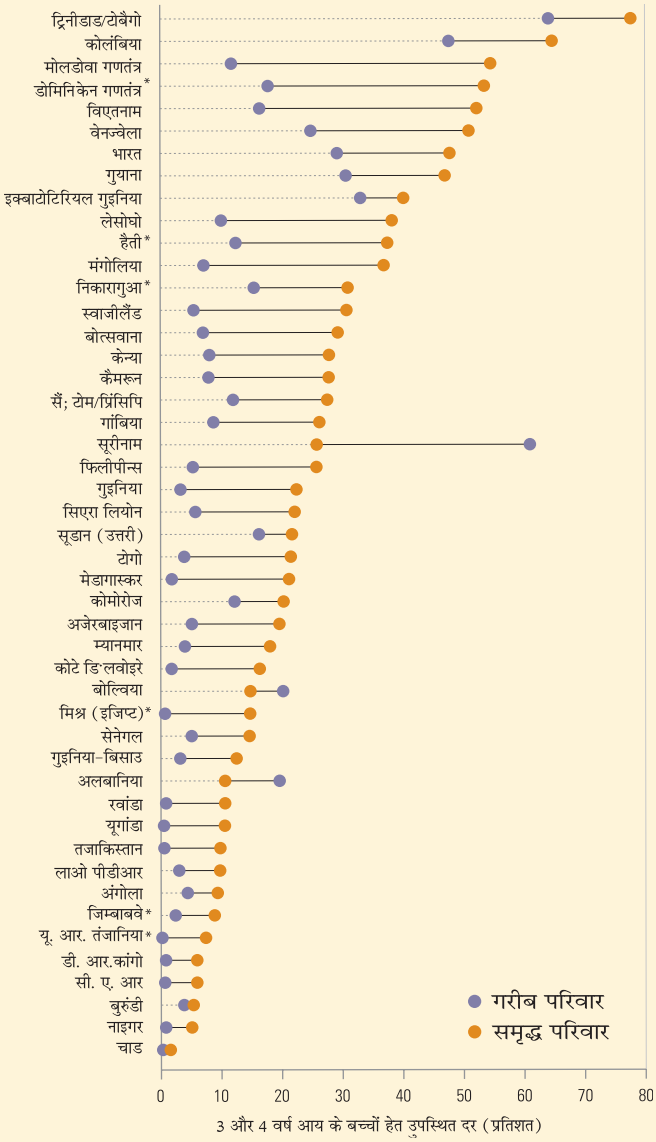

स्रोत : देखें, अध्याय 6, पूर्ण ई एफ ए रिपोर्ट में

बच्चों का नुकसान रहता है। बहुत सारे देशों में, ग्रामीण बच्चों को प्रारंभिक बालपन प्रावधान हेतु पहुँच का समानुपात शहरी बच्चों की अपेक्षा बीस प्रतिशत अंक तक कम रहता है। कुछेक अपवादों को छोड़कर धनी परिवारों के बच्चों की ई सी सी ई उपस्थिति दर गरीब परिवारों के बच्चों की अपेक्षा उच्च होती है। (चित्र 4.2)। एक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त माता के बच्चों के द्वारा ई सी सी ई में भाग लेने की संभावना मूल रूप से बढ़ जाती है। बिना जन्म तिथि प्रमाण पत्र वाले बच्चे और टीकाकरण रिकार्ड आदि तक कम पहुँच वाले बच्चों की ई सी सी ई कार्यक्रम में कम उपस्थिति रहती है। जो बच्चे बौनापन (आयु के अनुसार लंबाई में कमी) युक्त हैं, ऐसे बच्चों की भी ई सी सी ई में भागीदारी की दर अन्य बच्चों की तुलना में कम होती है।

ई सी सी ई कार्यबल

विकासशील देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों की प्रवेश योग्यता उच्च विविधता पूर्ण है और यह निम्न माध्यमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक की है। सामान्यत: औपचारिक प्रवेश योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को बहुत थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो सदैव प्राथमिक शिक्षकों से थोड़ी कम ही होती है। कुछ देशों में, लेसोथो और यूगांडा सहित, ने हाल ही में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया है।

औद्योगिकीकृत अधिकतर देशों में, शिक्षक की प्रवेश योग्यता प्राय: तृतीयक स्तर की और विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ अपेक्षित होती है। शैशवकालीन देखभाल प्रावधान एवं शिक्षा संघटक प्राय: अलग होते हैं और पृथक कर्मचारी नीतियों को बढ़ाते हैं। उच्च प्रशिक्षित शिक्षा शास्त्री अप्रशिक्षित बाल सेवा कर्मी के साथ कार्य करते हैं जिनमें से अधिकतर अंशकालिक या स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता होते हैं।

लगभग अधिकतर पूर्व प्राथमिक शिक्षक स्त्रियाँ हैं जो एक प्रकार से ई सी सी ई को परम्परागत मातृत्व भूमिका के विस्तार की संकल्पना या अवबोधन को प्रतिबिंबित करता है। ओ ई सी डी देशों में, 20% से अधिक पूर्व प्राथमिक शिक्षक 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। कम आय वाले देशों में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ताजा विस्तार होने के कारण प्राथमिक स्तर की अपेक्षा अधिक युवा शिक्षकों को अधिक अनुपात में रूपान्तरित करते हैं।

उपलब्ध आँकड़ों सहित अधिकतर देशों (मुख्यत: मध्य आय वालों) में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का वेतन लगभग समान होता है। वेतन असमानता केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों के बीच विद्यमान है और उनके साथ भी जो औपचारिक प्रणाली में काम कर रहे हैं और वे अनौपचारिक कार्यक्रमों में प्राय: अधिक छोटे बच्चों के साथ कार्यरत हैं। यूनाइटेड किंगडम सहित कुछ देश ई सी सी ई में एक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को प्रस्तुत करने के साथ शिक्षा एवं देखभाल कर्मियों के बीच इस दूरी को खत्म करने के करीब पहुँच रहे हैं।

कुछ देश एक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को प्रस्तुत करने के साथ शिक्षा एवं देखभाल कर्मियों के बीच इस दूरी को खत्म करने के करीब पहुँच रहे हैं।

बहुत सारे देश प्राथमिक शिक्षकों को सुयोग्य बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित, संशोधित तथा बेहतर बना रहे हैं। मिस्र में अनेक विश्वविद्यालयों ने पूर्व प्राथमिक तथा सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम किंडर गार्डन शिक्षकों के लिए विकसित किए हैं। अन्य देशों ने भी अपने पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम हाल ही में तैयार किए हैं। बहुत से सेवा में प्रशिक्षण को सुदृढ़ बना रहे हैं। मोरक्को के प्रत्येक राज्य में एक पूर्व स्कूल संसाधन केन्द्र है जो सतत् शिक्षा एवं शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय उपाय उपलब्ध कराते हैं। त्रिनीडाड व टोबैगो में सेरवल (SERVOL) प्रशिक्षण केंद्र अन्य कैरेबियन द्वीपों को सेवा में प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

भाग V. छोटे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों की रचना

- सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देना
- माता-पिता के साथ काम करना
- मातृ भाषा में शुरू करना
- बिना रूढ़िबद्ध धारणा के लिंग
- सम्मिलित करके सापेक्ष महत्व
- स्कूल के लिए तैयार करना

शैशवकालीन कार्यक्रम माता-पिता तथा अन्य की देखभाल के प्रयासों का समर्थन देते एवं संपूर्ण बनाते हैं। प्रभावशील होने के लिए, इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से संस्कृति के लिए संवेदनशील, भाषा की विविधता का सम्मान करने वाले तथा विशेष आवश्यकता के साथ रहने वाले बच्चों या अन्य आपातस्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए अनुकूल होने चाहिए। यह भाग कुछ एक प्रभावशाली कार्यक्रमों के प्रमाणकों की समीक्षा करता है जो बच्चों को जन्म से उनके प्राथमिक स्कूल में प्रवेश तक समर्थन प्रदान करते हैं।

सेनेगल, टौबाब डायलॉव में एक मछुआरा गाँव में एक किंडरगार्टेन शिक्षिका बच्चों का ध्यान खीचं रही हैं। यहां के अधिकतर निवसी गरीबी रेखा से नीचे के है।

छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रमों की रचना करना विशेष रूप से जटिल है। उन्हें स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सेवाओं से समिश्रित शैक्षिक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है, जो उनके समग्र विकास को सुनिश्चित बनाएँ। शिक्षा शास्त्र को निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि से अधिगृहीत किया जाना चाहिए। और बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में, उनके माता-पिता को सहारा प्रदान करने में सहायतापूर्ण भी हो। शैशवकालीन प्रावधान का कोई भी एक प्रतिरूप सभी देशों में सार्वभौमिकता से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, पूरी दुनिया में अभिभावकत्व भिन्नतापूर्ण है। शैशवकालीन कार्यक्रम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन भिन्नताओं को मान्यता दें और यह सुनिश्चित करें कि उस देश के संदर्भ में कार्यक्रम औचित्यपूर्ण हो तथा उस समूह के लिए भी जिसके लिए तैयार किया गया है।

© EPA/NIC BOTHMA/SIPA

जनकीय (अभिभावक) कार्यक्रम : घर में प्रारंभ होता है

माता-पिता या अभिभावक (या अन्य अभिरक्षक या देखभाल कर्ता) बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं और छोटी आयु समूह के लिए देखभाल का मुख्य केन्द्र घर होता है। एक बच्चे के सहजात विकास एवं समाज-भावनात्मक बेहतरी के लिए घर के पर्यावरण का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। सामग्री के पाठन एवं चित्रों तथा कला की उपलब्धता एक बच्चे के देखभालकर्ता के ध्यान देने, स्मरण तथा नियोजन के सहजात परिणाम को पूरित करती है। घर के माहौल को समर्थन देने का सबसे बढ़िया तरीका सीधे माता-पिता के साथ काम करना है।

अभिभावकत्व कार्यक्रम भिन्नतापूर्ण एवं निगरानी हेतु कठिन होते हैं। घर पर मुलाकात या भेंट कार्यक्रम अलग-अलग अभिभावकों के लिए आमने-सामने का समर्थन प्रदान करता है। चूँकि प्रतिरूप बहुत महँगा तथा उत्तम भी है अत: जोखिम ग्राह्य परिवार के साथ लक्षित हस्तक्षेप के रूप में सीमित प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए, डबलिन में कम्युनिटी मदर्स प्रोग्राम के लिए लक्ष्य समूह में एकल और/या किशोर माता-पिता, शरणार्थी, शरणागत तथा प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। समुदाय की स्वैच्छा कर्मियों, जिन्हें नर्सों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, वे माता-पिता या अभिभावकों के पास माह में एक बार भेंट करने जाती हैं और विशेष रूप से तैयार किया गया कार्यक्रम प्रयुक्त करती हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवा, पोषण तथा संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मूल्याकंन यह दर्शाते हैं कि माता तथा बच्चों, दोनों ही में, आत्मउत्साह, परस्पर क्रिया तथा बच्चों के अधिगम अनुभव हेतु समर्थन के लिए महत्वपूर्ण रूप से लाभदायी सिद्ध हुआ है। कुछ अभिभावक समूहों का गठन सामान्यत: व्यावसायिकों द्वारा अन्य सामान्य उपाय है जिनसे बच्चे की देखभाल एवं शिक्षा की जानकारी बाँटी जा सकती है।

स्थानीय समुदाय भी घर या समुदाय आधारित बाल देखभाल के माध्यम से छोटे बच्चों तथा परिवार वालों के समर्थन देने की एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोलंबिया में वे होगेयर्स कम्युनिटेयर्स प्रोग्राम एक प्रमुख कल्याण प्रयास बन गया है जो जन्म से 6 वर्ष की आयु के एक मिलियन से अधिक बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रारंभ में इसकी रचना गरीब परिवारों में पोषण को सुधारना था, लेकिन अब इसके साथ बच्चों की देखभाल भी सम्मिलित है। वांछनीय परिवार एक 'समुदाय माता' का चुनाव करते हैं जो 15 बच्चों के लिए अपने घर में जगह बनाती है। यह कार्यक्रम गरीबतम बच्चों तक पहुँचता है और प्रतिदिन उन्हें भोजन उपलब्ध कराकर उनकी शारीरिक वृद्धि को जोश प्रदान करता है। 13 से 17 वर्ष के जो बच्चे कभी एक बार इस कार्यक्रम में भागीदारी हुए हैं वे बहुत हद तक स्कूल में होते हैं तथा पिछली ही कक्षा में दोबारा पढ़ने की नौबत अपेक्षाकृत उनसे बहुत कम संभावित होती है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था।

शिक्षा शास्त्र और पाठ्य–क्रम : शिक्षण के लिए आधार स्थापित करना

तीन से छह वर्ष आयु समूह के बच्चों हेतु, ई सी सी ई का सर्वाधिक सामान्य स्वरूप केन्द्र आधारित प्रावधान है। इस अनुभव को एक सकारात्मक स्वरूप देना संकटापन्न होता है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि यह व्यवहार उस आयु समूह के बच्चे के लिए और सांस्कृतिक वातावरण के लिए अनुकूल साबित हो। मातृभाषा में सीखना अधिक प्रभावी होता है। ठीक इसी समय पर, एक आयोजित अधिगम के प्रति पहला खुलाव या उद्घाटन का सुअवसर होता है तथा परम्परागत लैंगिक भूमिका के प्रति चुनौती भी है। अंतत: कार्यक्रम को अंतर्विष्ट तथा परिस्थितियों

गरीबी भाषा विकास को भी प्रभावित करती है

का सामना करने वाला- जैसे कि सशस्त्र संघर्ष युक्त देश के बच्चों से तालमेल वाला होना चाहिए (बाक्स 5.1)।

विकसित एवं विकासशील, दोनों ही देशों के अनुसंधान गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के उपायों और असल में एक बच्चे के विकास के प्रत्येक पक्ष के बीच एक सतत् सकारात्मक संबंध पर प्रकाश डालते हैं। यद्यपि, संरचनात्मक विशिष्टताएं जैसे कि कक्षा का आकार एवं कर्मचारी – बच्चों का अनुपात आदि एक अच्छी प्रारंभिक बालपन पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अनुसंधान दिखाते हैं कि कर्मचारियों तथा बच्चों के बीच परस्पर क्रिया की बढ़ी हुई स्थिति बच्चों की बेहतरी के लिए अति महत्वपूर्ण भविष्यसूचक है।

17 देशों में, आई ई ए[7] पूर्व प्राथमिक परियोजना ने यह देखा कि चार वर्ष की अवधि पर प्राप्त अनुभवों ने सात वर्ष की आयु में बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, यह पाया गया कि जब चार वर्ष आयु वाले बच्चों ने उन कार्यक्रमों में भाग लिया जहाँ बच्चे की रूचि द्वारा अभिप्रेरित असंरचनात्मक क्रियाकलाप प्रचुरता से थे, तो उन्होंने 7 वर्ष की आयु में उन प्रतियोगियों से बेहतर भाषाई अंक प्राप्त किए जिन्होंने कौशल विकास के अधिक क्रियाकलापों में भाग लिया था जैसे कि साक्षरता एवं संख्या गणना आदि। बच्चे से परस्पर क्रिया की बारंबारता, बच्चों के क्रियाकलाप में वयस्कों की भागीदारी तथा शिक्षक का शैक्षिक स्तर आदि निश्चित ही बाद में भाषाई निष्पादन के लिए सकारात्मक रूप से संबद्ध होते हैं।

लिंग : चुनौतीपूर्ण रूढ़िबद्ध धारणा

मर्दानापन या जनानापन के बारे में अवधारणा या अवबोध प्रारंभिक बालपन में ही स्थान पा लेता है। इस आयु समूह के लिए पाठ्यक्रम प्राय: लिंग-उदासीन नहीं होते हैं। पुस्तकों की प्रवृत्ति पुरुष एवं स्त्री विशिष्टिता के बीच स्पष्ट रेखा खींचती है। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो अक्सर उन्हें रूढ़िबद्धता को अनुपालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षकों की वृत्ति भी लड़कों एवं लड़कियों के बीच परस्पर क्रिया या प्रश्न पूछने पर भिन्न अभिव्यक्ति वाली होती है।

शैशवकालीन कार्यक्रमों का अधिग्रहण, लिंग भूमिका को चुनौती देने वाला किया जा सकता है। शिक्षा शास्त्र, शिक्षण तथा खेल-सामग्री आदि को भिन्न महत्व या मान के साथ प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वीडन ने एक ऐसे दल का गठन किया जो पूर्व प्राथमिक स्कूलों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के तरीकों के लिए बहस को प्रोत्साहित करे और पूर्व प्राथमिक स्कूल को फंड देने वाले माध्यम ने कर्मियों से यह कामना की थी कि वे इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक उपायों को विकसित करें। प्रशिक्षणों को चाहिए कि वे शिक्षकों को अपनी व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य करें। शैशवकालीन कार्यक्रमों में पुरूषों को काम करने हेतु प्रोत्साहित करने से भी इस परिकल्पना या मान्यता को चुनौती देने में मदद मिल सकती है कि स्त्री ही एकमात्र देखभालकर्ता है और साथ ही बच्चे को बड़ा बनाने की प्रक्रिया में पिता को अधिकाधिक सम्मिलन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

7. शिक्षा उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन

बॉक्स 5.1: आपात्कालिक स्थितियों में रहने वाले बच्चे

नरमी से अच्छा बनाना

अफ्रीका और एशिया में छह में से पाँच देशों में संघर्ष जारी है, जो आम जनसंख्या के लिए एक नाटकीय दुष्परिणाम है। संघर्ष के कारण लगभग 24 मिलियन लोग अपने ही देशों में घर से बेघर हैं। संघर्ष की यह प्रकृति निम्न सघनता की ओर बढ़ते हुए गृह युद्ध का रूप लेने से सेनाओं की अधिक मात्रा में निजी या अर्ध सैनिक बलों और बाल सैनिकों पर भरोसा बढ़ रहा है। बच्चों के जीवन में कुछ स्थिरता लाने के लिए शिक्षा अनिवार्य है।

उत्तरी इथोपिया में, अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (आई आर सी) द्वारा शिमेल्बा शरणार्थी शिविर में एक प्रोत्साहक कार्य चलाया जा रहा है जहाँ बच्चों को अच्छा बनाने तथा स्वस्थता को प्रोत्साहित किया जाता है। शिविर के एक विशिष्ट आँगन में पूर्व स्कूल वालों के लिए हीलिंग क्लास रूम इनीसिएटिव ने एक 'चिल्ड्रेन्स विलेज' खोला है। इन्हें प्रतिदिन का भोजन आपूर्ति केन्द्र उपलब्ध कराता है। कक्षों की साज-साज्जा बच्चों का स्वागत करती है। बाल केन्द्राभिमुख अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत कला, सगीत तथा पूर्व-साक्षरता कक्षाएं सम्मिलित हैं। ठीक इसी दौरान, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़/वयस्क शिक्षक माताओं को लाभ पहुँचाती हैं।

अनेक उप सहारा अफ्रीकी देशों में, यूनीसेफ के बाल मैत्री स्थल देखभाल के अनेक आयामों को समन्वित करते हैं तथा माताओं एवं बच्चों के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। लाइबेरिया में, यह स्थल माताओं को स्तनपान कराने के लिए एक आरामदेय जगह उपलब्ध कराते हैं जबकि शैशवकालीन विकास कक्षाओं में सफाई-स्वच्छता, पोषण तथा खेल का महत्व जैसे घटक सम्मिलित हैं। इसके साथ अन्य सेवाएं भी स्वास्थ, पोषण, प्रारंभिक उत्प्रेरण तथा अधिगम, जल स्वच्छता एवं सफाई तथा छोटे बच्चों की संरक्षा से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

प्रारंभिक भाषाई विकास समर्थन

अनुसंधान लगातार यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक साक्षरता अनुभव-जैसे बच्चों हेतु पुस्तकें पढ़ना, घर पर भाषा विकास, काफी संख्या में पुस्तकें होना, आदि पढ़ाई के परिणामों एवं स्कूल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड किंगडम में बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में पाठन के अधिगम में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पूर्व स्कूल के दौरान लिखित सामग्री से बच्चों का प्रभावन है। गरीबी भी भाषाई कौशल विकास को प्रभावित करती है। युनाइटेड स्टेट्स में 4 वर्ष की आयु वर्ग में कल्याण प्राप्त, कामकाजी-वर्ग तथा व्यावसायिक परिवारों के बच्चों द्वारा अनगिनत शब्द भिन्नतानुसार सुने जाते हैं। तीन वर्ष की आयु में व्यावसायिकों के बच्चों का शब्द भंडार कल्याण प्राप्त बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। यह बच्चे की अनावृत्ति या प्रभावन महत्ता को उजागर करता है। विशेष रूप गरीब समाज आर्थिक पृष्ठभूमि वालों से लेकर प्रारंभिक आयु में समृद्ध भाषाई स्थापना में बच्चों के अधिगम स्तर पर झलकता है।

यद्यपि, बहुत सारे बच्चे बहु भाषाई समाज में वृद्धि करते हैं तथापि सामान्य तौर पर पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों में पूरी दुनिया भर में अधिगम (शिक्षण) प्रशासकीय या अधिकृत भाषा में ही होता है। यद्यपि जो बच्चे 6 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल में अपनी मातृ भाषा में पढ़ते हैं, वे अधिकृत भाषा में पढ़ाई शुरू करने वालों की अपेक्षा बढ़िया दक्षता (निष्पादन) दर्शाते हैं।

हालांकि, द्विभाषी मॉडल केवल कुछ शेष हैं और दोनों के बीच काफी अंतर है। कुछ लोगों का दावा है कि ये खर्चीले हैं तथा इन्हें क्रियान्वित करना कठिन है तथा सामाजिक एवं राजनैतिक विभेद के जोखिम को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कंबोडिया, मलेशिया, म्यानमार – पपुआ न्युगिनी तथा वियेतनाम सहित कई देशों ने द्विभाषी प्रारंभिक बालपन कार्यक्रमों को विकसित किया है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्ष की व्यावहारिकता को प्रभावित भी किया है। पपुआ न्युगिनी में, जो विश्व का सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है, वहाँ अभिभावकों ने स्थानीय सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करते हुए 1970 में, देशी भाषा का दो वर्षीय पूर्व स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया था। 1995में सरकार ने औपचारिक स्कूल प्रणाली को प्राथमिक स्कूल के प्रथम तीन वर्षों के लिए देशी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जिसे धीरे-धीरे अंग्रेजी में अंतरित करना है। आज इस देश की शिक्षा प्रणाली में लगभग 350 भाषाएं प्रयुक्त की जा रही हैं।

द्विभाषी कहानी-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप भी बच्चों में साक्षरता कौशल विकास में सहायक हो सकते हैं, जिसे एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित किया जा सकता है। बहुभाषाई कर्मचारी भर्ती एक अन्य आशाजनक रणनीति है। अनेक यूरोपीय देशों ने अपने नए प्रवासित छात्रों एवं उनके अभिभावकों के साथ पूर्व स्कूली स्थापना में काम करने हेतु द्विभाषी सहायकों को भर्ती किया है। भाषाई अल्पसंख्यता वाले अभिभावकों को सूचित किए जाने की जरूरत है कि उनके बच्चों को शैशवकालीन कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर हैं तथा उनके गृह में भाषा एवं संस्कृति की संरक्षा का मूल्य या महत्व है।

सम्मिलित उपागम : विषेश आवश्यकताएं तथा आपात्कालिक स्थितियाँ

विशेष आवश्यकताओं वाले 85% से अधिक बच्चे विकासशील देशों में रहते हैं जहाँ पर बचपन की अंधता तथा श्रवणक्षति जैसी इंद्रिय गोचर समस्याएं असमानुपातिक ढंग से उच्च हैं। इंद्रिय एवं गैर इंद्रिय विकारों संबंधी जांच-पड़ताल के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छोटे बच्चों के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की ओर बढ़ा जा सकता है। शैशवकालीन कार्यक्रमों से भी कुछ विशेष बच्चों का मुख्यधारा के स्कूल में अंतरण हेतु प्रोत्साहित किया सकता है। चिली में शैशवकालीन हेतु एक सम्मिलित करने वाला उपागम है जिसके अंतर्गत नर्सरी स्कूल के शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम है। शिक्षकों के लिए मासिक समाचार पत्रिका तथा पहियाकुर्सी एवं सुनने के यंत्र हेतु फंड की उपलब्धि से मुख्य धारा केन्द्रों में विशेष आवश्यकता वाले छोटे बच्चों की देखभाल में सुधार आया है। अधिकतर ओ.ई.सी.डी देश भी सम्मिलित उपागम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो बाल अधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की दिशा में हैं।

प्राथमिक स्कूलों हेतु अंतरण को सुसाध्य बनाना

अच्छी गुणवत्ता की ई.सी.सी.ई केवल अपने आप में एक अंत नहीं है। यह सर्व शिक्षा (ई एफ ए) लक्ष्यों से मान्य अनुवर्ती शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नींव भी हैं। इसलिए यह बच्चों को प्राथमिक स्कूलों के लिए तैयार करने हेतु ही महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ बच्चे शारीरिक, सामाजिक एवं सहजात रूप से विकास पाते हैं, बल्कि ये प्राथमिक स्कूलों के लिए स्वत: ही एक सर्वोत्तम अधिगम स्थितियाँ प्रदान करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के साथ ई.सी.सी.ई को और अधिक निकट से जोड़ने का एक पथ है।

इस प्रकार के एकीकरण विखंडन से उबरने की चाहत के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं और बच्चों के लिए अंतरण को सुगम बनाते हैं। इस उपागम के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल तथा ई सी सी ई के शिक्षा घटकों के बीच सुदृढ़ संबंधों का गठन शामिल है और प्राय: एक प्रशासकीय ढांचा बनाते हैं। सामान्यत: शिक्षा मंत्रालय ई.सी.सी.ई तथा प्रथामिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यद्यपि इस प्रकार के प्रयास बच्चों के लिए सातत्यता को बढ़ा सकते हैं और अपेक्षाकृत एक व्यापक कल्याण समन्वित समग्र उपागम, स्वास्थ्य तथा देखभाल से केवल शिक्षा पर केन्द्रीकृत होने के जोखिम के जोर को टाल सकते हैं।

एकीकृत ई सी सी ई तथा प्राथमिक शिक्षा का दूसरा पहलू, पाठ्यक्रम की निरंतरता को सुनिश्चित करना है। कुछ देशों में पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु एकीकृत पाठ्यक्रम है। केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप के तीस देशों ने चरण-दर-चरण पाठ्यक्रम का अनुपालन किया है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के पहले चार वर्षों के दौरान कोई ग्रेड/कक्षा नहीं होती थी, ताकि बच्चे अपने आयाम में प्रगति कर सकें। जमैका में पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक अंतरण हेतु ठीक यही सिद्धांत पालन किया जाता है। भारत में बोध शिक्षा समिति तथा कोलंबिया के ऐसक्युला नुयेवा बहु ग्रेड/कक्षाई एक सक्रिय पाठ्यक्रम एवं पाठ योजना का उपयोग करते हैं जो छात्रों की विभिन्न क्षमताओं एवं रूचियों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

माता-पिता को अधिकाधिक सम्मिलित करके निरंतरता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पाकिस्तान में, गरीब ग्रामीण समुदाय के अभिभावक स्थानीय गीतों एवं कहानियों को सीखने में मदद करते हैं। फ्रांस में समुदाय – बिचौलिये कम आय वाले पड़ोस में शिक्षकों के साथ संवाद को बेहतर बनाने हेतु अभिभावकों के साथ काम करते हैं। जहाँ पर पूर्व विद्यालय में पहुँच का अभाव होता है, वहाँ अंतरण से सरल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्कूलों में दौराकर बच्चों को उनके भावी पर्यावरण से चिर-परिचित कराना या स्कूल में प्रवेश से पूर्व के महीनों में बच्चों के छोटे समूह के लिए मुफ्त खेल गतिविधियों का आयोजन करना आदि, किया जा सकता है। ■

माता-पिता को अधिकाधिक सम्मिलित करके निरंतरता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भाग VI. सुदृढ़ ई सी सी ई नीतियों को प्रोत्साहित करना

प्रारंभिक आयु में, यदि बच्चे अच्छी किस्म की देखभाल एवं अधिगम अवसरों से लाभ पाते हैं तो सरकारों को अन्य पणधारियों के साथ भागीदारी में निश्चित रूप से उनके लिए ठोस नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना चाहिए। तीन प्रमुख क्षेत्र ध्यान चाहते हैं: अभिशासन, गुणवत्ता और वित्त – जिसके अंतर्गत प्रतिकूल परिस्थिति वालों को लक्षित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाओं के साथ साझेदारी में सम्मिलित होना भी शामिल है ।

मैक्सिको, चिआपास में सड़क पर

© Miquel DEWEVER-PLANA / AGENCE VU

- अनुकूल नीति वातावरण तैयार करना
- राष्ट्रीय शैशवकालीन नीतियों का विकास करना
- सभी प्रस्थापनाओं में गुणवत्ता नियामन करना
- निजी कर्ताओं को शामिल करना
- अत्यधिक सुकुमार एवं प्रतिकूल परिस्थिति वालों तक पहुँच बनाना
- वित्तीय रणनीतियाँ तैयार करना
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाओं के साथ साझेदारी

आशाजनक संकेत

विकासशील देशों की सरकारों ने सामान्यत: सर्व शिक्षा (ईएफए) लक्ष्यों सहित, शैशवकालीन नीतियों पर; प्राथमिक शिक्षा एवं लिंग समानता की अपेक्षा सीमित ध्यान दिया है। पैंतालीस देशों की नीतियों के अभिलेखों की समीक्षा से यह बात प्रकट होती है कि 8 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण को सम्मिलित करने हेतु कुछ एक देशों ने ही समग्रात्मक उपागम अपनाये हैं। प्रतिकूल परिस्थिति वाले (लाभ रहित), जोखिम (सुकुमार) तथा विकलांग बच्चों के लिए एवं राष्ट्रीय ई सी सी ई नीति का अभाव सही रूप से अवसर गँवाने का प्रतिनिधित्व करती है। जहां कहीं भी ई सी सी ई थोड़ा ध्यान पाती है, वहां भी 3 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं। इस प्रकार से यहां पर भी छोटे बच्चों के लिए सुअवसर या सुयोग गायब है।

हालांकि; यहां पर कुछ आशाजनक संकेत हैं। ई सी सी ई के लाभों पर अनुसंधान हेतु संस्थान उभर रहे हैं, जिन्होंने इसे शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पहले चरण के रूप में समाविष्ट किया है और सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय ई सी सी ई नेटवर्क और अधिक अनुकूलतम नीति वातावरण में भागीदारी कर रहे हैं। बढ़ती संख्या में सरकारों ने विस्तृत सुस्पष्ट और व्यापक राष्ट्रीय ई सी सी ई नीतियों की शुरुआत की है जिनके अंतर्गत छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा, जल, स्वच्छता, साफ – सफाई तथा कानूनी संरक्षा के आवरण सम्मिलित हैं। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रपत्र प्रत्येक क्षेत्र के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कर सकता है, जिसमें फंडिंग प्रतिबद्धताएं भी शामिल है। इस प्रकार की नीतियों को निशिचत रूप से पूरा करने के लिए कानूनी विधान में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

ई सी सी ई ने राजनैतिक महत्व कैसे प्राप्त किया?

ई सी सी ई के प्रति बढ़ता ध्यान कई एक घटकों का परिणाम है–

- ***ई सी सी ई उच्च स्तरीय राजनैतिक समर्थन*** एजेंडे पर आ सकता है। चिली, जमैका, जोर्डन, सेनेगल, थाईलैंड, विएतनाम सहित कई देशों के नेताओं ने हाल ही के वर्षों में शैशवकालीन को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया; जिसने नई राष्ट्रीय नीतियों, विस्तृत प्रावधानों, गुणवत्ता हेतु बढ़े हुए ध्यान तथा अतिरिक्त वित्तीय समर्थन हेतु मार्ग पशस्त किया।

- ***व्यापक पणधारों का आवेष्टन*** – से स्वामित्व एवं सहमति (जैसे कि घाना में) को बढ़ावा देने में मदद प्राप्त हुई। अभिभावकों को साथ जोड़ने से ई सी सी ई कार्यक्रम के लिए स्थानीय सामुदाय से समर्थन को बढ़ावा मिल सकता है।

- ***सरकारी साझेदारी*** – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, दानदाता संस्थाओं तथा गैर सरकारी सगठनों के साथ सरकार की साझेदारी से महत्वपूर्ण रूप से धन पैदा हो सकता है तथा उन परियोजनाओं के लिए तकनीकी समर्थन मिल सकता है जिन्हें बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है।

- ***ई सी सी ई नीतियाँ पंक्तिबद्ध करना*** – अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रगत विकास नीतियों के साथ पंक्तिबद्ध करना जोकि संसाधनों को उत्तोलित करने तथा ई सी सी ई एकीकरण को प्रोत्साहित करने का एक सामरिक उपाय है। घाना, युगांडा तथा जांबिया अपने पी आर एस पीज के साथ शैशवकालीन विकास को एकीकृत कर रहे हैं।

- ***विस्तृत कार्य योजनाएं*** – जिम्मेदारियों के विभाजन की व्याख्या करके तथा संसाधनों को बाँटकर एवं एक समय सीमा निर्धारित करने के द्वारा ई सी सी ई नीति क्रियान्वयन को सुकर बनाते हैं।

- ***संचार (माध्यम) अभियान द्वारा*** – बाल सेवा व्यवहारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की प्रक्रिया से ई सी सी ई हेतु ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, उदाहरण के रूप में; नवजातों तथा स्तनपान के बारे में, और बच्चों के लिए पाठन तथा पिता की भूमिका के महत्व के बारे में जानकारी प्रसारित करके।

नेतृत्व कौन करता है? ई सी सी ई में बहुसंख्यक क्षेत्र/खंड, कार्यक्रम तथा कर्ता शामिल होते हैं जो बहुधा समन्वय को एक चुनौती बना देते हैं।

अभिशासन मुद्दे

नेतृत्व कौन करता है? ई सी सी ई में बहुसंख्यक क्षेत्र/खंड, कार्यक्रम तथा कर्ता शामिल होते हैं जो बहुधा समन्वय को एक चुनौती बना देते हैं। अधिकतर देशों, विशेष रूप से लातीनी अमेरिका व यूरोप में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही एक या दो साल का पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं लेकिन ई सी सी ई के दूसरे स्वरूप में, विशेष रूप से तीन वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए दिए जाने वाले स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बाल एवं महिला आदि मामलों की चुनौतियाँ भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के तत्वाधान में आती हैं। बहुसंख्यक भागीदारों के सम्मिलित होने से भिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता उन एजेंसियों द्वारा एक साथ लाई जा सकती है, लेकिन यह भी विभिन्न मंत्रालयों के बीच झगड़ा पैदा कर सकता है। कुछेक देशों में कोई भी एक प्रशासकीय निकाय ई सी सी ई की प्रमुख जिम्मेदारी नहीं निभाता है। फलत: उपेक्षा की संभावनाएं बढ़ जाती है।

सरकारों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य मानक प्राप्त हों।

उपलब्ध सूचनाओं वाले 172 देशों में से लगभग 60% देशों में मंत्रालय सामान्यत: शिक्षा मंत्रालय तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को देखता या कार्यक्रमों को समन्वित करता है। लगभग 30% देशों में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी एक अन्य अधिकृत निकाय द्वारा निभाई जाती है जैसे कि एक राष्ट्रीय संस्थान या कोई उपराष्ट्रीय प्राधिकरण। बाकी बचे 10% देशों में गैर सरकारी संस्थाएं या निकाय प्रारंभिक बालपन कार्यक्रमों की एकमात्र पर्यवेक्षक होती हैं।

यद्यपि; बहुत सारे देशों में शैशवकालीन प्रशासकीय जिम्मेदारी आयु समूह के अनुसार बाँटी हुई है। 1980 दशक के अंतिम से निरंतर बढ़ती हुई संख्या के साथ (जिनमें ब्राजील, चिली, जमैका, कजाकिस्तान, न्युजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन तथा विएतनाम शामिल हैं) कई देशों ने जन्म के बाद बच्चों के लिए शिक्षा को एक अग्रणी मंत्रालय को सौंपा हुआ है। शैशवकालीन के मसले को शिक्षा मंत्रालय के अधीन रखने से छोटे बच्चों के अधिगम और प्राथमिक स्कूल में अंतरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन; चूँकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, अत: शिक्षा मंत्रालय की अफसरशाही के अंतर्गत ही संसाधन जुटाने एवं ध्यान रखने पर संघर्ष हो सकता है। एक अन्य चिंता का विषय यह है कि ई सी सी ई और अधिक औपचारिक एवं स्कूल जैसा बनने के दबाव में रहेगा।

इस महत्व को नकारते हुए कि नेतृत्व कौन करता है, बल्कि संस्थानों एवं सम्मिलित क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय प्रक्रम संसाधनों, मानकों, नियामकों, प्रशिक्षण तथा कर्मचारी-चयन आदि को एक साथ समेटने के लिए एक सामान्य दृष्टि को सक्षमता से प्राप्त करने हेतु मंच प्रदान करता है। अक्सर देखा जाता है कि समन्वय निकाय में कर्मचारियों की कमी होती है और सलाहकार छोटे बच्चों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता सीमित कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका इसमें असामान्य है क्योंकि उसकी राष्ट्रीय समन्वय समिति में अनेक मंत्रालयों, प्रशिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। ये सभी 5 एवं 6 साल के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कार्यक्रमों को तैयार करने में यह सहायक थे।

अक्सर ई सी सी ई को विकेन्द्रीकृत करने के लिए तर्क दिए जाते हैं जिससे कि समुदाय की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं एवं संसाधनों को प्रभावी व बढ़िया तरीके से अधिगृहीत किया जा सके। यद्यपि, व्यावहारिकता में यह असमान नीति क्रियान्वयन, आंकलन व गुणवत्ता के रूप में प्रकट हो सकता है। बहुत सारे संक्रमणशील देशों में 1990 दशक में विकेन्द्रीकरण ने समृद्ध शहरियों एवं गरीबतम ग्रामीण समुदाय के बीच गंभीर असामनता पैदा कर दी थी, जिसके कारण किंडर गार्टेन की गुणवत्ता एवं व्याप्ति में विकृति (ह्रास) को बढ़ावा मिला।

तब से यह बड़े पैमाने पर माना गया कि विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप से प्रभावी केन्द्रीय सरकार की निरीक्षण एवं नियामन से निरूपित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वीडन में, 1990 में फीस के नियंत्रणहीन करने के पश्चात पूर्व प्राथमिक स्कूल के लिए अधिकतम फीस तय कर दी तथा एक नया पाठ्यक्रम ढांचा प्रस्तुत किया, जिसके करण व्यापक विषमताएं आई।

संभावित साझेदार के रूप में वैयक्तिक कर्ता

गैर सरकारी कर्ता, समुदाय आधारित समूह, गैर सरकारी संगठन, आस्था (धर्म) आधारित संगठन तथा लाभकारी सत्ताएं बहुत सारे देशों में एक विस्तृत भूमिका निभा रही हैं। आस्था (धर्म) समूह यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लातीनी अमेरिका तथा अरब राष्ट्रों में कार्यरत हैं।

उपलब्ध आंकड़ों वाले 154 देशों में से लगभग आधे देशों में, निजी संस्थानों में नामांकन कुल का एक तिहाई से भी कम है। निजी क्षेत्र विशेष प्रचुरता के साथ उप सहारा अफ्रीका, अरब राष्ट्रों, कैरिबियन तथा पूर्वी एशिया देशों मे कार्यरत हैं जबकि ई सी सी ई के विकास में अधिकतर यूरोपीय देशों में सरकारी प्रावधान का अंगभूत बन चुका है। बहुत सारे संक्रमणशील देशों में निजी (क्षेत्र) प्रदाताओं ने वहां कदम बढ़ाए हैं जहाँ से सरकार पीछे हट गईं हैं। ताकि नवाचारी व्यवहार आगे बढ़ें और लाभ हीनों तक पहुँच भी स्थापित हो।

लाभ अर्जक करने वालों की भूमिका, विशेष रूप से विवादास्पद है। प्रस्तावक मानते हैं कि इससे प्रतियोगिता और अभिभावकों का चुनाव बढ़ता है। आलोचकों का तर्क है कि निजी प्रदाता प्राय: सरकारी प्रणाली से बाहर संचालन करते हैं और प्राय: उच्च फीस तथा प्रवेश अपेक्षाओं के बहाने गरीब बच्चों को बहिष्कृत रखते हैं। द्विपथ प्रणाली में काफी जोखिम हैं क्योंकि कम आय वाले अभिभावक कम लागत वाले, खराब गुणवत्ता के सरकारी विकल्पों को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। इससे बचने के लिए, सरकारों को जरूरत है कि वे और अधिक अनुकूल सक्रियता पूर्ण भूमिका निभाएं और नियामन, गुणवत्ता सुनिश्चितता, निगरानी तथा निष्पक्षता के प्रोत्साहन के लिए एक ढांचा तैयार करें।

गुणवत्ता सुधार

सरकारों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य मानक प्राप्त हों। इस प्रकार के विनियम, सरकारी या निजी, सभी प्रदाताओं के ऊपर लागू होने चाहिए। अधिकतर जो सरकारें ई सी सी ई कार्यक्रमों का विनियमन करती हैं, वे गुणवत्ता के ढांचागत संकेतकों के सरल मापकों- जैसे कक्षा का आकार, कर्मचारी- छात्र

अनुपात, सामग्री की उपलब्धता तथा कर्मचारी प्रशिक्षण आदि, का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही, यदि अधिक नहीं तो कम से कम यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि देखभालकर्ता व बच्चे का सबंध, परिवारों का सम्मिलन, सांस्कृतिक विविधता हेतु समादर तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आदि।

पांच लातीनी अमेरिकी देशों ने ई सी सी ई के लिए राष्ट्रीय गुणता मानक विकसित किया है एवं सात कैरीबियाई देशों ने एक सामान्य साधन से अधिगम पर्यावरण तथा देखभालकर्ता एवं बच्चे की परस्पर संबंध का मूल्यांकन कर कार्यक्रम गुणवत्ता का आंकलन किया है। कुछेक देशों ने प्रारंभिक अधिगम एवं विकास मानक अपनाया हुआ है– जो एक बच्चे को क्या मालूम हो और क्या करने योग्य हो, की राष्ट्रीय अपेक्षाओं का पता करता है। मानकों को निश्चित रूप से बहुत सावधानी के साथ स्थापित करना चाहिए तथा ध्यान से इस्तेमाल किया जाना चाहिए; क्योंकि यदि राष्ट्रीय स्तर का मानक सांस्कृतिक, भाषाई तथा अन्य प्रकार की विविधताओं को ध्यान में न रख सके; और उनका दुरुपयोग हो, वे बच्चे को निन्दित करते हों या बच्चे को 'असफल' अथवा स्कूल शुरू करने के लिए ''तैयार नही'' जैसे लांछन चस्पा कर सकते हैं।

नीतियों को सहारा देकर गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना

बच्चे अपने देखभालकर्ता एवं शिक्षक से कितना जुड़ते हैं, व्यापकतौर पर अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। अनेक औद्योगिकीकृत देश जन्म से स्कूल में प्रवेश हेतु ई सी सी ई प्रावधान की एकीकृत प्रणाली की दिशा में बढ़ रहे हैं जो कि कर्मचारियों की योग्यता एवं प्रशिक्षण को पुनर्गठित करने तथा ई सी सी ई के देखभाल घटकों और शिक्षा के बीच अंतराल को पाटने में संलग्न हैं। उदाहरण के लिए, सिंगापुर में अब सभी बाल सेवक एवं पूर्व स्कूली कर्मचारी एक समान प्रशिक्षण तथा प्रत्यायन से गुजरते हैं।

एक प्रमुख मुद्दा यह है कि भारी संख्या में प्रशिक्षित ई सी सी ई कर्मचारी कैसे भर्ती करें। इस क्षेत्र में अधिकाधिक उम्मीदवार खींचने के लिए कुछ देश उच्च शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु लचीला प्रवेश पथ तैयार कर रहे हैं। अनेक कैरीबियाई द्वीप सुयोग्यता आधारित आंकलन कर रहे हैं। अनेक देशों में आधुनिक तकनीक भी काम में लगाई जा रही है। उदाहरण के लिए दि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट वरचुअल यूनीवर्सिटी एक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रयास है ताकि अफ्रीका एवं मध्यपूर्व क्षेत्रों में इस क्षेत्र में विकास एवं नेतृत्व की जरूरतें पूरी करने में सहायता प्राप्त हो। उन छात्रों, जो प्रारंभिक बालपन कर्मी सेवा में है, को दुनिया भर के संकाय सदस्यों द्वारा पढ़वाया जाता है और प्रत्येक देश या क्षेत्र में परामर्शदाताओं के साथ काम करते हैं।

शैशवकालीन कार्यक्रम से प्राथमिक स्कूल में अंतरण को आसान बनाने हेतु अनेक देश दो स्तरों के बीच व्यावसायिक सातत्यता को सुनिश्चित करने हेतु मापकों को शुरू कर रहे हैं। वे संयुक्त प्रशिक्षण (फ्रांस, आयरलैंड, जमैका तथा यूनाइटेड किंगडम) को शामिल कर सक्रिय अधिगम उपागम पर तथा ई सी सी ई और प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के बीच समान व्यावसायिक स्तर पर जोर देते हैं।

पर्याप्त वित्तीय भरोसा

ई सी सी ई के विस्तारण एवं सुधार के लिए अतिरिक्त सरकारी एवं निजी फंडों को उगाहने की जरूरत होगी और उन्हें अधिक सक्षम वित्तीय प्रक्रम के माध्यम से आवंटित करना होगा। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्विष्ट रहते ई सी सी ई के विस्तार एवं सुधार की देश विशिष्ट अनुमानित लागत; एक वैश्विक आंकलन की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रासंगिक नीति है। प्राप्त आंकडों के साथ 79 देशों में से 65 देशों ने 2004 में ई सी सी ई के लिए शिक्षा खर्च में से 10% से कम धन आवंटित किया था। 65 देशों में से आधों ने 5% से भी कम आवंटित किया था, जिन 14 देशों ने 10% से अधिक आंवटित किया था, वे अधिकतर यूरोप से थे।

सकल घरेलू उत्पाद (जीएनपी) में हिस्से के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक सरकारी व्यय केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप में (0.5%) है जबकि तुलना में उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप 0.4% के साथ तथा लातीनी अमरीका 0.2% के साथ हैं। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल योग में से पूर्व प्राथमिक कार्यक्रमों पर लगभग 26% खर्च निर्धारित है। यद्यपि फ्रांस और जर्मनी में यह भागीदारी लगभग 60% तक बढ़ी हुई है। देशों के बीच व्यापक भिन्नता के साथ लातीनी अमेरिका एवं कैरीबियन क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक पर खर्च 14% है जोकि प्राथमिक के बराबर है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, सरकारी शिक्षा खर्च के कुल योग से प्राप्त थोड़ी सी भागीदारी प्रति बच्चे निम्न खर्च की अपेक्षा निम्न नामांकन अनुपात को प्रतिबिंबित करता है। आंकड़ा प्राप्त सभी देशों में प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चे का औसत व्यय 85% है। वास्तव में, जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पूरी लागत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जैसा कि अभी केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप के पूर्व सोशलिस्ट देशों में प्रवृत्ति है, वहां अभी भी प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा पूर्व प्राथमिक में 25% अधिक लागत है, इसका मुख्य कारण छात्र शिक्षक अनुपात निम्नतर है। उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप तथा लातीनी अमेरिका एवं कैरीबियन देशों में प्राथमिक की अपेक्षा पूर्व प्राथमिक पर प्रति बच्चे का औसत खर्च लगभग 70% के करीब है (यद्यपि फ्रांस, जर्मनी एवं ग्रीस में यह लगभग 90% के करीब पहुँच रहा है)।

ई सी सी ई के विस्तारण एवं सुधार के लिए अतिरिक्त सरकारी एवं निजी फंडों को उगाहने की जरूरत होगी

कुल मिलाकर, सरकारी एवं निजी, दोनों की ई सी सी ई की फंडिंग के साथ सरकारी फंड प्राय: सरकार के स्तर से एक स्तर अधिक प्रदान किया जाता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की फंडिंग की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भिन्नता वाली होती है। ओ ई सी डी देशों के साथ, उदाहरण के लिए, अभिभावकों की हिस्सेदारी ऊंची रहती है जैसाकि यूनाइटेड स्टेट्स में कुल का 60% अभिभावक हिस्सा है लेकिन स्वीडन एवं फ्रांस में 20% के करीब है। विकासशील देशों के बीच यह भिन्नता बहुत व्यापक है। इंडोनेशिया में ई सी सी ई को मुख्यतौर पर परिवार की जिम्मेदारी माना जाता है और कुल खर्च में सरकारी फंडिंग का हिस्सा 5% से अधिक नहीं होता है। प्राय: यह निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित शहरी देखभाल केन्द्रों की आर्थिक सहायता के रूप में मिलता है। क्यूबा में सरकार 100% वहन करती है।

ई सी सी ई कार्यक्रमों को सीधे फंडिंग करने का एक विकल्प सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध कराना है जो अभिभावकों को विभिन्न प्रकार के सेवादाताओं में से किसी एक से सेवाएं खरीदने के योग्य बनाते हैं। जैसा

कि चिली, यूनाइटेड स्टेट्स तथा ताईवान (चीन) द्वारा एक उपागम ने जगह पाई है। फ्रांस में वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिवारों को बच्चों की देखभाल लागत को क्षतिपूर्ति करने में मदद करती है।

सुकुमार या सुभेद्य एवं प्रतिकूल परिस्थितियुक्त बच्चों को लक्षित करना

ई सी सी ई कार्यक्रम में सुकुमार या सुभेद्य एवं प्रतिकूल परिस्थिति वाले बच्चों के लिए व्यापक संभावना है। लेकिन असंदिग्धरूप से इन बच्चों की पहुंच संभवत: न्यूनतम होती है। जब देशों के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं तब वह इसे कैसे आवंटित करें कि सर्वाधिक आवश्यकता वालों तक पहुंचें? यहाँ पर दो प्रकार के लक्ष्य भेद प्रयुक्त होते हैं- भौगोलिक और आय द्वारा। इसके अतिरिक्त अंतर्विष्ट नीतियां प्राय: एक विशेष समूह को लक्ष्य करती हैं जैसे कि विकलांग, भाषाई या मानवजातीय अल्पसंख्यक।

दानदाता जो फंड कुल प्राथमिक शिक्षा के लिए देते हैं, उसमें से पूर्व प्राथमिक के लिए केवल 10 प्रतिशत आवंटित करते हैं,

भौगोलिक रूप से लक्षित करना भारत की समेकित बाल विकास परियोजना का उपागम है। जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झोपड़-पट्टी क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, 23 मिलियन (2.3 करोड़) से अधिक बच्चों तक पहुंच रही है। यह पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्यजांच तथा संदर्भ सेवाओं तथा शिक्षा का एकीकृत पैकेज है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और स्तनपान कराती माताओं को तथा गर्भवती स्त्रियों को सेवाएं दे रहा है। इस कार्यक्रम ने उनकी उत्तरजीविता, वृद्धि एवं छोटे बच्चों के विकास में सकारात्मक प्रभाव डाला है। वीएतनाम ने भी दूरदराज तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लक्षित किया है। केन्या ने पशुचारण समुदाय के बच्चों को लक्ष्य बनाया है (बाक्स 6.1)। आय लक्ष्य भेद के अंतर्गत और अधिक सामान्य विकल्प हैं, जिसमें वांछनीयता को सीमित करना तथा गरीबों के लिए नामांकन हेतु आर्थिक सहायता या वाउचर्स के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

बाक्स 6.1 : केन्या के पशुचारण समुदाय में बच्चों की देखभाल

केन्या की राष्ट्रीय नीति सार्वभौम मुफ्त प्राथमिक शिक्षा ने उत्तर के पशुचारण समुदायों पर यह जोर डाला है कि वे अधिकाधिक एक स्थान पर बसने वाले बने। स्थानीय भाषा में 'लोइपी'- 'शेड' (कुंज या निवास) पास के वह क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों की दादियां देखभाल करती हैं और वे परंपराओं एवं कौशलों को मौखिक रूप से पारित करती हैं। वर्ष 1997 से अनेक पशुचारण लोगों ने 2 से 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय समर्थन के साथ संसाधनों को जुटाया है। अब 5,200 से अधिक बच्चों तक पहुंच रहे हैं जहाँ लोइपी कार्यक्रम ने परम्परागत उपागम से बच्चों की देखभाल उपागम में जड़ें जमाई हैं जहां पर एक ओर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक, आय उपार्जन की पहुंच प्रस्तावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर हानिकारक प्रथाओं जैसे कि स्त्री लिंग अंगच्छेद के बारे में जानकारी देते हैं। यहां समुदाय द्वारा अहाते एवं खेल सामग्रियां स्वत: तैयार की जाती हैं। परिणामस्वरूप टीकाकरण कार्यक्रम की पहुंच में सुधार व बेहतर पोषण हुआ है और एक पूर्व प्राथमिक शिक्षक के अनुसार बच्चों के प्राथमिक स्कूल में अंतरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

ई सी सी ई के साथ-साथ, अन्य सरकारी सेवाओं को साथ लेने से, यहां पर एक जोखिम यह है कि लक्षित उपागम पर्याप्त समर्थन न जुटा सकें। यहां लक्ष्य भेद बच्चों को विभाजित या विलग कर सकता है और कार्यक्रम में प्रतिकूल परिस्थितियों वाले बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करने की ओर बढ़ सकता है। नियमनिष्ठ लक्ष्य भेद भी बहुत कठिन है। अनेक देशों ने सरकारी फंड से पूर्व प्राथमिक कार्यक्रमों को फंड प्रदान किया है जो सभी बच्चों को लक्ष्य बनाता है लेकिन सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थिति वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन लक्ष्य करता है। परन्तु यह उपागम बहुत सारे विकासशील देशों में कम उपयोज्य है जहाँ अधिकतर बच्चे ई सी सी ई कार्यक्रम से बहिष्कृत हैं। एक चारणिक या फेस उपागम शायद अधिक अनुकूल है; इसमें देश एक राष्ट्रीय ई सी सी ई नीति सभी बच्चों एवं स्थापनाओं के लिए विकसित करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थिति वाले बच्चों पर सरकारी संसाधनों के केंद्रित करने से शुरूआत करते हैं।

शैशवकालीन – सहायता नीतियां

विकास सहायता के लिए ई सी सी ई एक प्राथमिकता नहीं है। अरसठ दानदाताओं के एक सर्वेक्षण में, प्रतिक्रिया देने वाली सत्रह संस्थाओं में केवल चार ने ई सी सी ई को अपनी सम्पूर्ण सहायता रणनीति में एक विशिष्ट घटक के रूप में माना है। अन्य शेष ने प्रारंभिक बालपन को अपने स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्र की रणनीति के साथ सम्मिलित किया हुआ है। दानदाता केंद्र आधारित ई सी सी ई कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं जो तीन वर्ष से प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को शामिल करते हैं और लघु विस्तार के बाद अभिभावकों एवं देखभालकर्ताओं को समर्थन देते हैं। यूनीसेफ और यूएसएड केवल औपचारिक ई सी सी ई कार्यक्रमों को समर्थन देने वाले अकेले उत्तरदाता हैं जबकि शायद सभी दानदाताओं के प्रतिनिधियों के लिए यह जरूरी नहीं लगता है फिर चाहे ये फंडिंग प्राथमिकताएं उस देश की जरूरतों के अनुकूल नहीं बैठ सकें। कम औपचारिक और कम महंगी व्यवस्थाएं, केंद्रों की अपेक्षा बच्चों तक अधिक पहुंच कर मदद कर सकती है।

शैशवकालीन को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहायता डाटाबेस में प्राथमिक शिक्षा से विलय करना कठिन है। इसके अतिरिक्त ई सी सी ई के कुछ घटकों को अन्य क्षेत्रों में भी सम्मिलित कर लिया गया है; जैसे कि स्वास्थ्य। कम आय वाले देशों में यह वृत्ति देखी गई है कि उन्हें मध्य आय वाले देशों की अपेक्षा कम फंडिंग प्राप्त होती है। आस्ट्रेलिया, ग्रीस और स्पेन के अलावा दानदाता जो फंड कुल प्राथमिक शिक्षा के लिए देते हैं, उसमें से पूर्व प्राथमिक के लिए केवल 10 प्रतिशत आवंटित करते हैं, और बहुतायत में ई सी सी ई के लिए केवल 2 प्रतिशत आवंटित करते हैं, अधिकतर दानदाताओं की कुल शिक्षा सहायता में ई सी सी ई की हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से भी कम जारी होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सुदृढ़ राजनैतिक समर्थन, विकासशील देशों की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और ई सी सी ई के लाभों पर हुए अनुसंधानों को प्रसारित करने से दानदाता संस्थाओं को ई सी सी ई के मुद्दे के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन रणनीति के साथ ई सी सी ई नीतियों की सहबद्धता में भी सुधार होगा। ■

निष्कर्ष

कुल मिलाकर सर्व शिक्षा (ई एफ ए) की तस्वीर समिश्रित है। यहां पर डाकर के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विशेषरूप से लड़कियों सहित प्राथमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ी है। हालांकि सर्व शिक्षा का बाकी एजेंडा पिछड़ रहा है, और यहां तक कि वर्तमान प्रवृत्ति से यू पी ई लक्ष्य संभवत: समय पर पूरा नहीं होने वाला। विशेषरूप से, यहां पर अभी भी वयस्क साक्षरता के सुधार हेतु न्यूनतम ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के उन कार्यक्रमों में भी, जो प्राथमिक स्कूल में प्रवेश से पहले के हैं।

प्राधिकृत नौ क्षेत्र तत्काल नीतिगत ध्यान चाहते है

1. ***डाकर के विस्तृत उपागम हेतु वापसी*** – यूपीई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को अधिग्रहीत कर लिया है लेकिन सरकारें वयस्क साक्षरता के लिए राजकीय जिम्मदारी नहीं ले रही हैं। यह विचलित करने वाला है कि पांच वयस्कों में एक बिना प्राथमिक शिक्षा कौशल एवं ई सी सी ई के रह रहा है। इस प्रकार से यूपीई की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्कूल को पूरा करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में जूनियरमाध्यमिक स्थानों पर पर्याप्त विस्तार करने की जरूरत होगी।

2. ***आग्रह के साथ कार्यवाही*** – वर्ष 2015 के आने में केवल नौ वर्ष बचे हैं जब कि सभी बच्चे को उपयुक्त आयु वर्ग के अनुकूल प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत होने के लिए तीन वर्ष बचे हैं। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति वाले तथा सुकुमार बच्चों का पंजीयन यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार तथा उन बच्चों के लिए शिक्षा सुअवसरों को तैयार करना जो संघषरत देशों के साथ रह रहे हैं और लड़ाई के उपरांत की स्थिति वालों को विशेष रूप से प्राथमिकता देती है।

3. ***साम्यता तथा अन्तर्भाव पर जोर डालना*** – बहुत सारे देशों में, ई सी सी ई कार्यक्रमों तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए फीस अभी भी गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं और बहुत सारे प्राथमिक शिक्षा की अंतिम कक्षा तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। शिक्षा नीतियों को जरूरत है कि विशिष्ट क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों के लिए विशेष उपागमों को विकसित करें। एक सम्मिलित नीति सांस्कृतिक संवेदना तथा भाषाई विविधता तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित, सभी शिक्षा स्थितियों पर लिंग समानता तथा स्कूल और कार्यक्रमों को उनके करीब ले जाने का प्रयास, जहां लोग रहते हैं, एक उच्च चिंता का विषय है।

4. ***राजकीय खर्च बढ़ाना तथा इसकी बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करना*** – बहुत सारी सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर पर्याप्त राजकीय फंड खर्च नहीं करती हैं, विशेष रूप से ई सी सी ई तथा साक्षरता पर। शिक्षा पर राजकीय खर्च उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) के एक हिस्से के रूप में, 2006 की रिपोर्ट के अनुसार, 41 देशों में घटी है। वित्तीय ससांधनों को अपरिहार्य आवश्यकताओं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों तथा सबके लिए विशुद्ध रूप से सर्व शिक्षा को यथार्थ बनाने के लिए उपायों के समावेश पर केंद्रित करना चाहिए।

5. ***जहां सर्वाधिक आवश्यकता है वहां के लिए सहायता बढ़ाना एवं आवंटित करना*** – कम आय वाले देशों में प्राथमिक शिक्षा पर सहायता कम से कम दोगुनी की आवश्यकता है तथा व्यापक रूप से ई सी सी ई तथा साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तीव्रगामी प्रयासों को और अधिक फंड प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि अधिक पूर्वानुमानित प्रवाह को अधिक समय तक पहुंचाते रहें और अपने प्राथमिक शिक्षा के ध्यान को व्यापक करते हुए संपूर्ण सर्व शिक्षा को सम्मिलित करें।

6. ***घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों में ई सी सी ई को आगे बढ़ाना*** – उच्च स्तरीय राजनैतिक अनुमोदन ई सी सी ई को बच्चों के वर्तमान कल्याण एवं भावी विकास हेतु एक अनिवार्यता के साथ एक प्रमुखता के रूप में मान्यता देता है। सभी देशों को आवश्यकता है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु एक स्पष्ट प्राधिकृत मंत्रालय या एजेंसी गठित करें जो ई सी सी ई पर राष्ट्रीय नीति सरंचना विकसित करें तथा इससे संबंधित सभी देशों के साथ मिलकर काम करें। इस प्रकार की नीति को

वर्ष 2015 के आने में केवल नौ वर्ष बचे हैं जब तीन वर्ष से ऊपर के सभी बच्चे उपयुक्त आयु वर्ग के अनुकूल प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत होने हैं।

सर्व शिक्षा को और अधिक व्यापक उपागम तथा अधिक टिकाऊ प्रयासों की आवश्यकता है

लक्ष्य तय करने व फंडिंग स्तर निर्धारित करने चाहिए तथा वह नियमन एवं गुणवत्ता निगरानी प्रदान करें। कायक्रमों के साथ पोषण, स्वास्थ्य सेवा, देखभाल तथा शिक्षा को समिश्रित करने से वे और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, अपेक्षाकृत उनके जो केवल एक पहलू को देखते हैं। निजी क्षेत्र के साथ एक प्रभावी साझेदारी–जो कि अनेक देशों में प्रमुखकर्ता है–को विकसित किया जाना चाहिए और पहुंच तथा गुणवत्ता की विषमता के प्रति सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए।

7. ***ई सी सी ई के लिए राजकीय वित्त बढ़ाना तथा उसे लक्षित करना*** – यद्यपि राष्ट्रीय नीति में सभी बच्चों को समेटे होना चाहिए और कुछ विशेष संदर्भों में सरकारी संसाधनों को शुरूआत में सुकुमार एवं विपरीत परिस्थिति वाले बच्चों पर बेहतर लक्षित किया जा सकता है। यह अति आवश्यक है कि ई सी सी ई को राजकीय संसाधन आवंटन के प्रमुख दस्तावेजों (राष्ट्रीय बजट, क्षेत्रीय योजनाओं) और पी आर एस पीज में सम्मिलित किया जाए। अन्य दानदाताओं को भी चाहिए कि वे शैशवकालीन मुद्दों को अग्रिम प्राथमिकता देने हेतु यूनीसेफ का अनुपालन करें।

8. ***ई सी सी ई कार्यबल का उन्नयन–विशेषरूप से योग्यताओं, प्रशिक्षण एवं कार्यस्थितियों के संबंध में*** – ई सी सी ई कार्यक्रमों में गुणवत्ता के निर्धारण में देखभालकर्ताओं एवं शिक्षकों के साथ बच्चों की परस्पर क्रिया अत्यंत विशिष्ट है। प्राय: यह प्रवृत्ति दिखती है कि ई सी सी ई कर्मियों को प्रशिक्षण एवं वेतन दोनों ही संदर्भों में अवमूल्यित किया जाता है। सभी प्रकार के ई सी सी ई कर्मचारियों हेतु गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली होने के लिए कर्मचारियों को औचित्यपूर्ण संरचनात्मक परिस्थितियों (जैसे कि उचित बच्चों/कर्मचारी अनुपात तथा समूह का आकर एवं पर्याप्त सामग्री) की आवश्यकता होती है।

9. ***ई सी सी ई की निगरानी को सुधारना*** – देशों को ई सी सी ई पर विस्तृत जानकारी संग्रहीत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को लाना चाहिए। विशेष रूप से तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु कार्यक्रमों के संबंध में, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की अपेक्षा ई सी सी ई कर्मचारी की गुणवत्ता मापन तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय व्यय के लिए विशेषज्ञों को लाया जाना चाहिए।

सर्व शिक्षा (ई एफ ए) की दिशा में डाकर के पश्चात् की महत्वपूर्ण प्रगति एक पैमाना उपलब्ध कराती है कि जब सभी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक संयुक्त कार्यवाही के बल में सम्मिलित हो जाते हैं तो कितना काम निष्पादित किया जा सकता है। अभी भी सर्व शिक्षा को और अधिक व्यापक उपागम तथा अधिक टिकाऊ प्रयासों की आवश्यकता है। हमें निश्चित रूप से रूचि और उत्साह की पताका झुकने नहीं देनी चाहिए। सर्व शिक्षा (ई एफ ए) का मतलब है सब के लिए शिक्षा, न कि केवल कुछ लोगों के लिए शिक्षा। इसका तात्पर्य सभी छह लक्ष्यों से है, न कि केवल वे जो प्राथमिक स्कूल से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि विशेष रूप से शैशवकाल पर ध्यान देना, जब प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के प्रभावी चरण न्यूनतम लागत पर उठाए जा सकते हैं, जब सुदृढ़ नींव आसानी से डाली जा सकती हो। अंत में; इसका तात्पर्य है कि यह प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। आज नई युवा पीढ़ी के असफल होने पर केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन मात्र नहीं है; बल्कि यह कल की गहन गरीबी एवं विषमताओं के बीज को दर्शाते हैं। चुनौतियां और उसके एजेंडे भी बिलकुल स्पष्ट हैं। अब समय कार्यवाही करने का है।

बांग्लादेश के साथ – किरा जिले के एक गांव के प्राथमिक स्कूल के बाहर सबकी आंखें वर्णमाला पर

© REUTERS

सर्व शिक्षा (ईएफए) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट पश्नावली

ई एफ ए जी एम आर
सबके लिए शिक्षा विश्व वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

कृपया उत्तर प्रतिपेषित करें

सबके लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक स्वतंत्र रिपोर्ट है। कृपया आप कुछ मिनट का समय निकाल कर हमारे प्रश्नों का उत्तर दें तथा अपने बारे में परिचय दें। हम आपके विचारों एवं सुझावों का स्वागत करते हैं।

यह प्रश्नावली डाक या फैक्स द्वारा प्रेषित करें (पता नीचे देखें); या फिर आप इसे जी एम आर की बेवसाइट – पर इलैक्ट्रोनिकली भरकर भेज सकते हैं। www.efareport.unesco.org

वैयक्तिक/व्यावसायिक सूचना

नाम

पद

पता

शहर देश

ई–मेल

आपका प्रमुख व्यावसायिक कार्य/क्षेत्र क्या है?

सर्वशिक्षा (EFA) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

आपको जी एम आर के बारे में कैसे पता चला?

क्या आपने पहले के संस्करण देखे है?

क्या आप पूरी रिपोर्ट के मुद्रित संस्करण पर ध्यान देते हैं? संक्षिप्त रिपोर्ट?

क्या आप पूरी रिपोर्ट के वेब संस्करण पर ध्यान देते हैं? संक्षिप्त रिपोर्ट?

क्या आप पूर्ण रिपोर्ट की सीडी पर ध्यान देते हैं? संक्षिप्त रिपोर्ट?

कृपया विवरण दें कि रिपोर्ट का उपयोग कैसे करते हैं संक्षिप्त रिपोर्ट?

आपकी राय

रिपोर्ट को और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है?

वर्तमान में सांख्यिकीय सारणियां लगभग आधी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं,
यदि इन्हें अलग से प्रस्तुत किया जाए तो क्या आप रिपोर्ट के बारे में अपनी समालोचना (विचार) बदलेगें?

टिप्पणी या सुझाव

जी एम आर क्षेत्रीय दृष्टिकोण

प्रत्येक वर्ष की जी एम आर से उत्पादित क्षेत्रीय दृष्टिकोण से क्या आप चिरपरिचित है?

क्या आपने एक जी एम आर क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है ?

यदि हां, तो क्या यह मुद्रित संस्करण था? वेब संस्करण? दोनों?

कौन सा/से क्षेत्र?

वर्णन करें कि आपने क्षेत्रीय दृष्टिकोण को कैसे अपयोग किया?

टिप्पणी या सुझाव

जी एम आर वेबसाइट

क्या आपने कभी जी एम आर वेबसाइट विजिट किया है?

आप उसमें क्या देख रहे थे और क्या आपको वह मिला था?

क्या आपने कभी वेबसाइट के पृष्ठभूमि प्रपत्रों से कुछ परामर्श प्राप्त की?

क्या आपने अपनी सारणी बनाने हेतु सांख्यिकीय उपकरण उपयोग किया है?

वेबसाइट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

जी एम आर समाचार एलर्ट्स

क्या आप कभी कभार ई-मेल द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर) न्यूज एलर्ट्स प्राप्त करना चाहेंगे?

यदि हां तो कृपया यहां पर अपना ई मेल पता दें

(आप किसी भी समय ग्राहक सूची से हट सकते हैं)

कोई अन्य टिप्पणी या सुझाव

आपका धन्यवाद

दि ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट टीम
पेरिस, फ्रांस

फैक्स व डाक का पता

ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट टीम
अटेन.-जी एम आर फीड बैक
यूनेस्को,
7, प्लेस डि फोनटेनोय,
75352 पेरिस 07, फ्रांस

फेक्स : +33 (0) 1 45 68 56 41
बेवसाइट : www.efareport.unesco.org
ई मेल efareport@unesco.org

ई एफ ए जी एम आर
सबके लिए शिक्षा विश्व वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

सारांश

ई एफ ए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2007

शैशवकाल असाधारण रूपांतरण तथा अति सुकुमारता का एक समय होता है। वे कार्यक्रम जो छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व के वर्षों में समर्थन प्रदान करते है, वे पर्याप्त अधिगम एवं विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिकूल परिस्थिति वालों और बहिष्कृतों को क्षति पूरित भी करते हैं तथा गरीबी से बाहर निकलने की एक राह दिखाते हैं।

यह संक्षिप्त (सारांश) रिपोर्ट सबसे पहले सबके लिए सर्व शिक्षा के लक्ष्य पर संकेंद्रित है, जो देशों से शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा–एक ऐसे समग्रतात्मक पैकेज, जिसमें शिक्षा के अतिरिक्त देखभाल, स्वास्थ्य एवं पोषण समेटा गया हो– के सुधार एवं विस्तार का आह्वान करती है। इससे विपरीत परिस्थिति वाले बच्चे सर्वाधिक लाभ प्राप्त करें। अभी तक बहुत थोड़े से विकासशील देशों, और बहुत थोड़ी सी दानदाता संस्थाओं ने शैशवकाल को एक प्राथमिकता बनाया है।

अन्य क्षेत्रों में सर्वशिक्षा की दिशा में विशेष रूप से सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अधिक लड़कियां स्कूल में जा रही हैं तथा शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ रही है। हालांकि, अभी भी लक्ष्य तिथि 2015 को पाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यदि, केवल कुछ सख्त कार्यवाही की जाए तो बहिष्करण से पार पाया जा सकता है तथा हर एक हेतु शैशवकाल एवं पूरे जीवन भर के लिए व्यापक अधिगम के सुअवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

ई एफ ए जी एम आर
सबके लिए शिक्षा विश्व वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

आवरण चित्र (कवर फोटो)
नेपाल, काठमांडू में खेलते हुए बच्चे
कॉपी राइट © ओलीवर कुलमान/टेनडांस फ्लूई

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture